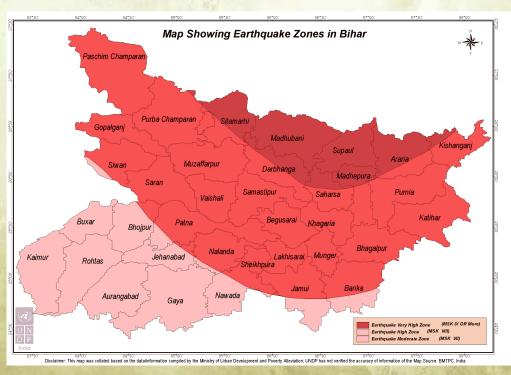






बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु

हस्त पुरितका-।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोंड, पटना-800001, फोन: +91 (612) 2522032, फैक्स: +91 (612) 2532311

visit us: www.bsdma.org; e-mail: info@bsdma.org

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका

(A Handbook for Professional Training of the officers of Bihar Administrative Service on Disaster Risk Reduction and Management)

प्रस्तावना



बिहार एक बहु—आपदा प्रवण राज्य है। यह राज्य एक ओर चक्रीय रुप से बाढ़ का प्रकोप झेलता है तो दूसरी ओर विगत कई वर्षों से सुखाड़ आपदा ने इसके बड़े भू—भाग को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त भूकंप, ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान, नौका दुर्घटना, वज्रपात, निदयों/तालाबों में डूबने की घटनाएँ, अग्निकांड, असमय भारी वर्षा आदि आपदाओं से समय—समय पर प्रभावित होता रहा है।

लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। आपदा प्रबंधन की अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं वरन् रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारियाँ, न्यूनीकरण, रिस्पांस एवं पुर्नस्थापन/पुर्ननिर्माण की गतिविधियाँ भी शामिल हो गयी है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व में उल्लेखित ''अवधारणा परिवर्तन'' (Paradigm Shift) के पश्चात् यह समीचीन हो गया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप आदि का पूर्ण ज्ञान हो। साथ ही, उनका आपदा रिस्पांस के लिये निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF) के कार्यों की जानकारी भी हो। विशेष कर विभिन्न आपदाओं के लिए गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा मार्गदर्शिकाओं का अध्ययन तथा जिला स्तर पर इनके इस्तेमाल के संबंध में उनका अवगत होना भी अत्यावश्यक हो गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ के सहयोग से दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों तथा विभिन्न जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता का आकलन (Training Need Assessment) किया गया। तत्पश्चात इस आकलन के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का मॉड्यूल तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर इस पुस्तिका में संकलित किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि बिहार प्रशासिनक सेवा के सभी स्तरों यथा—अनुमंडल, जिला एवं राज्य—के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन में अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजिनत आयामों यथा—रोकथाम, शामन, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पांस, पुर्नस्थापन एवं पुर्निर्निर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु—आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम, नीतियों, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मानव संचालन प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता—वर्द्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रिस्पांस में गित आयेगी एवं किसी प्रकार के दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

मुझे आशा ही नहीं वरन्, पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तिका का सदुपयोग कर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण आपदाओं का समुचित प्रबंधन कर राज्य के आपदा पीड़ितों की कठिनाईयों को दूर करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेगें।

भवदीय

(व्यास जी)

उपाध्यक्ष

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्रा<mark>धिकरण</mark>

विषय-सूची

1.	बिहार की बहु आपदा प्रवणता एवं अधिसूचित आपदाएँ	1-19
2.	आपदा प्रबंधन की बदलती भूमिका एवं आपदा प्रबंधन की संरचना	20-40
	(राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक)	
3.	आपदा प्रबंधन अधिनियम	41-60
4.	NDMA/SDMA/DDMA/NDRF/SDRF की संरचना , कर्तव्य एवं दायित्व	61-76
5.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (२०१५–३०) की मुख्य बातें	77-96
6.	जिला आपदा प्रबंधन योजना	97-117
7.	मानक संचालन प्रक्रिया	
	(क) मानक संचालन प्रक्रिया – बाढ़	118-139
	(ख) मानक संचालन प्रक्रिया – अग्नि	140-153
	(ग) मानक संचालन प्रक्रिया – पेयजल	154-164
	(घ) मानक संचालन प्रक्रिया – सुखाड़	165-178
	(ङ) मानक संचालन प्रक्रिया – अस्पतालों में अग्नि से सुरक्षा प्रबंधन	179-186
8.	साहाय्य मानदर, वित्तीय प्रबंधन एवं विभागीय परिपत्र	187-219
9.	आपदा प्रबंधन संबंधी प्रपत्र एवं प्रतिवेदनों का प्रेषण	220-232







fcgkj dh cgqvkink i zo. krk, oavf/kl fipr vkink, W

Mo xxu

vu**ęM**yk, ykd f'kdk, r fuokj.k i nkf/kdkjh egukj ¹/₀Skkyh/₂

fo"k, oLrq, oai Łrfrdj.k; kt uk

- 1. आपदा प्रबंधन और आपदा प्रवणता के संबंध में तकनीकी परिचय
- 2. Hazard, vulnerability, risk, capacity building की सामान्य जानकारी
- 3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)
- 4. बिहार की प्रमुख आपदा की घटनाओं की जानकारी (आंकड़ों के साथ)
- 5. राज्य की अधिसूचित अपदाएँ

1. आपदा प्रबंधन और आपदा प्रवणता के संबंध में तकनीकी

vki nk D; k gS

Disaster (As per DM Act, 2005)

Disaster means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence affecting any area from natural and manmade causes, or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, or degradation of environment and is of such a nature and magnitude as to be beyond the capacity of the community of the affected areas

1. आपदा प्रबंधन और आपदा प्रवणता के संबंध में तकनीकीContd

vkink i záku D; k gS

Disaster means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence affecting any area from natural and manmade causes, or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, or degradation of environment and is of such a nature and magnitude as to be beyond the capacity of the community of the



1. आपदा प्रबंधन और आपदा प्रवणता के संबंध में तकनीकीContd

vkink i záku D; k gS

As per DM Act, 2005 [U/S2(e)]

"Disaster management" means a continuous and integrated process of planning, organization, coordinating and implementing measure which are necessary of expedient for-

- (i) Prevention of danger threat of any disaster;
- (ii) Mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences;
- (iii)Capacity-building;
- (iv)Preparedness to deal with any disaster;
- (v) Prompt response to any threatening disaster situation or disaster;
- (vi)Assessing the severity or magnitude of effects of any disaster;
- (vii)Evacuation, rescue and relief;
- (viii)Rehabilitation and reconstruction;

1. आपदा प्रबंधन और आपदा प्रवणता के संबंध में तकनीकीContd

vkink izo. krk (Disaster proneness) D; kgS

Disaster proneness is the likelihood of occurrence of a disaster which depends on the demography, geographical location, socio-economic condition, level of awareness and other related factor such as-logistics, preparedness, technolegal regime & its implementation etc.

Disaster proneness necessitates proper disaster management

2. Hazard, vulnerability, risk, capacity building की सामान्य जानकारी

Hazard:- A potential threat.

A dangerous condition or events that threaten or have the potential for causing injury to life or damage to property or the environment. Hazards are basically grouped in two broad headings:

- Natural Hazards (hazards with meteorological, geological or biological origin)
- Unnatural Hazards (hazards with human-caused or technological origin)
 - Natural phenomena are extreme *climatological*, *hydrological*, or *geological*, processes. A massive earthquake in an unpopulated area, is a natural phenomenon, *not a hazard*. But when these natural phenomena interact with the man made habitat, they may cause wide spread damage. Then, they become hazard.

2. Hazard, vulnerability, risk, capacity building की सामान्य जानकारीcontd

Vulnerability:- susceptibility

Vulnerability is defined as "The extent to which a community, structure, service, or geographic area is likely to be damaged or disrupted by the impact of particular hazard, on account of their nature, construction and proximity to hazardous terrain or a disaster prone area."

Physical vulnerability – weak buildings, bridges, service lines, lifeline structures, production units etc.

Social & Economic vulnerability

Human losses in disasters in developing countries are seen to be higher when compared to developed countries.

2. Hazard, vulnerability, risk, capacity building की सामान्य जानकारीcontd

Risk:-

Risk is a measure of the expected losses (deaths, injuries, property, economic activity etc) due to a *hazard* of a particular *magnitude or Intensity* occurring in a given area over a specific time period.

Exposure the value and importance of the various types of structures and lifeline systems (such as water-supply, communication network, transportation network etc in the community serving the population)

2. Hazard, vulnerability, risk, capacity building की सामान्य जानकारीcontd

Capacity building:-

As per DM Act [u/s 2(b)]

Capacity building includes

- (i) Identification of exiting resources and resources to be acquired or created
- (ii) Acquiring or creating resources identified under sub-clause(i);
- (iii) Organisation and training of personnel and coordination of such training for effective management of disasters;

2. Hazard, vulnerability, risk, capacity building की सामान्य जानकारीcontd

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)

Bihar is one of the most disaster prone state of the country. Floods, droughts, cyclonic storms, hail storms, earthquakes, heat/cold waves, Road accidents, boat capsizing, drowning, lightening, river erosions, fire incidence etc. are various forms of disasters prevalent in the State

- →17 % of the country's Flood area in Bihar
- →Frequent change of river course & land erosion
- **→**Frequent Droughts
- **→**Earthquake Zone-IV & V (Some districts of North Bihar as vulnerable as Bhuj and kashmir)
- →High wind velocity in most parts- cyclonic storms
- **→Quite often hailstorms**
- →Recurrent village fires in summer months
- **→**Cold wave/Heat wave
- **→**Lightening
- **→**Boat capsizing & Drowning
- **→**Road accidents

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

Disaster proneness of Bihar springs

from:-

- Demography of Bihar
- Geographical factors
- Social Economic conditions
- Infrastructure related issue
 - Transportation

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

AS PER 2011 CENSUS

Demography Of Bihar

Populaton	10,38,04,637	
Male	5,41,85,347	
Female	4,96,19,290	
Population (0-6 Years Group)		
In Absolute Number	1,85,82,229	
Male	96,15,280	
Female	89,66,949	
Percentage of Total Population	17.90%	
Male	17.90%	
Female	18.07%	

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd As per 2011 census

Literacy		
In Absolute Numbers	5,43,90,254	
Male	3,27,11,975	
Female	2,16,78,279	
Percentage of Total Population	63.82%	
Male	73.39%	
Female	53.33%	

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

AS PER 2011 CENSUS

Decadal Population Growth (2001-2011)		
Absolute	2,08,06,128	
As Percentage	25.07%	
Highest Decadal Growth at	Madhepura district (30.65%)	
Lowest Decadal Growth at	Gopalganj district (18.83%)	
Civil Police Stations	813	
Railway Police Stations	40	
Density of Population	1,102 per sq kms	
Highest Density	Sheohar: 1882 per sq kms	
Lowest Density	Kaimur: 488 per sq kms	

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय

(मानचित्र के साथ)contd

Geographical factors

Location:-

Lies Between 24 degree- 20'-10" to 27 degree-31'-15" North Latitude and between 82 degree-19'-50" to 88 degree-17'-40" East Longitude

Completely land locked

North- Nepal/Himalaya

South-Jharkhand

East-West Bengal

West-Utter Pradesh

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

❖ Land

Total Area-94,163 sq kms

Rural Area-92,251.49 sq kms (97.97%)

Urban Area-1,911.51 sq kms (2.03%)

- Three agro-climatics zone
- I. Zone One- Twelve Districts- W. Champaran, E. Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran, Sheohar, Sitamardhi, Madhubani, Darbhanga, Muzffarpur, Vaishali, Samastipur
- II. Zone Two- Nine Districts- Begusarai, Khagaria, Saharsa, Madhepura, Supaul, Araria, Kishanganj, Katihar
- III. Zone Three-Seventeen Districts- Buxar, Bhojpur, Kaimur, Rohtas, Aurangabad, Gaya, Jehanabad, Arwal, Patna, Nalanda, Nawada, Sheikhpura, Jamui, Banka, Lakhisarai,, Munger and Bhagalpur

Source :SDMP at www.disastermgmt.bih.nic.in

- 3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd
 - ❖ Agro-Climatic Zones are important for analyzing drought scenario in State. Zone One and Two Highly fertile. Zone one is conducive to Kharif crops and Zone Two is conducive to Rabi crops.

❖Water Bodies :-

- (I) North Bihar Rivers- Ganga and its tributaries, Ghaghara, Gandak, Budhi Gandak, Bagmati, Kamla, Kosi, Mahananda etc
- (II) South Bihar Rivers- Son, Punpun, Karmnasa, Falgu, Qual, Sakri etc.
- (III) Other Water Bodies- Ponds, Rivulets, Pine etc Geographical-Cultural Zones

Zone One- Ghaghra –Gandhak Zone- W. Champaran, E. Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran.

Source :SDMP at www.disastermgmt.bih.nic.in

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

Zone Two- Gandhak-Bagmati Zone- Sheohar, Sitamardhi, Vaishali, Samstipur, Begusarai

Zone Three- Bagmati-Kosi Zone- Darbhanga, Madhubani, Supaul, Saharsa, Khagria,

Zone Four- Kosi-Mahananda Zone- Madhepura, Araria, Kishanganj, Katihar, Purnea

Zone Five- Karmnasa-Son Zone- Buxar, Bhojpur, Kaimur, Rohtas

Zone Six- Son-Punpun Zone- Patna, Jehanbad, Arwal, Nalanda, Nawada, Aurngabad

Zone Seven- Punpun-Sakri Zone- Shekhpura, Lakhisarai, Banka, Jamui, Bhagalpur

Source:

SDMP at www.disastermgmt.bih.nic.in

- 3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd
 - Climate and Rain Fall:-
 - Hot and Humid, Temp. up to 45degree in summer and up to 4 degree to 5 degree winter.
 - Average Rain Fall 1120mm-mostly through south-west Monsoon.
 - Rain Fall highly erratic
 - ❖ Forest :- Only 6.87% of area(National average 15%).

Source :SDMP at www.disastermgmt.bih.nic.in

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

Social Economic conditions.

Maternal Mortality rate :- 261 per lac live birth

Infra mortality rate :- 66 per one thousand live birth

Poverty of Bihar in approx 70%

Courtesy: www.censusindia.gov.in (Bihar chapter)

3. प्रमुख आपदाओं के संबंध में बिहार राज्य की प्रवणता का संक्षिप्त परिचय (मानचित्र के साथ)contd

Infrastructure related issue(Transpotation)

Roads:-

Major District Road :- 1145.28 km

State Highway 4005.56km

National Highway 4917.19 km

Total 20068.03 km

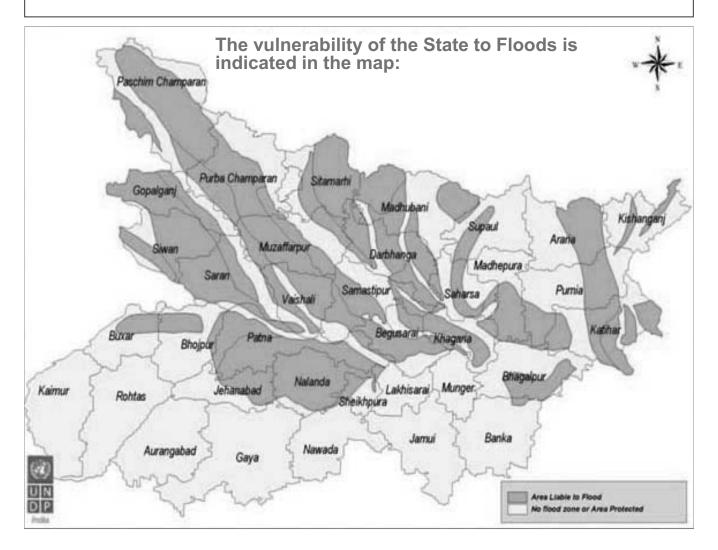
❖ Bihar has lowest lane kilometer density but due to lack of awareness and deviant behavior pattern road accidents are re-current

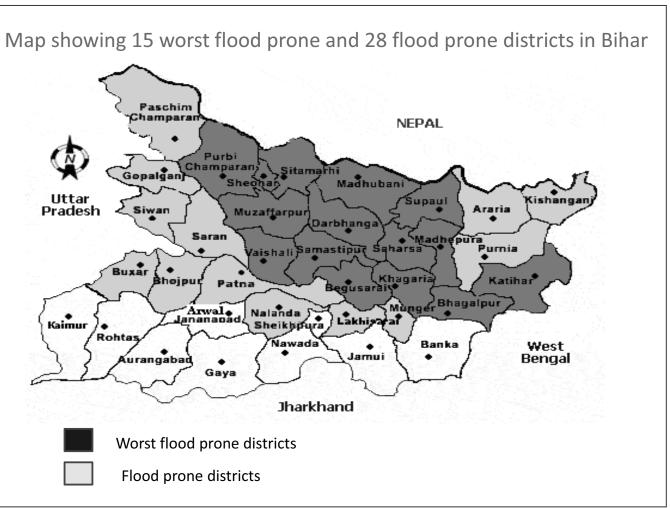
Water ways :-

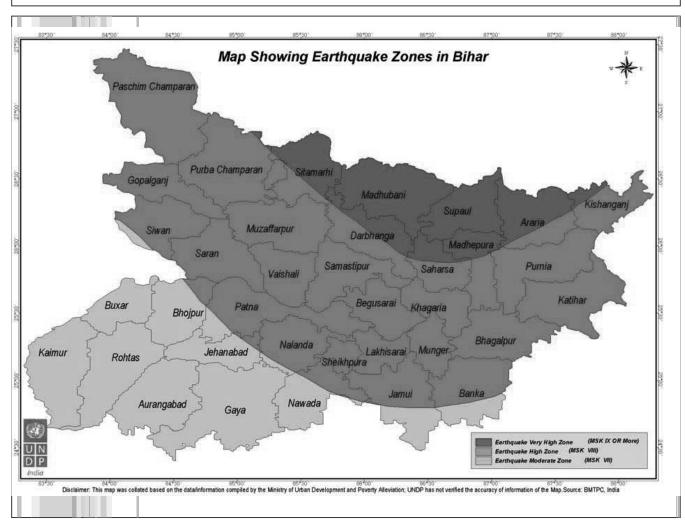
State criss-crossed by River.

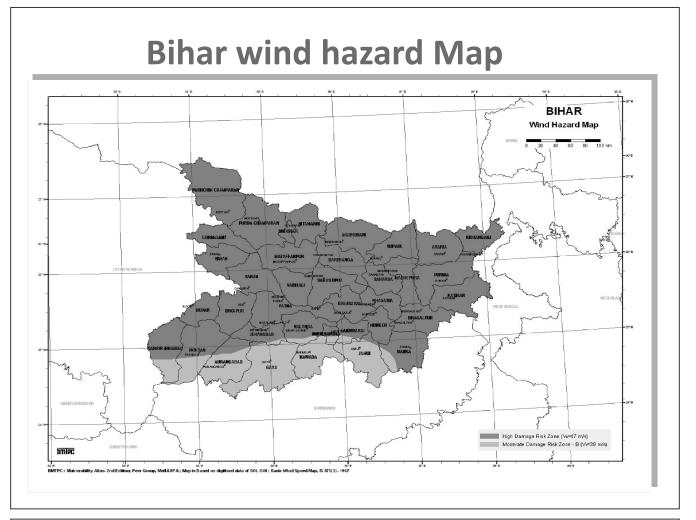
Death due to boat-capsizing.

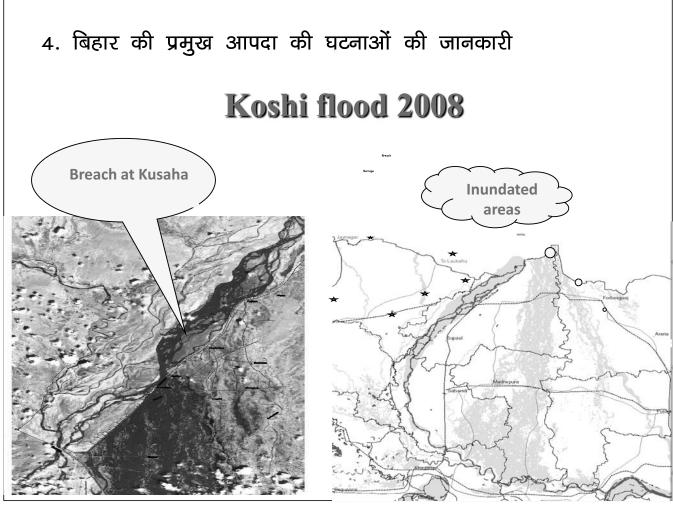
Courtesy: www.rcd.bih.nic.in











Major Disaster Events:

Floods - 2007, 2008,2016 and 2017 Drought- 2009, 2010 and 2013 Earthquake- 2015 Cyclonic Storm — 2010 and 2015 Lightening Death-Fire incidents in 2016 Boat capsizing- नारियल घाट(2017), पटना, खगड़िया Stamped - Gandhi Maidan(2013), Patna

4. बिहार की प्रमुख आपदा की घटनाओं की जानकारीcontd

IMPACT (Koshi Flood)

 Name of affected Districts -Supaul, Madhepura, Saharsa, Araria, Purnia

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•	No. of Blocks affected	- 35
•	No. of Panchayats affected	- 412
•	No. of villages affected	- 993
•	Population affected	- 3329423
•	Live Stock affected	- 712140
•	Area affected in hac	- 368000
•	No. of human deaths	- 527
•	No. of live stock deaths	- 19323
•	No. of houses damaged	- 220174

Courtesy:www.disastermgmt.bih.nic.in

Response

- One of the largest ever evacuation operations 993992 persons evacuated .
- 3500 police personnel, more than 5,000 civilian personnel,
 35 columns of Army, 4 columns of Navy & 855 NDRF
 personnel deployed for evacuation.
- More than 1500 country boats (including 843 requisitioned from other districts) and 561 motor boats deployed.
- Each unit made responsible for evacuation from specific panchayats.

Courtesy:www.disastermgmt.bih.nic.in

Flood 2007

- •Heavy rainfall in the catchment areas of Bagmati, Kamla-Balan, Budhi-Gandak, the Adhwara group of rivers and the Kosi in the July, 2007 led to unprecedented floods in **19 districts** of Bihar.
- •Rivers rose above danger levels and embankments were breached at **32 points** inundating and devastating vast stretches of thickly populated areas.

Flood-2007- Cont.....

- » A total of **264** blocks, **3817** Panchayats and **18832** villages were ravaged, affecting total population of **244.42 lakh** & **27.13 Lakh** live stock.
- » This flood was severest to date. 741 people died, 748328 houses were damaged & 2423 livestock was lost.
- » The state launched massive relief operations. A total of **8375** boats were deployed;

Contd.....

- 4. बिहार की प्रमुख आपदा की घटनाओं की जानकारीcontd
- » Flood 2016

Impact

- ❖ Total no of District affected 31
- ❖ Total no of Block affected 185
- ❖ Total no of Panchayat affected 1408
- ❖ Total no of Villages affected 5527
- ❖ Total Area affected (Lac ha) 43.3
- House damage (incl. Pucca, kuchha & Huts) -69102

Response

- ❖ GR distribution (in qtls.) -30593.7
- ❖ GR distribution (cash in lac) -54467.6
- Ready food (in qtls.) -80475.1(chura), 2622.6 (chana), 9382 (sattu), 8045.5(gur), 10011(khichri)
- Material distributed- 14971 lts(k Oil), 291482(polythene), 987677 (candles), 569661(matches)

4. बिहार की प्रमुख आपदा की घटनाओं की जानकारीcontd

Other Major disaster events:

Drought	2009 (26 Districts affected), 2010 (28 Districts affected), 2013 (33 Districts affected)
Earthquake	2015 (71 Deaths, 9 injured)
Cyclonic storm	2010, 2015 (57 deaths)
Lightening Thunder	2015 (approx 154 deaths), 2016 (approx 200 deaths)
Fire incidents	All 38 Districts affected in 2017 (19 human deaths & 34 injured, 376 livestock deaths & 33 injured, total house damaged-4605, total crops damaged-1030.82 ha.)
Boat capsizing and Drawing	Nariyal ghat incidents, Khagria incidents, Sabbalpur Diyara, Patna (24 deaths, injured)
Stampede	Chhat 2012(18 deaths), Rawan dahan Gandhi Maidan Oct'2014 (33 deaths, 39 injured), Baunsi stampede (3 deaths)
Road accident	Madhubani 2016 (23 deaths)

Courtesy:

www.disastermgmt.bih.nic.in

5- vf/kl for Lakdird vkink, a 1/4kjr ljdkj }kjk½



- 1- ck<+
- 2- 1 **(| kkM**+
- 3- vfXudkM



- 4- Hard Ei
- 5- pØokr
- 6-vkykof"V



- 10-ckny QVuk
- 11- dhV dk vhØe.k
- 12- 'khrygj



- 7-fgeikr
- 8- **H**w&L[kyu
- 9-1 qukeh



आपदा प्रबंधन विभाग





- 5- vf/kl for Lakdfrd vkink, a lacgki jkT; dh fo'kk LFkkuh, izdfr dh vkink/2
 - » पूर्व में उल्लिखित प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक 33-4/2015-NDM-1 दिनांक 20.03.15 के आलोक में राज्य सरकार ने विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं को अधिसूचित किया है।
 - » ये आपदाएं हैं:— वजपात, लू, अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, निदयों/ तालाबों/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जिनत सामूहिक दुर्घटना यथा—सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव।
 - » विशेष स्थानीय प्रकृति के आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदर के अनुरूप 10 प्रति ात की सीमा तक अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है। अधिसूचना 20.03.015 से प्रभावी।
- » द्रष्टव्य–आपदा प्रबंधन विभाग बिहार का पत्रांक1 प्रा0आ0–17/2015/1973/आ0प्र0 दिनांक–26.05.2017

Website-http://www.disastermgmt.bih.nic.in/



CHANGING ROLE OF DISASTER MANAGEMENT AND ITS NATIONAL TO DISTRICT LEVEL STRUCTURE

(IN BIHAR DEPARTMENT OF RELIEF & REHABILITATION SEPARATED- 1977-78

RENAMED DEPARMENT OF DISASTER MANAGEMENT - 18-03-2004)

A Presentation by, VIPIN KUMAR RAI

CONTENTS

- 1.Evolution of DM in India & Paradigm shift (National factors responsible for Activity based Reactive set-up to Pro-active Institutionalized Structure)
- 2. Paradigm shift in approach of DM(Responsible International factors)
- 3. Constitutional basis of DM Act-2005
- 4.Good governance basis of new approach of DM
- 5.Qualitative shift in India's Strategy of DM: Guided by HFA(2005-15),(Institutions at centre & state)
- 6.Role of Central Govt. in DM
- 7. Role of State Govt. In DM
- 8. Role of District Administration in DM
- 9. National Policy on Disaster Risk Management 2009
- 10.HFA(2005-15) to Sendai Frame Work for DRR(2015-30): manifestation of DRM
- 11.Need of Disaster risk Governance /DRM in post HFA Policy- Framework
- 12.Disaster Risk Governance: A function of Sustainable development and livelihood
- 13.DRM: An essential ingredient to achieve sustainable livelihood
- 14.Disaster Risk Governance includes DRM
- 15. DRR vs. DRM: a perception
- 16. Structure under DM Act 2005 & their function (A brief Introduction)

1.Evolution of DM in India & Paradigm shift (National factors responsible for Activity based Reactive set-up to Pro-active Institutionalized Structure)

3

- □ Over the past century, DM in India has undergone substantive changes in its composition, nature &policy.
- DM in India has evolved from-
- > An activity based reactive set-up to pro-active institutionalized structure
- Single faculty domain to a multi-stakeholders set -up
- > Relief based approach to a multi-dimensional pro active holistic approach for reducing risk
- □ During British administration
- > Relief departments were set-up with a reactive approach, functional only in post disaster scenarios.
- > The policy was relief oriented & activities included designing the releif codes and initializing food for work programmes.
- Post independence Relief commissioners appointed in each state with role limited to delegation of relief material and money in the affected area.
- > Every five year plan addressed flood disasters under "Irrigation, command area development and flood control"

CONTD....

- □ In India famine codes developed in the 19th century, which provided a formal basis disaster relief activities and relief manuals introduced by states both before and after independence.
- □ The environment protection act 1986 and a number of rules under the act were developed after Bhopal gas tragedy.
- Several other acts, rules and codes relating to the subject of water, air, fire, chemicals, micro organism were enacted at the national and state level.
- □ Emergence of Institutional frame-work in the decade of 1990s
- > 1990 decade was declared" International decade for natural disaster reduction (IDNDR) by UN General Assembly
- > Disaster management cell was set up in Ministry of Agriculture
- > Following series of disasters-Latur EQ(1993), Malpa landslide (1994), Orissa super cyclone(1999) & a <u>High Power Committee</u> was constituted **in August 1999** for drawing up a systematic, comprehensive and holistic approach towards disaster.

CONTD....

5

- High Powered Committee (HPC) submitted its report in October 2001, recommending a Model National Calamity Management Act and a Model State Disaster Management Act.
- Also ,after the Bhuj earthquake in January 2001, a National Committee on Disaster Management was constituted in February 2001 under the chairmanship of Prime Minister, which set up a Working Group to assist it.
- > The Working Group consisted of the Vice Chairman of the National Committee and the High Power Committee.
- > The Working Group presented its report to the Prime Minister in June 2003.
- > The Working Group endorsed the recommendation of the HPC made in October 2001 for enacting the Disaster Management act.
- > Initially instead of central legislation, GOI was in a view to advise the state to enact their own respective legislation, because the constitution of India does not explicitly mention disaster management as a subject in any of three lists of the Seventh Schedule. Also the state like Gujrat, Bihar U.P, had enacted their own legislation before DM Act 2005.
- > The Asian Tsunami Disaster in December 2004, accelerated the process of making of Central legislation on DM.

2. PARADIGM SHIFT IN APPROACH OF DM (Responsible International factors)

- □ From relief & rehabilitation to prevention & mitigation through a holistic and comprehensive approach triggered by
- > The UN move to observe the 1990s as IDNDR,
- > The Yokohama strategy and plan of action for a safer world(1994) and
- The Hyogo framework for action (2005-15)-building the resilience of nations and communities to disasters(HFA),2005 adopted by UN
- ☐ The focus turned to legislation, policy and institutional arrangements as important ingredients of a holistic approach to disaster management.
- □ It supported organizational arrangements and plans, allocated major legal responsibilities crucial for proper implementation.
- Achievements identified in National policy & legislation in DM and it provided a formal basis for DM relating to Preparedness/Response/ Recovery & Reconstruction

3. Constitutional basis of DM Act-2005

7

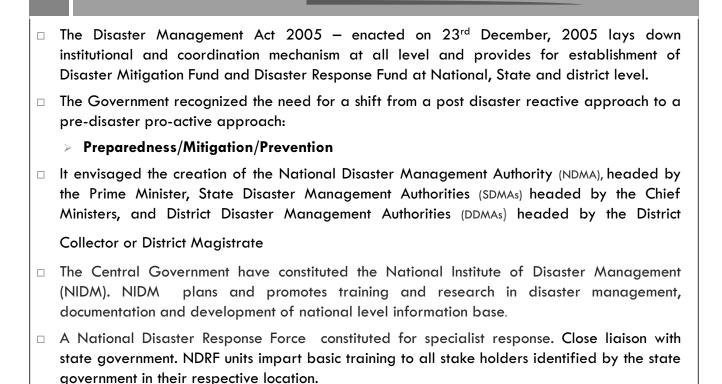
- Disaster management is not mentioned as any subject of three lists of the seventh schedule- Union list/State list/Concurrent list.
- According to one view a subject not specifically mentioned in any of the three lists comes under the Residuary Power of Union under entry 97of Union list, there fore centre has the competence to legislate on the subject.
- □ But, by practice and convention the primary responsibility for managing disasters rests with the state.
- □ The Parliament enacted the DM act 2005 by invoking entry 23, namely " Social Security Insurance, Employment & Unemployment" in Concurrent list of the Constitution of India.
- ☐ This also has the advantage that States can have their own legislation on DM as well.

30-Jan-19

4.Good Governance basis of new approach of DM

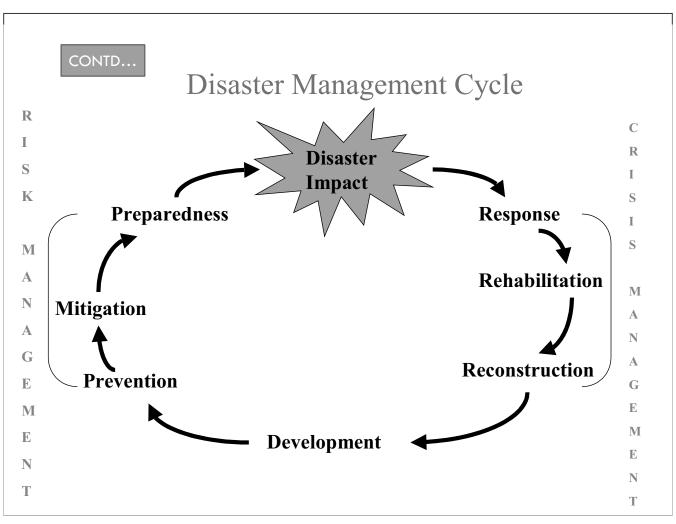
- □ It proceeds from the conviction that development cannot be sustainable unless disaster mitigation is built in, in the development process.
- Objective is that hazards may be prevented from turning into disaster by taking mitigation and preparedness process.
- □ It is observed that the response to disasters could be improved if appropriate preparedness and capacity building measures are put in place.

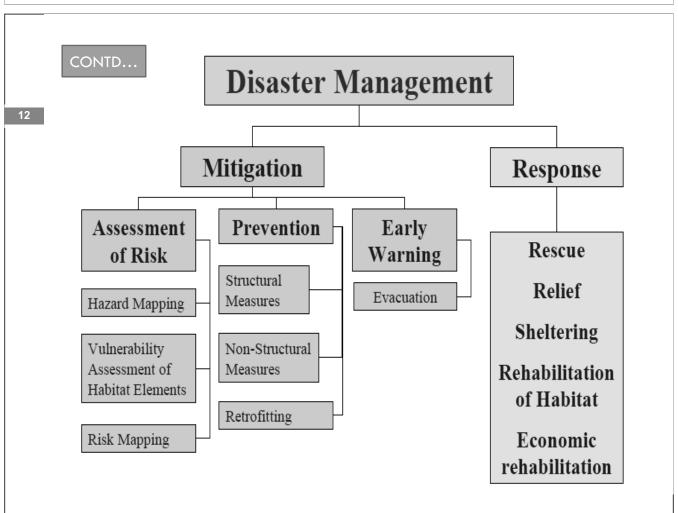
5.Qualitative shift in India's Strategy of DM: Guided by HFA(2005-15) (DM Act 2005 and DM Institutions at centre & state)



CONTD....

- This shift in strategy was feasible because of :
- Advancement in Science and Technology
- Effective Implementation has shown decline in casualties.
- Advancements in forecasting technologies and warning systems
- Standardization.
 Standardization.
- Enlargement and reinforcement of disaster prevention systems, equipment and facilities.





What is Disaster Management?

CONTD

Preparedness -- activities prior to a disaster. Examples: preparedness plans; emergency exercises/training; warning systems.

Response -- activities during a disaster. Examples: public warning systems; emergency operations; search and rescue.

Recovery -- activities following a disaster. Examples: temporary housing; claims processing and grants; long-term medical care and counseling.

Mitigation - activities that reduce the effects of disasters.

Examples: building codes and zoning; vulnerability

analyses; public education.

BSDMA

Preparedness

6. ROLE OF CENTRAL GOVT. IN DM

- In the event of a disaster of a severe nature, <u>National Crisis Management</u> <u>Committee</u> under Cabinet Secretary gives policy, directions and guidelines to the Crisis Management Group.
- Crisis Management Group in MHA reviews the situation in Inter-Ministerial meeting to coordinate various emergency support functions for the affected States.
- □ Union Cabinet may set up a Cabinet Committee/Task Force/GoM for effective coordination of relief measures in the wake of calamities of severe nature
- Nodal Agencies for different Disasters at National level-
- Floods: Ministry of Water Resources, CWC/Cyclones: Indian Meteorological Department/ Earthquakes: Indian Meteorological department/Epidemics: Ministry of Health and Family welfare/Chemical Disasters: Ministry of Environment and Forests
- Industrial Disasters: Ministry of Labor/Rail Accidents: Ministry of Railways

CONTD....

15

- > Air Accidents : Ministry of Civil Aviation
- > Fire: Ministry of Home Affairs
- Nuclear Incidents : Department of Atomic Energy
- Mine Disasters : Department of Mines
- □ Central and State Governments are jointly responsible for undertaking mitigation, preparedness, response, relief and rehabilitation measures.
- Central Government supplements the efforts of State Government by providing financial and logistic support in case of a major calamity.
- ☐ The Central Government is responsible for coordination of actions by Ministries/Departments of the Central Government, National Authority, State Authorities, governmental and non governmental organizations.

CONTD....

- ☐ The Central Government ensures integration of measures for prevention and mitigation of disasters.
- The Central Government ensures appropriate allocation of funds for disaster management
- The Central Government has the power to issue directions to NEC, state government, SDMA, SEC for any of their officers or employees to assist in DM and these bodies and officials shall be bound to comply with such direction.
- □ Takes measures for the deployment of Armed Forces for DM.
- □ Facilitate coordination with UN Agencies, International Organization and the governments of foreign countries in the field of DM. The ministry of External Affairs in coordination with Ministry of Home Affairs will facilitate external coordination and cooperation.

7. ROLE OF STATE GOVT, IN DM

17

- □ The primary responsibility for disaster management rests with the states .
- □ A State level Crisis Management Committee under the Chairmanship of Chief Secretary is responsible for formulating policies and guidelines for management of natural disasters in the States.
- ☐ This committee comprises of concerned functionaries in various State Departments and representatives of Central Organizations located in the State.
- PS DMD is the Nodal Officer for coordinating the activities for relief operations in the event of natural disasters.
- The State Government takes action for integration of measures for prevention and mitigation of disasters in their development plans; and provide rehabilitation and reconstruction assistance to the affected people.
- These measures also include emergency communication; transporting personnel and relief goods; evacuation, rescue of affected population, livestock, temporary shelters or other immediate relief.

CONTD...

- □ The disaster management Act 2005 mandates states government to take measures for preparation of Disaster Management Plans, integration of measures for prevention of disasters or mitigation into development of early warning systems, and to assist the Central Government and other agencies in various aspects of Disaster Management.
- Every Department of the State Governments prepares a Disaster Management Plan in respect of roles and responsibilities assigned to it and review and update it annually.

8. ROLE OF DISTRICT ADMINISTRATION IN DM

10

- □ District level is the focal point in a disaster situation from which disaster management related activities are coordinated and implemented.
- □ A district level committee exists under the District Collector / Deputy Commissioner.
- District Collector is the key functionary for directing, supervising and monitoring all Disaster Management operations.

9. National Policy on Disaster Risk Management 2009 (Approved by the Union Cabinet on 22nd October, 2009)

Vision

To build a safe and disaster resilient India by developing a holistic, proactive, multi-disaster oriented and technology driven strategy through a culture of prevention, mitigation, preparedness and response.

Approach

A holistic and integrated approach will be evolved towards disaster management with emphasis on building strategic partnerships at various levels. The themes underpinning the policy are:

- Community based DM, including last mile integration of the policy, plans and execution.
- Capacity development in all spheres.
- Consolidation of past initiatives and best practices.
- Cooperation with agencies at National and International levels.
- Multi- sectoral synergy.

CONTD...

Objectives

- a culture of prevention, preparedness and resilience at all levels through knowledge, innovation and education.
- Encouraging mitigation measures based on technology,
 traditional wisdom and environmental sustainability.
- Mainstreaming disaster management into the developmental planning process.
- □ Establishing institutional and techno legal frameworks to create an enabling regulatory environment and a compliance regime.

CONTD...

- Ensuring efficient mechanism for identification, assessment and monitoring of disaster risks.
- Developing contemporary forecasting and early warning systems backed by responsive and fail-safe communication with information technology support.
- Ensuring efficient response and relief with a caring approach towards the needs of the vulnerable sections of the society.
- Under taking reconstruction as an opportunity to build disaster resilient structures and habitat for ensuring safer living.
- Promoting a productive and proactive partnership with the media for disaster management.

9.HFA(2005-15) to Sendai Frame Work for DRR(2015-30): manifestation of DRM

HFA Priorities for Action

- DRR, a national and a local priority with a strong institutional basis.
- Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning.
- Build a culture of safety and resilience at all levels,
- Reduction of underlying risk factors.
- Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels.

Sendai Priorities for Action

- Understanding of disaster risk in all its dimensions of vulnerability, capacity, exposure of persons and assets, hazardcharacteristics and the environment.
- Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk at the national, regional and global level.
- Public & private investment in DRR for economic, social, health and cultural resilience of person, community and countries.
- Enhancing disaster preparedness for effective response.

CONTD...

Challenge before Policy makers during HFA (2005-15)

- Policy makers of developing countries showed their interest to
 - > Select measures that reduce the overall level of risk.
 - > Protect the most vulnerable.
 - > Gain credibility.

Efficient" way.

& all above are, at the same time, must in a "Economically

The above approach has propagated the need of better understanding and realization of DRM that any economic assessment of risk must take account of environmental loss and a full appreciation of the range of benefits of effective Risk Governance for persons, communities and countries.

11.Need of Disaster risk Governance / DRM in post HFA Policy-Framework

- Despite the prevailing recognition that Good Governance and DRR are mutually supportive objectives, the understanding of the linkage is still at a nascent stage.
- Mainstreaming DRR concerns into development practices as an underlying principle, is still pending.
- □ The failure to prioritize DRR and the resulting absence of its inclusion in country development policies, planning and implementation leads to new or heightened patterns of disaster risk, and ultimately an increased risk of the loss of lives and livelihoods.
- □ More than 95% of humanitarian finance is still spent on responding to disaster and their aftermath with less than 5% spent on reducing the risk of disasters.
- Particularly in Asia and Africa, growing impact of climate change on the frequency and severity of extreme whether events.

CONTD...

- □ The data on disaster impacts and risks vary considerably in quality and quantity makes difficult to evaluate accurately the magnitude of problem.
 - Extensive risk, characterized by small scale and repeated disasters have much impact on communities than the intensive mega disaster but these daily disasters often go uncounted.
 - > Greater consistency in the reporting of and documentation of disaster, as well as evidence on the effectiveness of risk management measures, is crucial to establish baseline and track.
 - > Thorough analysis of causes using up-to-date scientific and technological knowledge and institutional analysis to built an evidence base of how natural hazards become disasters.
 - Risk assessment to identify the extent of risk, are based on data about hazard, exposure, vulnerability and capacity. They could be used to identify priorities of intervention and avoid risky investment.

CONTD...

- □ To Improve inter-sectoral coordination.
 - > Though HFA prompted to creation of national legislation and organization structures for DRM, but work of those organization that already exist is not acknowledged or strengthened.
 - Government departments, such as Water resources, Health and Agriculture already doing a lot to reduce the impact of hazards, without labeling it DRM, but their activity is rarely coordinated and often go unnoticed.
 - Government departments are not accustomed to working together on cross-cutting issues, but can be encouraged to do so, through inter-sectoral planning and budgeting for DRM and wider efforts to make development more resilient.
- Evolving the mechanism of accountability and evaluation.
 - > To know about the implementation and outcome of DRM policy in term of reducing disaster risk.
 - > To make relevant and realistic targets and milestones for implementation of DRM through multi stakeholder consultation.
 - Creation of regional platform and forums to demonstrate method and tools to achieve targets and oversee report on progress.

12.Disaster Risk Governance : A function of Sustainable development and livelihood

- Natural disasters set back development gains
- Unsustainable development increases disaster risk
- Disaster losses may be considerably reduced by integrating DRM practices in development programmes
 - > By strengthening institutions and mechanism of DRM
 - > Assisting vulnerable groups to
 - o build assets,
 - diversify income generating activities
 - strengthen community-based self-help institutions.
 - DRM practices and principles in sectoral development and post-disaster rehabilitation plans.

Contd....

- Special long-term DRM interventions to increases the coping capacities of the poorest and most vulnerable.
 - Development policies and programmes that assist poor men, women and youth to build livelihood assets, diversify income-generating activities, improve human capacities (health, nutritional status, education, technical skills), and strengthen community-based self-help organizations, can make a major contribution to reducing vulnerability and risk, and improving the coping strategies of the poorest.
- Improved technologies can help prevent or mitigate damage caused by natural hazards, like
 - > Water control/ conservation technology
 - > Improved Crops varieties that are drought or flood tolerant and disease and pest resistance
 - > Soil conservation techniques etc.
- Disasters may become opportunities for building back better development practices

13.DRM: An essential ingredient to achieve sustainable livelihood

Natural resources provide key livelihood assets and security, especially in rural areas.
A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living.
Disasters reduce household livelihood assets to different degrees depending on the asset and type of disaster and lead to livelihood insecurity (and may result in death or injury)
Policies and institutions influence household livelihood assets positively or negatively.
Policies and institutions can increase or decrease vulnerability to disaster.
Enabling institutions and diversified household assets widen livelihood options
Asset ownership decreases vulnerability and increases ability to withstand disaster impacts
A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and maintain its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base.

14. Disaster Risk Governance includes DRM

- Supportive governance is necessary to ensure coping capacities of vulnerable people/community and manage disaster.
- Governance influences the way in which national and sub-national actors (including governments, parliamentarians, public servants, the media, the private sector, and civil society organizations) are willing and able to coordinate their actions to manage and reduce disaster-related risk.

Essentials of risk management and Risk Governance-

- > Public awareness to recognize risk
- Political will to set policies and allocate appropriate resources
- > Institutions with sufficient managerial and coordination capacity to manage and integrate the efforts of relevant sectors
- > Broad participation, transparency, accountability, efficiency and responsiveness
- > voices of the poorest and the most vulnerable are heard in decisions about the allocation of resources affecting them

15. DRR vs. DRM: a perception

Disaster Risk Reduction (DRR) refers to the conceptual framework of elements considered with the possibilities to minimize vulnerabilities and disaster risks throughout a society, to avoid (prevention) or to limit (mitigation and preparedness) the adverse impacts of hazards, within the broad context of sustainable development.

Disaster Risk Management (DRM) includes but goes beyond DRR by adding a management perspective (administrative mechanism procedures and related to the management of disasters) that both risk and combines prevention, mitigation and preparedness with response.

33

On 23 December 2005, the Government of India took a defining step by enacting the Disaster Management 2005, which envisaged the creation of the National Disaster Management Authority (NDMA), headed by Prime Minister, Disaster Management Authorities (SDMAs) headed by the Chief Ministers, and **District Disaster Management** Authorities (DDMAs) headed by the District Collector or District Magistrate



i)NDMA

- National Disaster Management Authority (NDMA)
 under the Prime Minister with such other members,
 not exceeding nine, as may be nominated by Prime Minister.
- One of the Members designated as the Vice-Chairperson of NDMA by the Prime Minister.
- The National Authority have the responsibility for laying down the policies, plans and guidelines for disaster management.

Functions of NDMA

35

- □ Lay down policies on Disaster Management
- Approve the National plan.
- Approve plans prepared by Ministries/ Departments of GOI.
- Lay down guidelines to be followed by State Authorities in drawing up state plans.
- Coordinate enforcement and implementation of policies and plans.
- Recommend provision of funds for mitigation.

30-Jan-19

Contd.

- □ Take measures for prevention, mitigation, preparedness and capacity building for dealing with threatening disaster situation or disasters.
- □ Lay down broad policies and guidelines for NIDM.
- □ Recommend guidelines for minimum standards of relief.
- Recommend relief in the payment of loans or for grant of fresh loans in case of disasters of severe magnitude.

ii)SDMA

37

- Setting up of State Disaster Management Authority (SDMA) by the State Government under the Chief Minister with eight other members to be nominated by the Chief Minister and the Chairperson of the State Executive Committee.
- One of the members my be designated as the Vice-Chairperson of the State Authority by the Chief Minister.
- The State Authority may constitute an Advisory Committee of experts, as when it considers necessary.

- The State Authority responsible for laying down the policies and plans for disaster management in the State.
- The State Authority recommend guidelines for providing minimum standards of relief to persons affected by disaster in the State provided that such standards shall not be less than the minimum standards laid in down in the guidelines by the National Authority
- The State Authority will be assisted by the State Executive Committee.

Functions of SDMA

- x Lay down state DM policies; approve the state plan as per guidelines laid down by NDMA.
- * Approve DM plans of State departments.
- * Lay down guidelines for integration of measures for prevention and mitigation in the development plans and projects.
- * Coordinate implementation of State plan.
- * Recommend provision of funds for mitigation and preparedness measures.
- * Lay down detailed guidelines for standards of relief.

iii) DDMA& its Functions

39

- States to establish DDMA for every district headed by District Magistrate.
- DDMA to act as the district planning, coordinating and implementing body for DM and take measures in accordance with the guidelines laid down by NDMA and SDMA.
- Prepare district disaster management including response plan.

30-Jan-19

DDMA-Contd.

- Coordinate implementation of national policies, state policies, national plan, state plan and district plan.
- □ Take measures for prevention of disaster and mitigation of its effects through departments at district level and local authorities.
- Examine construction standards; ensure communication systems; involve NGOs and take all operational measures.
- □ Detailed functions laid down in section 30.

iv) NIDM

41

- ☐ The Central Government have constituted the National Institute of Disaster Management (NIDM)
- NIDM plans and promotes training and research in disaster management, documentation and development of national level information base relating to disaster management policies, prevention mechanism and mitigation measures.
- Develops HRD plan for DM.
- Develops training modules and training of different stake holders.

DISASTER RISK GOVERNANCE: IN BIHAR









THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005

Dr. Gagan PGRO, Mahnar (Vaishali) General Administration Department, GoB

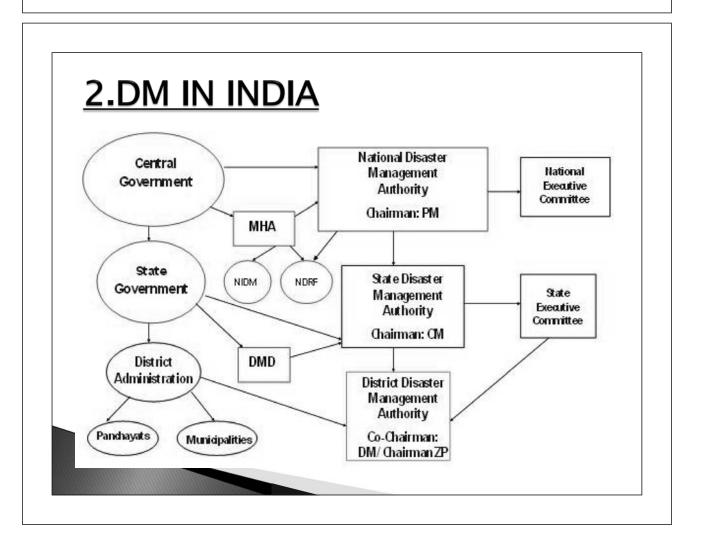


Plan of Presentation

- ▶ 1. Historical background
- > 2. Disaster Management architecture in India
- ▶ 3. Salient features of Disaster Management Act.
- 4. Definition as per DM Act.
- ▶ 5. National level organizations
- ▶ 6. State level organizations
- ▶ 7. District level Structure
- 8. Other Provision
- ▶ 9. NIDM
- ▶ 10. NDRF
- ▶ 11. National Policy, 2009
- ▶ 12. Finance, Accounts & Audit
- 13. Offences and penalties
- 14. Miscellaneous

1. HISTORY OF DISASTER MANAGEMENT IN INDIA

- High Powered Committee set up in August 1999.
- Until 2001 Responsibility with Agriculture Ministry,
- Transferred to Ministry of Home Affairs in June 2002.
- Disaster Management Act passed by the parliament received the assent of the President on the 23rd December 2005.



Cont.....

- ► The Ministry of Home Affairs (MHA) in the Central Government has the overall responsibility for disaster management in the country.
- For a few specific types of disasters the concerned Ministries have the nodal responsibilities for management of the disasters, as under

Drought
Epidemics & Biological Disasters
Chemical Disasters
Nuclear Disasters
Air Accidents
Railway Accidents

Ministry of Agriculture
Ministry of Health and Family Welfare
Ministry of Environment & Forests
Ministry of Atomic Energy
Ministry of Civil Aviation
Ministry of Railways

Cont.....

- In the federal polity of India the primary responsibility of disaster management vests with the State Governments
- Central Government lays down policies and guidelines and provides technical, financial and logistic support while the district administration carries out most of the operations
- The Cabinet Committee on Management of Natural Calamities (CCMNC) oversees all aspects relating to the management of natural calamities
- The National Crisis Management Committee (NCMC) under the Cabinet Secretary oversees the Command, Control and Coordination of the disaster response

3. SALIENT FEATURE OF THE DISASTER MANAGEMENT ACT

- •The Disaster Management Act 2005 has provided the legal and institutional framework for disaster management in India at the national, state and district levels.
- Paradigm Shift from Response Centric to a Holistic and Integrated Approach.
- Backed by Institutional Framework and Legal Authority.
- Supported by Financial Mechanism
- Creation of new Funds, i.e., Response Fund and Mitigation Fund at National, State and District levels.
- ❖NDRF (Sec-46), NDMF(Sec-47)
- ❖SDRF(Sec-48), SDMF (Sec-48)
- ❖DDMF (Sec-48), DDRF (Sec-48)

Cont.....

Consists of 11 Chapters and 79 Sections

- Definitions (Sec-2)
- Institutional arrangements at National, State and District levels
- ❖NDMA (Sec-3), SDMA(Sec-14), DDMA (Sec-25)
 - The measures taken by Government (Sec.-35,36,37,38,39 & 40)
 - Local Authorities (Sec.-41)
 - National Institute of Disaster Management (Sec.-42)
 - National Disaster Response Force (Sec.-44)
 - Finance, Accounts & Audit (Sec.-46 to Sec-50)
- Section-50, Emergency procurement
 - Offence & Penalties (Sec.-51 to Sec.-60)
 - Miscellaneous (Sec.-61 to79)

4. **DEFINITIONS**

- ❖ "disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;
- ❖ "disaster management" means

4. **DEFINITIONS**

- ❖ "disaster management" means a continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating and implementing measures which are necessary or expedient for-
- i. Prevention of danger or threat of any disaster;
- ii. Mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences;
- iii. Capacity-building;
- iv. Preparedness to deal with any disaster;
- v. Prompt response to any threatening disaster situation or disaster;
- vi. Assessing the severity or magnitude of effects of any disaster;
- vii. Evacuation, rescue and relief;
- viii. Rehabilitation and reconstruction;

4. **DEFINITIONS**

- *mitigation" means measures aimed at reducing the risk, impact or effects of a disaster or threatening disaster situation;
- *"preparedness" means the state of readiness to deal with a threatening disaster situation or disaster and the effects thereof;
- "reconstruction" means construction or restoration of any property after a disaster;
- ❖ "National Plan" means the plan for disaster management for the whole of the country prepared under section 11;
- *"State Plan" means the plan for disaster management for the whole of the State prepared under section 23.

4. **DEFINITIONS**

- ❖"National Authority" means the National Disaster Management Authority established under sub-section (I) of section 3;
- *"State Authority" means the State Disaster Management Authority established under sub-section (1) of section 14 and includes the Disaster Management Authority for the Union territory constituted under that section;
- ❖ "National Executive Committee" means the Executive Committee of the National Authority constituted under subsection (1) of section 8;
- *"State Executive Committee" means the Executive Committee of a State Authority constituted under sub-section (1) of Section 20;

5. NATIONAL LEVEL

National Disaster Management Authority

- Chaired by Hon'ble Prime Minister
- A Vice Chairperson and upto 8 Members
- Advisory Committee (consisting of experts in the field of disaster management)

Contd.....

- · Lay down Policy and Guidelines.
- Approve National Disaster Management (DM) Plan and DM Plans of Ministries & Departments.
- Coordinate enforcement and implementation of policy and plans.
- Lay down guidelines to be followed by the State Authorities in drawing up the State Plan
- Take Measures for :-
 - · Prevention.
 - · Preparedness (including Capacity Development).
 - Mitigation.
 - · Awareness Generation.
 - Rehabilitation and Recovery

Contd.....

National Executive Committee

- To assist the National Authority in the performance of its functions.
- Chaired by Union Home Secretary

Important functions

- Act as the coordinating and monitoring body for disaster management;
- Prepare the National Plan
- Coordinate and monitor the implementation of the National Policy;
- Lay down guidelines for preparing disaster management plans by different Ministries or Departments and the State Authorities;
- Provide necessary technical assistance the State

Contd.....

National Plan

• Plan for disaster management for the whole of the country

• Guidelines for minimum standards of relief

- The minimum requirements to be provided in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation;
- The special provisions to be made for widows and orphans:
- Ex gratia assistance on account of loss of life/ damage to houses/ restoration of means of livelihood;

Relief in loan payment

• Recommend relief in repayment of loans or for grant of fresh loans to the persons affected by disaster

6. STATE LEVEL

State Disaster Management Authority

- Chaired by Hon'ble Chief Minister
- A Vice Chairperson and upto 7 Members
- Advisory Committee (consisting of experts in the field of disaster management)
- Chief Secretary as the Chief Executive Officer of the State Authority as well as Chairperson of State Executive Committee.

Important functions of SDMAs

- Lay down the State disaster management policy;
- Approve the State Plan
- Approve the disaster management plans prepared by State Government Departments
- Lay down guidelines to be followed by the State Government Departments
- Recommend provision of funds for mitigation and preparedness measures
- Review the development plans of the different departments of the State
- Review the measures being taken for mitigation, capacity building and preparedness

Cont.....

State Executive Committee

- Implementing the National Plan and State Plan and act as the coordinating and monitoring body for management of disaster in the State
- Chaired by Chief Secretary

Important functions

- Examine the vulnerability of different parts of the State to different forms of disasters and specify measures to be taken for their prevention or mitigation
- Monitor the implementation of disaster management plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities
- Coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster
- Perform such other functions as may be assigned to it by the State Authority or as it may consider necessary.

Guidelines for minimum standard of relief by State Authority

 The State Authority shall lay down detailed guidelines for providing standards of relief to persons affected by disaster in the State: Such standards shall in no case be less than the minimum standards in the guidelines laid down by the National Authority

State Plan

- The State Plan shall be prepared by the State Executive Committee
- Shall be approved by the State Authority

7. DISTRICT LEVEL

District Disaster Management Authority

- Chaired by District Magistrate and consists of 7 members
- The elected representative of the local authority who shall be the cochairperson
- Chief Executive Officer: Officer not below the rank of Additional District Magistrate
- The District Authority may constitute one or more advisory committees for the efficient discharge of its functions

Some of the important functions of DDMA

- Prepare a disaster management plan including district response plan
- Ensure that the areas in the district vulnerable to disasters are identified and measures for the prevention of disasters and the mitigation of its effects are undertaken Bihar State

Cont.....

- Monitor the implementation of disaster management plans prepared by the Departments of the Government at the district level
- Review the state of capabilities for responding to any disaster
- Review the preparedness measures and give directions to the concerned departments
- Organize and coordinate specialized training programmes for different levels of officers
- Set up, maintain, review and upgrade the mechanism for early warnings and dissemination of proper information to public
- Facilitate community training and awareness programmes
- Provide information to the State Authority relating to different aspects of disaster management;

District Plan

- (1) There shall be a plan for disaster management for every district of the State.
- (2) The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with the local authorities and having regard to the National Plan and the State Plan, to be approved by the State Authority.
- (3) The District Plan shall include-
- (a) the areas in the district vulnerable to different forms of disasters;
- (b) the measures to be taken, for prevention and mitigation of disaster, by the Departments of the Government at the district level and local authorities in the district;
- (c) the capacity-building and preparedness measures required to be taken by the Departments of the Government at the district level and the local authorities in the district to respond to any threatening disaster situation or disaster;
- (d) the response plans and procedures, in the event of a disaster, providing for-

Contd...

- (i) allocation of responsibilities to the Departments of the Government at the district level and the local authorities in the district;
- (ii) prompt response to disaster and relief thereof;
- (iii) procurement of essential resources:
- (iv) establishment of communication links; and
- (v) the dissemination of information to the public;
- (e) such other matters as may be required by the State Authority.
- (4) The district Plan shall be reviewed and updated annually.
- (5) The copies of the District Plan referred to in sub-sections (2) and
- (4) shall be made available to the Departments of the Government in the district.
- (6) The District Authority shall send a copy of the District Plan to the State Authority which shall forward it to the State Government.
- (7) The District Authority shall, review from time to time, the implementation of the Plan and issue such instructions to different departments of the Government in the district as it may deem necessary for the implementation there of;

8. OTHER PROVISIONS

Measures taken up by central government

- Coordination among the ministries
- Ensure appropriate allocation of funds

Responsibilities of ministry or department of Gol

- · Mainstreaming and integration into development plans
- Make available its resources to NDMA/SDMAs

Disaster Management plans of Ministries

• Preparation of Disaster Management Plan

Measures taken up by State government

- coordination of actions of different departments of the Government of the State the State Authority, District Authorities, local authority and other nongovernmental organizations;
- cooperation and assistance in the disaster management to the National Authority and National Executive Committee, the State Authority and the State Executive Committee, and the District Authorities;
- Government of India in disaster management, as requested by them or otherwise deemed appropriate in it:

Measure to taken by State Govt. ..contd.

- allocation of funds for measures for prevention of disaster, mitigation, capacity-building and preparedness by the departments of the Government of the State in accordance with the provisions of the State Plan and the District Plans;
- ensure that the integration of measures for prevention of disaster or mitigation by the departments of the government of the State in their development plans and projects;
- integrate in the State development plan, measures to reduce or mitigate the vulnerability of different parts of the State to different disasters;

Activities to be taken up by the departments of the State Government

- (a) take measures necessary for prevention of disasters, mitigation, preparedness and capacitybuilding in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority;
- (b)allocate funds for prevention of disaster, mitigation, capacity-building and preparedness; (c)respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the State Plan, and in accordance with the guidelines or directions of the National Executive Committee and the State Executive Committee;
- (d)review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations with a view to incorporate therein the provisions necessary for prevention of disaster, mitigation or preparedness;
- (e)provide assistance, as required, by the National Executive Committee, the State Executive Committee and District Authorities, for-
- (i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity-building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;
- (ii) assessing the damage from any disaster;
- (iii) carrying out rehabilitation and it construction;

Measure to taken by State Govt. ..contd.

Disaster Management plan of the department of the State

Every department of the State Government, in conformity with the guidelines laid down by the State Authority, shall-

- 1. Prepare a disaster management plan which shall lay down the following:-
- (i) the types of disasters to which different parts of the State are vulnerable;
- (ii) integration of strategies for the prevention of disaster or the mitigation of its effects or both with the development plans and programmes by the department;
- (iii) the roles and responsibilities of the department of the State in the event of any threatening disaster situation or disaster and emergency support function it is required to perform;
- (iv) present status of its preparedness to perform such roles or responsibilities or emergency support function under sub-clause (iii);

<u>Disaster Management plan of the department</u> of the State . ..contd.

- (2) Every department of the State Government, while preparing the plan under sub-section (1), shall make provisions for financing the activities specified therein.
- (3) Every department of the State Government shall furnish an implementation status report to the State Executive Committee regarding the implementation of the disaster management plan referred to in sub-section (1).

Contd....

Local Authorities

- Ensure that its officers and employees are trained for disaster management
- Ensure all construction projects under it or within its jurisdiction conform to the standards and specifications laid down for prevention of disasters and mitigation

9.NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT



- The National Centre for Disaster Management, established in 1995
- Upgraded to National Institute of Disaster Management (NIDM) after the transfer of the subject of disaster management to the Ministry of Home Affairs.
- The main responsibility of the institute is
- Human resource development through development and implementation of human resource plans,
- · capacity building & training,
- · research, documentation and
- policy advocacy in the field of disaster management.

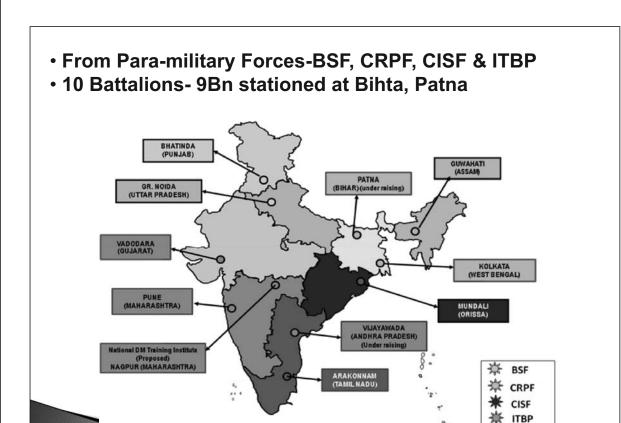
10. NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

• National Disaster Response Force constituted for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster.

Control & direction

- The general superintendence, direction and control of the Force shall be vested and exercised by the NDMA
- Command and supervision of the Force shall vest in an officer to be appointed by the Central Government as the Director General of the NDRF
- A Specialist Response Force with
- High skill training
- State of the art equipment
- A Multi Disciplinary, multi skilled, high tech force for all types of disasters capable of insertion by Air, Sea & Land





Cont.....

- Acquire and continually upgrade its own training and skills
- Impart basic and operational level training to State Response Forces (Police, Civil Defence and Home Guards)
- Assist in Community Training & Preparedness
- · Liaison, Reconnaissance, Rehearsals and Mock Drills.
- Proactive deployment during impending disaster situations
- Specialized Response

11. NATIONAL POLICY, 2009

- •Holistic and integrated approach towards disaster management with emphasis on building strategic partnerships at various levels.
- These include:
- Community Based Disaster Management, including last mile integration of the policy, plans and execution
 - Capacity development in all spheres
 - Consolidation of past initiatives and best practices
- Cooperation with agencies at National and International levels
 - Multi-Sectorial synergy

Objective:-

- Promoting a culture of prevention, preparedness and resilience at all levels through knowledge, innovation and education.
- Encouraging mitigation measures based on technology, traditional wisdom and environmental sustainability
- Mainstreaming disaster management into the developmental planning process
- Establishing institutional and techno-legal frameworks to create an enabling regulatory environment and a compliance regime
- Ensuring efficient mechanisms for identification, assessment and monitoring of disaster risks
- Ensuring efficient response and relief
- Undertaking reconstruction as an opportunity to build disaster resilient structures
- Promoting a productive and proactive partnership with the media for disaster management.

12. FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

- Constitution of the following fund at various levels by Central and State Governments
- Response fund made available to Executive Committees
- Mitigation Fund to be made available to Authorities

National Level

National
Disaster
Response Fund
National
Disaster

Disaster Mitigation Fund

State Level

State Disaster Response FundState Disaster Mitigation Fund

District Level

- District Disaster
 Response Fund
- DistrictsDisasterMitigation Fund

13. OFFENCES AND PENALTIES

Punishments for

- Obstruction
- False claim
- Misappropriation of money or material
- False warning
- Offences by departments of government
- Officer in-charge shall be held guilty and liable for punishment
- Penalty for contravention of any order regarding requisitioning
 - Offences by companies

14. MISCELLANEOUS

- Prohibition against discrimination
- Powers to be made available for search and rescue
- Making or amending rules in certain circumstances
- Power of requisition of resources, provisions, vehicles for rescue operation.
- Payment of compensation
- Direction to media for communication of warnings
- Authentication of orders
- Delegation of powers
- Annual report



आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 : संस्थाएं

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की संरचना, कर्तव्य एवं दायित्व:





कृष्ण कुमार झा उप समादेस्टा, राज्य आपदा मोचन बल, बिहार

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: (NDMA)

संरचना:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(I)के तहत केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन किया है।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा अधिकतम 9 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष उपरोक्त नामित सदस्यों मे से किन्हीं एक को उपाध्यक्ष पदनामित कर सकते हैं।

- अध्यक्ष की अनुमित से राष्ट्रीय प्राधिकरण की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जाती है।
- कार्यों के सम्पादन हेतु केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को पदाधिकारीयों कर्मचारीयों / सलाहकारों की सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति :

- प्राधिकरण को उसके कार्यों के सहयता प्रदान हेतु अधिनियम की धारा 8(1) के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया है।
- गृह विभाग के सचिव पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- 14 विभागों/ मंत्रालयों यथा केंद्र सरकार के कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विदयुत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं तकनीकी,अंतरिक्ष, दूरसंचार, नगर विकास, जल संसाधन मंत्रालयों / विभागों के सचिव तथा चीफ ऑफ इंट्रीग्रेटेड स्टाफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य होतें हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति : की अधिसूचना

अधिसूचना नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006 का.आ. 1616(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतर्द्धारा एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन करती है जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यो को करेगी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे :--(i) सचिव, गृह मंत्रालय (जिनके पास आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण है) (ii) सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य (iii) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य (iv) सचिव, रक्षा मंत्रालय (v) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग -सदस्य (vi) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय –सदस्य (vii) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग –सदस्य (viii) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य (ix) सचिव, विद्युत मंत्रालय (x) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग -सदस्य (xi) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य (xii) सचिव, अंतरिक्ष विभाग -सदस्य (xiii) सचिव, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (xiv) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास विभाग –सदस्य (xv) सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य (xvi) चीफ ऑफ इॉटेग्रेटिड डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी

राष्ट्रीय प्राधिकरण के शक्तियाँ एवं कृत्य:

- अधिनियम के धारा 6(1) के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदाओं मे समयबद्ध एवं प्रभावी रेस्पान्स सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन की नीतियाँ, योजनाओं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के निरूपण के लिए उत्तरदायी है।उपरोक्त के अलावा राष्ट्रीय प्राधिकरण निम्न कार्य करेगा:
- आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना,
- राष्ट्रीय योजना को अनुमोदित करना,

- भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गईं योजनाओं को अनुमोदित करना,
- राज्य योजना बनाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करना,
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करना,

- आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना,
- आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना.
- आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य आवश्यक कदम उठाना.

- आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य आवश्यक कदम उठाना.
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करना,

- आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देशों की अनुशंसा करना
- आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण की चुकौती में या रियायती शर्तों पर ताजा ऋण के अनुदान के लिए राहत की अनुशंसा करना।

2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :

संरचना:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 (I) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को "राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" का गठन करना है।
- बिहार सरकार ने 6 नवम्बर 2007 को अधिसूचना संख्याः 3439 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है।

- राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- अधिकतम ८ सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जा सकते हैं, जिसमें एक को मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष पदनामित किया जाएगा।
- प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य सचिव को नामित किया गया है जो प्राधिकरण के पदेन सदस्य होते हैं।

- राज्य प्राधिकरण की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से बुलाई जाती है।
- कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण को पदिधकारीयों / कर्मचारीयों / सलाहकारों की सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।

राज्य कार्यकरिणी समिति :

राज्य प्राधिकरण को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने,
 प्राधिकरण द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार गतिविधियों के समन्वय एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम की धारा 20(I) के तहत राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है।

- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: 3449 दिनांक 6 नवम्बर 2007 द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति गठित है।
- मुख्य सचिव राज्य कार्यकरिणी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।
- इस समिति के 4 अन्य सदस्य हैं: विकास आयुक्त तथा वित्त, आपदा प्रबंधन एवं जल संसाधन विभागों के सचिव / प्रधान सचिव।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: शक्तियां और कृत्य:

अधिनियम की धारा 18 (1) के अनुसार प्राधिकरण राज्य मे आपदा प्रबंधन की नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाने हेतु उत्तरदायी हैं। उपरोक्त के अलावा राज्य प्राधिकरण अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार निम्न कार्य करेगी:

- राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना।

- राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
- आपदा की रोकथाम के लिए उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से या उनके प्रभावों का शमन करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनके विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागू किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का निर्धारण करना।
- शमन (mitigation) और तैयारी के उद्देश्य के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना।

- राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए योजना को पुनर्विलोकन करना और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना।
- अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना :

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत तैयार की गयी राज्य आपदा प्रबंधन योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस राज्य योजना में आपदा के विभिन्न स्वरूप द्वारा राज्य मे प्रबणता, आपदा के निवारण और शमन के लिए उपाय, राज्य के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व का समायोजन किया गया है।

3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA):

- देश में त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके तथा आपदा से पीड़ितों को अतिशीघ्र राहत दिलाई जा सके।
- अधिनियम की धारा 25 (1) के अनुसार बिहार के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

DDMA गठन की अधिसूचना :

बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसचना

संख्या: 1प्रा0आ0-16/2008 5 0 9 /आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 13/6/**०**8

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए "जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सींपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य हाँगे:-

(i)	जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्त्ता	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष जिला परिषद	-	सह-अध्यक्ष
(iii)	पुलिस अधीक्षक	-	पदेन सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	_	पदेन सदस्य
(v)	उप विकास आयुक्त	-	पदेन सदस्य
(vi)	अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	-	पदेन सदस्य
(vii)	जिला के वरीयतम अभियंता	-	पदेन सदस्य

- (2) अपर समाहर्त्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

DDMA की शक्तियां और कृत्य:

- जिला स्तरीय विभिन्न प्राधिकारों एवं स्थानीय निकायों
 को आवश्यकतानुसार आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के
 उपाय करने की दिशा निर्देश देना।
- जिला स्तर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं के जिला स्तर पर कार्यान्यवन हेतु मार्गदर्शन देना।

- सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए आपदा प्रबंधन योजनाओं का जिला स्तर पर कार्यान्यवन कर समन्वय करना।
- आपदा की रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से या उनके प्रभावों को शमन करने के लिए राज्य सरकार के जिला स्तरीय विभिन्न विभागों को उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागू किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का निर्धारण करना एवं कार्यान्यवन कर अनुश्रवन करनाआदि।

4. राष्ट्रीयआपदा मोचन बल (NDRF):

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 8 के तहत किसी आपदा की आशंका की संभावना के विशेषज्ञतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन किया गया है।
- 14 फरवरी 2008 को देश में NDRF के 8 बटालियन की गठन की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की गयी।

एनडीआरएफ: गठन के स्वरूप

- महानिदेशक के नेतृत्व में वर्तमान में 12 बटालियन के रूप में विभिन्न आपदा प्रवण इलाके वाले राज्यों में तैनात।
- NDRF वस्तुतः विभिन्न पैरा-मिलिट्री फोर्स से प्रतिनियोजन
 पर ली गयी कार्मिकों के द्वारा गठित की गयी है।
- एक वाहिनी में 1149 कार्मिक होते है, जो विभिन्न आपदाओं
 में तुरंत रिसपोन्स के लिए अत्याधुनिक यंत्रो से लैस रहतें हैं।

- बिहार में पटना (बिहटा) मे NDRF की 9वीं बटालियन हैं, जिसकी 1-1 टीम सुपौल और रांची में है।
- वर्तमान समय मे NDRF के कार्मिक आपदा प्रबंधन के विभिन्न स्वरूपों की तकनीकी प्रशिक्षण ले कर NDRF में 7 वर्ष तक सेवारत रहते हैं।
- आधुनिक संचार संसाधनों के सुसज्जित 45 सदस्यों के टीम में स्वान दस्ता के अलावा इंजीनीयर और चिकित्सकों का दल भी रहता है।

REQUISITION FOR DEPLOYEMENT

- NDRF की राज्य में केंद्र के द्वारा तैनाती राज्य सरकार के मांग पर आपदा की LEVEL-3 के स्थिति मे अनुमित दी जाती है, किन्तु जान-माल के रक्षा हेतु आपदा पुर्व भी तैनात की जाती है।
- NDRF की आवश्यकता महसूस होने पर जिला-पदाधिकारी के मांग पर आपदा स्थिति के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा केंद्र से NDRF की समुचित टीमों की मांग की जाती है।

5. राज्य आपदा मोचन बल :SDRF

- गृह मंत्रालय भारत सरकार का परामर्श है कि प्रत्येक राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु NDRF की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना की जाय।
- तदनुसार प्रकृतिक आपदाओं के समय बचाव व राहत के लिए त्विरत कारवाई करने हेतु बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा रिस्पांस बल का गठन आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या: 698, 16 मार्च 2010 द्वारा किया गया है।

SDRF के गठन की अधिसूचना :

।। <u>संकल्प</u> ।। संख्या-2/स्था0-17-26/2008/<u>698</u>/आठप्र0, पटना-15, दिनांक- 16/3/2°/°

विषयः आपदा प्रबंधन हेतु राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) की एक बटालियन गठित करने एवं बटालियन के लिए विमिन्न पदों की स्वीकृति।

आपदाओं की दृष्टि से बिहार देश का सर्वाधिक आपदा प्रवण राज्य है। अपनी विशेष भौगोलिक संरचना के कारण बिहार राज्य प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से आक्रांत होता रहता है। राज्य एवं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षापात के कारण उत्तर बिहार की नदियों में आनेवाली बाढ़ से न केवल सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति एवं संसाधनों का भारी नुकसान होता है, बल्कि मानवजीवन एवं पशुधन की क्षति होती है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। इसी प्रकार भूगर्भीय स्थिति के कारण भी बिहार राज्य की स्थिति भूकम्प के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। राज्य के 38 जिलों में से 33 जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन V, IV एवं III में स्थित हैं, जहाँ भूकम्प का खतरा सदैव बना रहता है। चक्रवात की दृष्टि से भी राज्य के 31 जिले High Damage Zone में आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में, खासकर उत्तर बिहार में, आगजनी की घटनाएँ होती रहती हैं। राज्य में प्राकृतिक आपदाएं खासकर बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाएं, आने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सेना अथवा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स (NDRF) की सेवा (बोट सहित) लेने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जल प्लावित क्षेत्रों में घिरी आबादी को अविलंब सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके एवं तत्काल राहत सामग्रियाँ उपलब्ध करायी जा सकें।

 राज्य के किसी भू—भाग में आपदाओं के आने पर बचाव एवं राहत तथा
 आपदा से कुप्रभावित आवश्यक सेवाओं को शीघातिशीघ बहाल करने के दृष्टिकोण से राज्य में एक प्रशिक्षित. साधन सम्पन्न एवं कशल बल की आवश्यकता है जो

SDRF के वर्तमान स्वरूप:

- SDRF की 6 कंपनी हैं जिसमे कुल 18 टीमें होगी। प्रत्येक स्पेलिस्ट रेस्पोंस
 टीम में 45 सदस्य होतें हैं।
- 18 श्रेणी की भर्ती रक्षा सेवा / पैरा मिलिट्री सेवा के सेवानिवृत कर्मी को सविदा के आधार पर एकमुस्त/ मानदेय के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है।
- इन पदो पर प्रति नियुक्ति के आधार पर बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP)/
 केंद्रीय अर्ध सैनिक बल के जवानो/ अधिकारियों की सेवाएं ली गयी है।

- SDRF के बटालियन के प्रधान समादेष्टा होते हैं।
- आपदा राहत व बचाव के समय बेहतर तालमेल के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन) की प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उनकी सेवाएँ SDRF द्वारा ली जाएंगी।
- राज्य सरकार द्वारा SDRF के वर्तमान स्वरूप को बढ़ाकर 50 टीम तक करने का निर्णय लिया गया है।

धन्यवाद !!







BIHAR DISASTER RISK REDUCTION ROADMAP (2015-2030)

Development process, Structure, Silent Features and Specific Actions for Departments

Dr. Gagan, PGRO, Mahanar, Vaishali General Administration Department

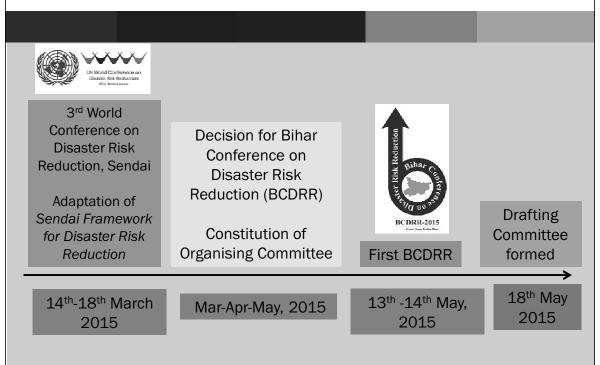
Mkjdkjh [kt kus i j vki nk i kfMrksdk i gyk gd gS^

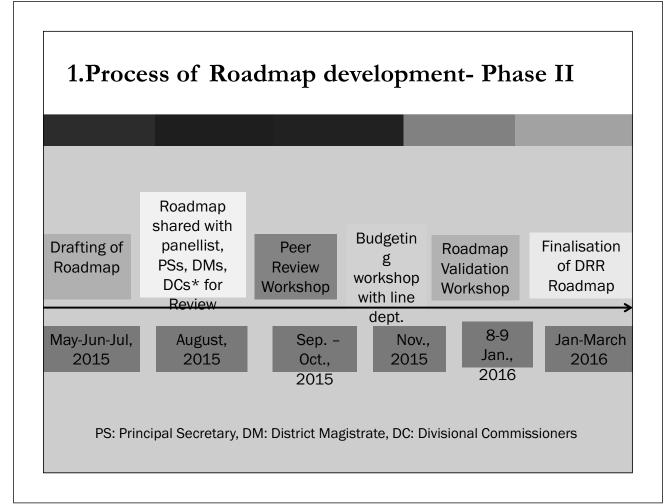
& Jh uhrh'k dekj] ekuuh; eq; e=h] fcgkj] mn?k\Vu Hk'k k i Fke fcgkj vki nk t kf[ke U; whdj.k l Fesyu] 13&14 eb# 2015 i Vuk

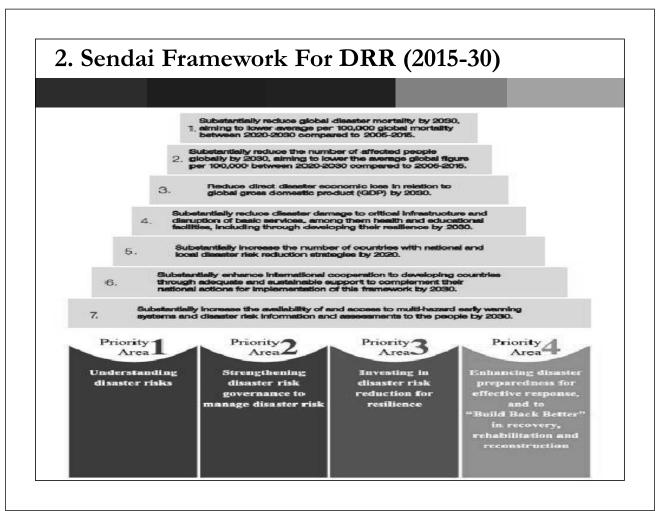
Plan of Presentation:

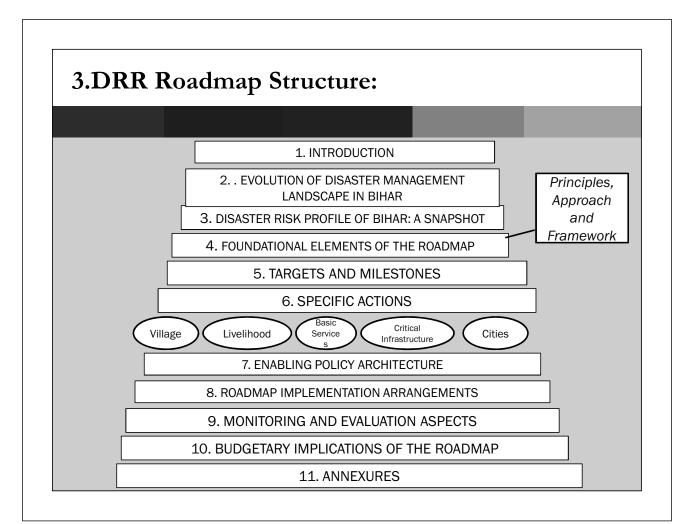
- 1. Process of Roadmap Development
- 2. Sendai Framework for DRR (2015-30)
- 3. DRR Roadmap structure
- 4. Disaster Profile of Bihar
- 5. Salient features of Roadmap
- 6. Specific Action for Departments

1.Process of Roadmap development- Phase I (From Sendai to Patna)









4.DISASTER PROFILE OF BIHAR Bihar is prone to multi-hazards like: Recurring Floods: 28 districts out of 38 are Earthquake: 07 dist. in Seismic zone V prone to floods, Bihar accounts for 17% of (Highest), 21 dist in zone IV (High). Faced EQ the flood-prone area and 22% of the floodin 1934, 1988 & 2015. 63 people lost their affected population in India life in April, 2015 EQ in Bihar Drought: Southern part of the state (13) High Speed Winds/ Cyclonic storms: 27 dist.) suffer from drought, Bihar faced dists out of 38 are fully affected by high moderate to severe drought in 2002, 2007, speed winds of 47 m/s intensity. Tornado 2008, 2009, 2010, 2011 & 2013 killed 59 people in April, 2015 in Bihar Severe Cold wave, Heat Wave, Lightning, Village fires in summer: fire hazard of varying intensity covers all the 38 districts of Hailstorm Health emergencies i.e. Acute Encephalitis Syndrome (AES) Climate Change Changing Climate- showing signs

DISASTER PROFILE......CONT.

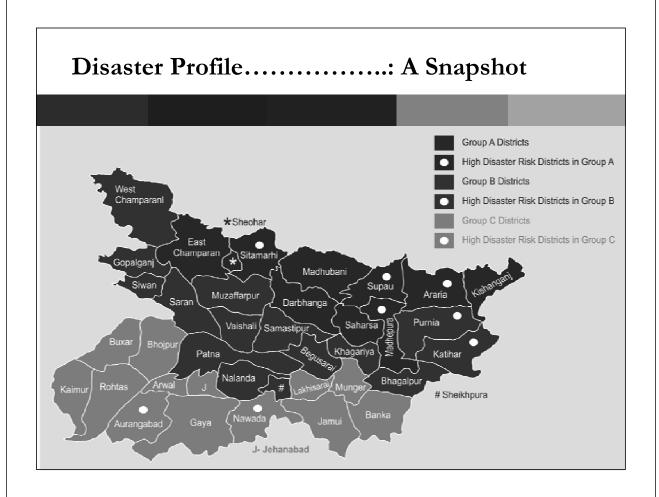
List of Notified Disasters in Bihar

Ministry of Home Affairs, Government of India (GoI) notified the following list of 'natural calamities':

- Avalanche, cloud burst, **cold wave**, **cyclonic storms**, **drought**, **earthquake**, **fire**, **flood**, **hailstorm**, landslide, tsunami, and pest-attack.

GoB notified following as state specific local disasters:

Lightning, Heat Wave, Excess Rainfall, Unseasonal and Heavy Rain, Boat Tragedies, Drowning (rivers, ponds and ditches), Human Induced Group Accidents such as Road Accidents, Airplane Accidents, Rail Accidents, Gas Leakage.



* Disaster Profilecont.

Group	Profile	Constituent Districts
Group A Districts (10)	Mainly Flood Prone and Earthquake Zone V	Araria, Drabhanga, East Champaran, Kishanhanj, Madhepura, Madhubani, Saharsa, Sheohar, Sitamarhi, and Supaul
Group B Districts (18)	Mainly Flood Prone and Earthquake Zone IV	Banka, Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Gopalganj, Katihar, Khagariya, Lakhisarai, Muzaffarpur, Nalanda, Patna, Purnia, Saran, Samastipur, Sheikhpura, Siwan, Vaishali, and West Champaran
Group C Districts (10)	Mainly Drought Prone and Earthquake Zone III	Arwal, Aurangabad, Buxar, Gaya, Jamui, Jehanabad, Kaimur, Munger, Nawada, and Rohtas

All Districts in Groups A, B and C prone to fire, hail storm, heat wave, cold wave, lightning, road accidents and stampede etc.

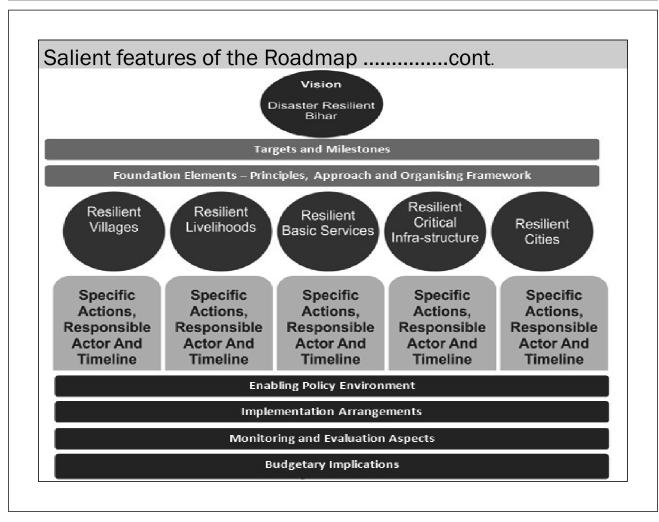
5. Salient features of the Roadmap:

1. 15 Guiding Principles:

- · Primacy of rights of at-risk people and communities,
- · Participation of and action by at-risk communities,
- · Risk realisation,
- Polycentric Governance
- Partnerships
- Coherence and consistency across policies, programs and plans
- · Inclusive DDR,
- · Right to safe and secure environment
- Culture of preparedness
- Build back better

Salient features of the Roadmap.....

- 2. Approach of Implementation:
 - · Multi-hazard focus
 - Phasing
- 3. Framework:
 - Resilience as the organising principle, goal and means
 - FIVE components communities and systems
 - Resilience lies at the core of the Roadmap: Resilience is the goal that the activities in the Roadmap seek to lead Bihar towards a "Resilient Bihar".
 - ➤ "Resilience" denotes identification, assessment and addressing of the hazard risk and preservance of ecosystem.



Salient features.....cont.....

TARGETS:

- 1. Lives lost due to natural disasters in Bihar would be reduced by 75% of the baseline level by 2030.
- Lives lost due to transportation related disasters (viz. road, rail and boat accidents) in Bihar would be substantially reduced over baseline level by 2030.
- 3. People affected by disasters in Bihar would be reduced by 50% of the baseline level by 2030.
- 4. Economic loss due to disasters in Bihar would be reduced by 50% of the baseline level by 2030.

Salient features Contd.

- The Roadmap set out actions to be taken at the state, district, city and village levels by various agencies and Govt. Departments
- It envisages great roles of BSDMA and Disaster Management Authorities (DDMAs) and tasks the DDMAs to prepare Village Disaster Management Plans (VDMPs)
- It also tasks Urban Local Bodies to prepare City Disaster Management Plans.
- The activities to be undertake under the Road have been clearly assigned to various Government Departments and agencies.
- For every activity the nodal and supporting department/agency has been identified with a define time line.
- The time lines are short, intermediate and long term each of 5 years duration.

Salient features Contd.

- The roles, responsibilities and activities assigned to the government departments and agencies have been woven around the FIVE PILLARS.
- Realising the challenges ahead in creation of a Resilient Bihar, the road map envisages
- provisions enabling policy architecture,
- o implementation arrangements,
- o robust monitoring & evaluation mechanism and
- budgetary

Salient featurescont. MILESTONES:

BY 2020:

- 1. Baseline status for each of the four targets is developed.
- 2. Training of Engineers, Architects, Masons etc. for safe construction of projects and buildings completed.
- 3. Structural safety audits of all government offices/ buildings and infrastructure (such as Secretariat, Collectorates, SDO/Block/Anchal Offices, Police Offices and Stations, Schools, Hospitals, Panchayat Bhawans, Anganwadi centres etc.) is completed and corrective measures initiated.
- 4. Safe construction of all major Government projects and building is initiated.
- Emergency Support Functions are notified and made operational with fullyfunctional Emergency Operations Centres (EOCs) at state and district levels.
- 6. Structural safety of all commercial buildings (such as malls, cinema halls and other public places of mass gathering) is ensured.
- 7. Comprehensive multi-hazard risk analysis (current and emerging disaster risks) and incorporating in annual plans and PIPs of all line departments and annual plans of PRIs and ULBs.

Salient featurescont. MILESTONES:

BY 2020:

- 8. Service Delivery Continuity Plans (SDCPs) and Infrastructure Continuity Plans (ICPs) for all basic services & critical infrastructures to ensure department functions return to 'business as usual' in the quickest time.
- 9. An effective Early Warning System (EWS) is established, wherein all villages and cities in Bihar have systems for early warning information reception, dissemination and taking up immediate good enough pertinent action.
- DDMAs strengthened with resources, mandates and capacities for playing an integral role in disaster risk reduction decision making at the district level.
- 11. Communities understand and practice 'do's and don'ts' during disaster situations as a result of a state-wide public awareness and education campaign launched at all levels.
- 12. Building bye-laws incorporating safe construction in all urban areas are approved.
- 13. Communities are encouraged and a policy regime is developed to enforce safe construction in rural areas.

Salient featurescont. MILESTONES:

BY 2025:

- Corrective measures, including retrofitting, for ensuring structural resilience of all government offices and social infrastructure are completed.
- 2. A system for Risk Informed Development Planning (RIDP) is adopted and operational in the state at all levels of planning.
- 3. All PRIs and ULBs are adequately empowered through funds, functions and functionaries to ensure resilience.
- 4. Communities in all villages and cities regularly monitor current and emerging disaster risks, including underlying risks, and assert for measures to be taken to address the same.
- 5. Platforms and mechanisms are institutionalized across Bihar for effective learning and sharing on DRR planning, implementing and drawing learning.

Salient features	cont.
MILESTONES:	

BY 2030:

- 1. Policies and practices for agriculture and other livelihood related risk transfer, sharing, and compensation are adopted by agriculture and small industry based livelihoods systems in Bihar.
- 2. Rural and urban habitat planning processes like land zoning, town and city development planning take into account existing and emerging disaster risks.
- 3. All existing and new public and private buildings in Bihar are structurally safe from a multi-hazard perspective.

6.SPECIFIC ACTIONS FOR DEPARTMENTS

Specific Actions for Departments

General points for all departments/ agencies:

- Specific Actions has been arranged department/ agency wise.
- Nodal department/ agency will lead the activities whereas supporting departments would provide requisite support to nodal department
- Level of action (State, District, Block, and Gram Panchayat or Urban area) and the timeline (short-term, medium term and long-term) for each specific activity has been identified.
- Each department/ agency has to make budgetary provisions for the assigned activities in their annual budget; DMD can supplement funds if some of the activities can't be budgeted by the departments/ agency.

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

1.Building Construction Department

- ✓ Ensure that all new constructions of public buildings are green, differently able-friendly and disaster resistant with water-harvesting facility and universal design
- ✓ RVS/Safety Audit of existing public buildings and Retrofitting of buildings/making the buildings disaster resistant and differently abled-friendly

2. Water Resources Department

- ✓ Identify and prioritize high flood risk prone villages/cities and develop scenario based inundation maps for planning, preparedness and response
- ✓ Augmentation of irrigation potential in drought prone districts

3. Rural Development Department

- Encourage beneficiaries of Govt housing projects to construct disaster resistant houses
- Ensure construction and renovation of water conservation and water harvesting structures in drought prone districts under MGNREGA
- ✓ Deepen the public water bodies such as, village ponds and other natural water and drainage systems

4. Panchayati Raj Department

- ✓ Put in place a policy regime to encourage safe house construction/retrofitting in villages
- ✓ Awareness campaign for safe house construction in villages
- Capacity building of PRIs to assess and address hazard risks

25

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

5.Agriculture Department

- ✓ Developing Resilience Index for agricultural operations in the context of climate change induced disasters
- Promotion of soil and water conservation in drought prone districts
- Promotion of horticulture activities
- ✓ Developing flood/drought resistant seeds
- Capacity development of farmers to assess and address risks in farm sector

6 & 7.Road Construction/Rural Works Departments

- Conduct road safety audit in terms of floods and ensure that all SHs/MDRs/Village Roads constructed henceforth are flood resistant in flood prone districts
- Ensure that all roads passing through habitations are pedestrian and slow moving vehicle-friendly to prevent accidents

8. Transport Department

- Ensure boat safety through boat registration and fitness checking of boats and safety equipments
- ✓ Enforcement of boat safety rules
- ✓ Rigorous implementation of Road Safety Roadmap

9. Social Welfare Department

- Ensure that AWC have sufficient first aid kits and other materials from a multi-hazard point of view
- Maintain and update list of vulnerable population(children, infirm, old, pregnant and lactating mothers) for taking their proper care during disasters
- Develop a plan to ensure continuation of the provisions of nutrient materials to malnourished children at the AWCs during disaster situations
- ✓ Develop a contingency plan and ensure running AWCs in Mega Shelter Camps

27

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

10. Animal and Fisheries Resources Department

- ✓ Establish emergency services and mobile emergency response units in Vet hospitals
- ✓ Develop a State Animal DM Plan and be ready with contingency plans for animal protection during disasters
- Capacity building of Vet doctors and staff to assess and address animal hazard risk

11. Cooperative Department

- ✓ Augment the coverage of crop insurance and ensure timely processing of insurance claims by the IPs
- ✓ Sensitize cooperative community institutions/groups on disaster risk analysis and measures for risk avoidance, transfer, sharing group activities and claiming compensation

12. Food and Consumer Affairs Department

- ✓ Ensure timely procurement of agriculture produce
- Augment and create more capacities for storage of agricultural produce
- ✓ Promote adequate stocking of PDS items in FCI/SFC godowns for the flood season in the flood prone districts and ensure distribution of the same to the PDS dealers before the onset of flood season
- Ensure all new departmental constructions are disaster resistant and deficiencies in the existing facilities are corrected

13. Jeevika

- ✓ Develop annual status report on livelihood clusters and measures taken for risk management
- ✓ Document and share good practices/case studies related to resilient livelihoods

29

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

14. Environment and Forest Department

- ✓ Undertake tree plantation in flood prone districts
- ✓ Undertake anti-erosion works along embankments/roadside though soil binder/leguminous grasses in consultation with concerned departments
- ✓ Implementation of State Action Plan on Climate Change
- Assessing and addressing factors causing air pollution and environmental degradation

15. Labour Resources Department

- ✓ Undertake/strengthen skilling program of youth and women in market driven trades
- Ensure preparation of DM plans by establishments/factories as per Factories/DM Act for Industrial safety

16. Finance Department

Develop menu of products and establish procedures for provision of soft loans, loan waivers/re-scheduling, working capital and capital costs to primary producers, traders and secondary producers so as to rebuild their assets and restart livelihood activities after a disaster event

17. Urban Development Department

- Enforcement of building by-laws to ensure safe construction of new buildings in urban areas
- RVS/Safety audit of all commercial buildings in the urban areas and ensuring remedial measures based on the findings
- Undertake comprehensive analysis of flooding and water logging risks, land use patterns, natural drainage patterns and water/drainage management systems in urban areas and take corrective measures based on the analysis

31

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

18. Home Department (Fire Services)

- ✓ Develop a fire safety and evacuation plan for public and commercial buildings, especially in health care facilities and schools
- Procurement and deployment of appropriate fire fighting equipments and fire tenders including protective gears
- Coordinate with Govt and local authorities for availability of water supply and other firefighting materials and equipments in all public and commercial buildings
- ✓ Undertaking community awareness programs on fire safety

19. Health Department

- Ensure that all new constructions of the health facilities are green, differently able-friendly and disaster resistant
- ✓ Conduct RVS/Safety audit of health facilities and undertake corrective measures based on the findings
- Develop resilience index and DM plans for all health facilities, including SOP for mass casualty mgt, and conduct regular mock drills as per DM plans
- Constitute and train Quick Medical Response Teams (QMRTs) and develop a SOP for their deployment

20. PHED

- Ensure that potable water is available to the affected population during disasters and situations of drinking water crisis
- Ensure that installation of piped water supply facilities and construction of toilets under "Nischay" programs are disaster resistant, disabled- and senior citizen-friendly
- Develop DM plans for Water and Sanitation (WASH) related facilities

21. Education Department

- Ensure that all new constructions of the Govt. educational facilities are green, differently able-friendly and disaster resistant
- Conduct RVS/Safety audit of educational facilities and undertake corrective measures based on the findings
- ✓ Implementation of MSSP with technical support of BSDMA

33

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

22. IPRD

 Public awareness campaigns for prevention/mitigation of disasters in collaboration with DMD/BSDMA and other departments

23. IT Department

✓ Develop and implement a contingency plan for the resilience of telecom and IT sector in the State

24. Energy Department

- ✓ Develop a resilient Index and ensure the resilience of all power infrastructure, new and existing in accordance with that index
- Make it mandatory to carry out a Risk Impact Analysis of a proposed installation/ construction before execution in flood prone and seismic zone V / III districts
- ✓ Develop power supply continuity plan during disasters and conduct mock drills for preparedness
- Awareness generation regarding risks associated with hightension power lines and taking corrective measures to prevent snapping thereof

25. Minor WRD

- Make tube wells functional in drought prone districts
- Undertake renovation of Ahar-Pyne system in drought prone districts for water conservation/ recharge and irrigation

26. DMD

- Compilation of baseline data on mortality/economic losses/population affected by various disasters
- ✓ Establishing RISU with full time technical experts and staff
- ✓ Establishment of SIDM
- ✓ Updation /formulation of SOPs for different disasters
- Community awareness through mock drills
- ✓ Strengthening of SEOCs and operationalisation of DEOCs
- Strengthening of Early Warning System with a view to ensure last mile connectivity
- Providing support to various Govt. Departments/agencies for implementation of Roadmap

35

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

27. BSDMA/DDMAs

(a) DDMAs

- Preparation of DDMPs and coordinating and monitoring its implementation
- ✓ Preparation of VDMPs
- ✓ Enforcement of Boat Safety/Road Safety rules and provisions
- Capacity building and Preparedness to respond to disaster situations

(b) BSDMA

- ✓ Undertake review of SDMP and coordinate its implementation
- ✓ Implement MSSP in collaboration with Education Department
- ✓ Training of Engineers/Architects/Contractors/Masons (26,000) in Earthquake resistant construction technology
- Public awareness and capacity building of stakeholders for prevention/mitigation / response of various disasters

BSDMA...Contd

- ✓ Provide required assistance to Municipal authorities to prepare City Disaster Management Plans for all cities
- Provide required assistance to the headquarter offices of all departments to prepare ODMPs and develop guidelines for preparation of ODMPs of their attached and subordinate offices
- Conduct regular mock drills in health facilities, Govt offices, commercial buildings and big apartments in collaboration with DMD/Fire Services/ULBs/DDMAs /NDRF/SDRF and other concerned departments
- ✓ Provide technical support, wherever necessary, to various departments/agencies in the implementation of the DRR Roadmap

37

SPECIFIC ACTIONS.....CONT.

28. Industries Department

- ★ Develop a resilience index and/or quality standards pertaining to hazardous industries
- ★ Encourage industries to development Infrastructure continuity plan for ensuring backup and regaining functionality of the infrastructure

29. BIPARD

- Build the capacities of civil society organizations and other community based institutions on Farm Field Schools, Context specific cropping packages, risk analysis and livelihood basket diversification
- ★ Capacity building of GPs and ULBs in assessment of livelihood opportunities, implementation and monitoring of livelihood assessments and compensation provisions

30. Revenue and Land Reforms Department

- * Make all public water bodies including rivers and natural drainage systems encroachment free and coordinate with development departments for their renovation/deepening
- ★ Wherever possible, the land of the water bodies should not be permanently settled with any person/department

THANKS.....

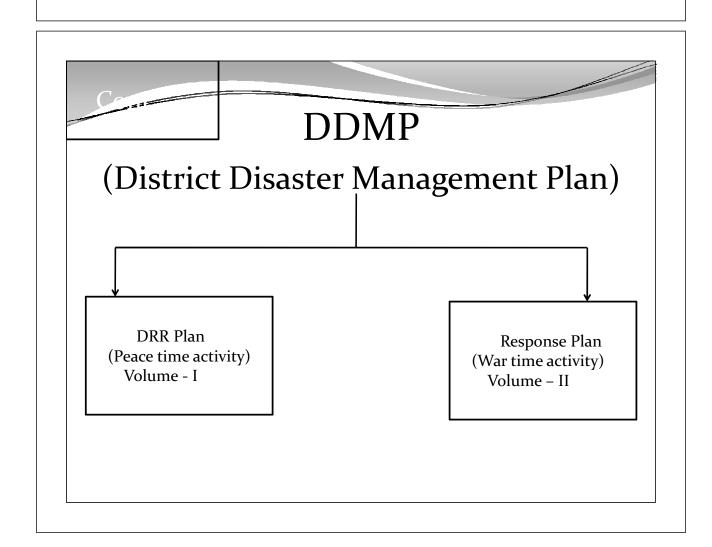
District Disaster Management Plan

Content:

- 1.DDMP An Introduction
- 2.Components of DDMP
- 3. Responsibilities of DDMA for DDMP (As per DM Act 2005)
- 4. Vulnerability profile of Bihar (Map presentation)
- 5.Comparision of preparation of DDMPs-Madhubani vs Supaul

1.DDMP - An Introduction

- DDMP stands for District Disaster Management Plan.
- **■**District Plan-Under Section 31 of Disaster Management Act, 2005
- ➤(1) There shall be a plan for disaster management for every district of the State.
- ➤(2) The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with the local authorities and having regard to the National Plan and the State Plan, to be approved by the State Authority.
- Section 30(2) (i) of DM Act says Mandate district authority to make a DM for the district including district response plan



2.Components of DDMP

- Sec. 31(2)&(3) of DM Act says -The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with the local authorities and having regard to the National Plan and the State Plan, to be approved by the State Authority and its components will be as follow:
- ➤ (a) The areas in the district vulnerable to different forms of disasters;
- ➤ (b) The measures to be taken, for prevention and mitigation of disaster, by the Departments of the Government at the district level and local authorities in the district;
- ➤ (c) The capacity-building and preparedness measures required to be taken by the Departments of the Government at the district level and the local authorities in the district to respond to any threatening disaster situation or disaster;

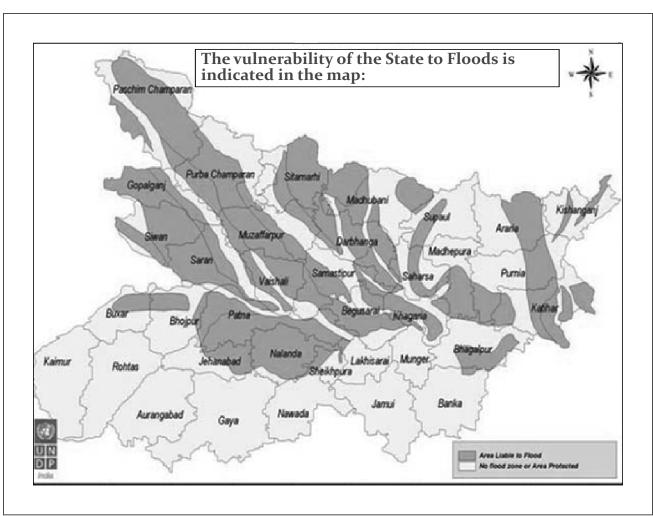
Cont....

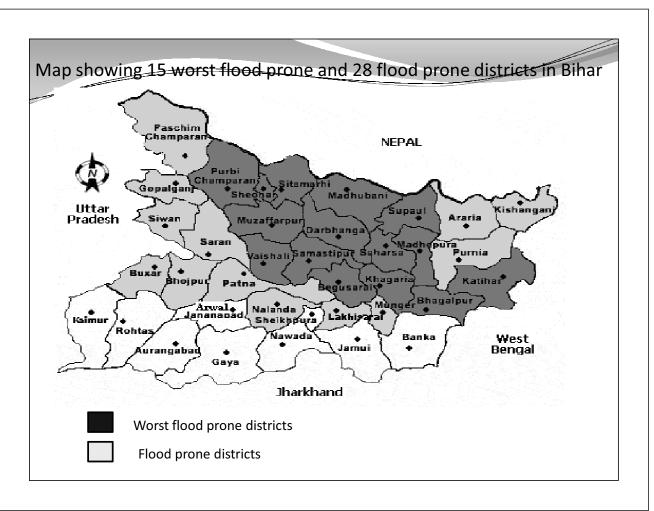
- ➤ (d) The response plans and procedures, in the event of a disaster will include -
- ❖(i) Allocation of responsibilities to the Departments of the Government at the district level and the local authorities in the district;
- ❖(ii) Prompt response to disaster and relief thereof;
- ❖(iii) Procurement of essential resources;
- ❖(iv) Establishment of communication links; and
- \diamond (v) The dissemination of information to the public;

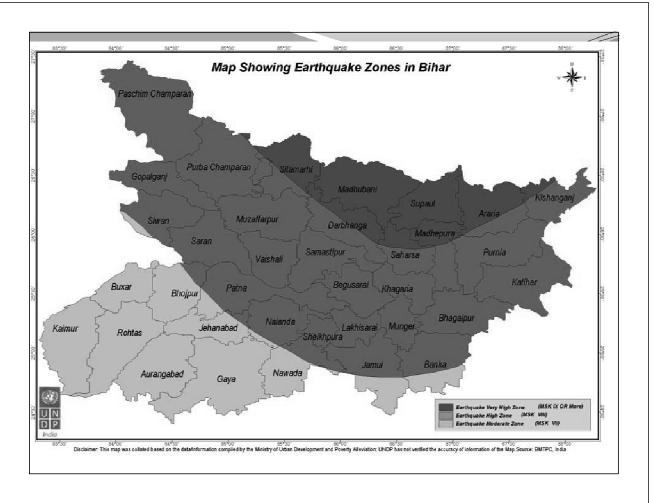
3. Responsibilities of DDMA for DDMP (As per DM Act 2005)

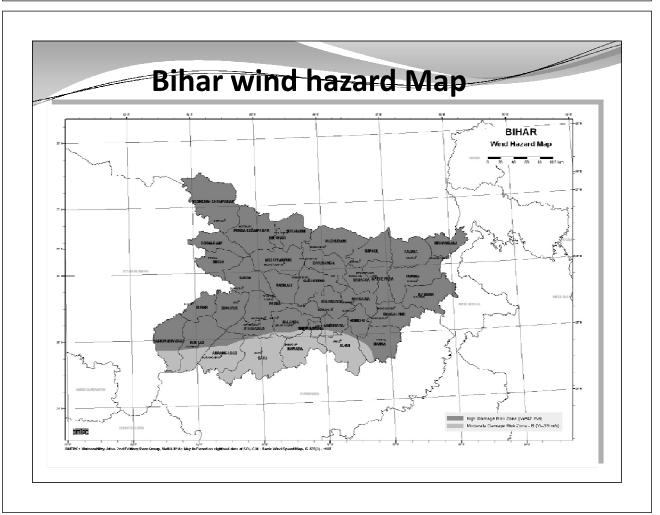
- DDMP shall be reviewed and updated annually.
- DDMP the District Plan shall be made available to the Departments of the Government in the district.
- District Authority shall also send a copy of DDMA.
- District Authority shall, review from time to time, the implementation of the plan and issues such instructions to different department of the Government in the district as it deemed necessary for the implementation there of;

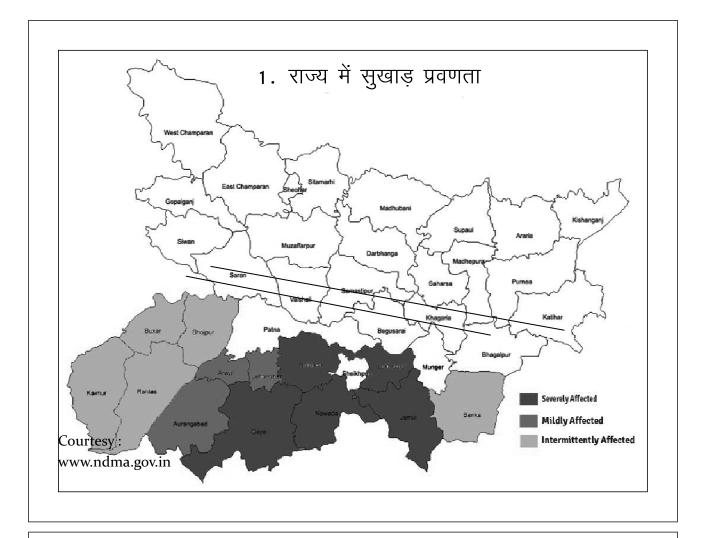
4. Vulnerability profile of Bihar











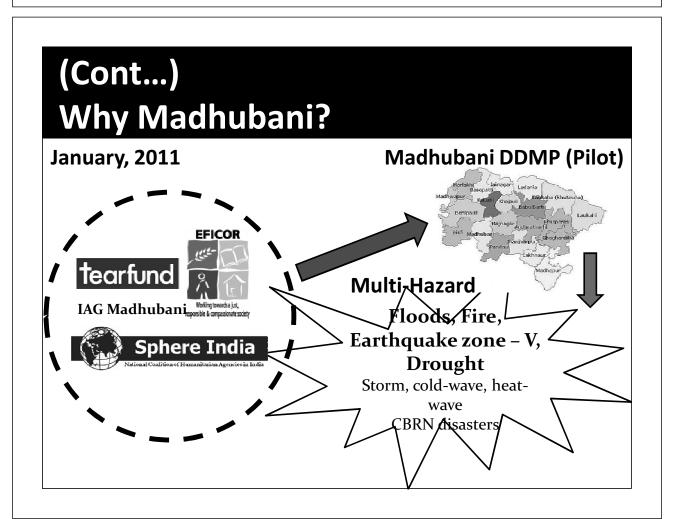
5.Comparision of preparation of DDMPs-Madhubani vs Supaul

Example –

- I. Madhubani District
- II. Supaul District

5(i) Why DDMP for Madhubani??

- Disaster Management Act 2005
 - Chapter IV, Clause 31(1)
 - Madhubani was the first district in Bihar for which DDMP was prepared in the year 2011.
- Gaps in existing DDMP
 - Lack of SOPs, ready materials
 - Poor participation (and ownership) of stakeholders
 - Lack of coordinated approach
 - Most plans were like directory/inventory



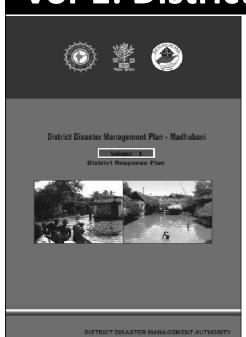
(Cont..) Different outputs

- 1. Vol-1: District Response Plan
- 2. Vol-2: DRR and Mitigation Plan
- 3. Vol-3: stake holder specific action plans
- 4. Vol-4: Checklists, formats and resource database
- 5. Process guideline



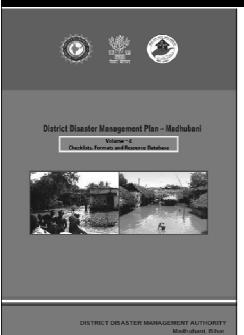


Vol-1: District Response Plan



- 1. Actions common to all disasters
 - 1. Actions on receipt of Early Warning
 - 2. Actions for Response Activation
 - 3. Actions for Relief and Response
 - 4. Deactivation of Response
 - 5. Recovery Actions
- 2. Specific contingency situation actions
 - 1. Floods
 - 2. Earthquake
 - 3. Drought
 - 4. Fire
 - 5. Crowd management
- Emergency Operations Centre (EOC)

Vol-4: Resource database, checklists & formats



- Important contact details
- Demographic and context details
- Resource details
- VULNERABILITY RELATED DETAILS
- DDMP ADVISORY BODIES
- LIST OF MAPS
- FORMATS AND QUESTIONNAIRE
- Checklists & references

Other key features

- 1. Guidance on how to use plan
- 2. Incorporation of feedbacks received from all levels
 - 1. NDMA (Shri Nand Kumar Ji, Hon'ble Member)
 - 2. BSDMA (Shri Anil Sinha Ji, VC)
 - & other key people
 - 3. BIPARD (Dr. Bala Prasad)
 - 4. UNDP, AIDMI & Other agencies & professionals



5(ii).Multi-hazards District Disaster Management Plan(Draft)-Supaul

Cont....

Contents of the presentation

- 1. Core Guiding Documents
- 2. Process activities
- 3. Understanding hazards, risk, and vulnerability
- 4. Response plan
- 5. Prevention, Preparedness, mitigation, recovery and reconstruction plan
- 6. Department wise training needs for capacity building
- 7. Feedbacks/ comments/ suggestions

Cont....

Core guiding documents

- 1. Disaster management Act, 2005
- 2. Bihar DRR roadmap,2016
- 3. State Disaster Management Plan
- 4. Bihar State action Plan on climate change
- 5. SoPs developed by the disaster management department
- 6. National action plan on children
- 7. Existing district response plan

Cont....

Review meetings with Supaul District Administration and BSDMA in last two year

Month	Meetings			
27.2.2016	Divisional level meeting with Vice chairman, BSDMA			
6.06.2016	District level meeting (with ADM disaster) for sharing DDMP for departmental feedback			
27.8.2016	Sharing of DDMP with Divisional Commissioner and DM for feedback			
23.12.2016	Final sharing of plan with district administration			
26.12.2016	Final submission of draft DDMP for BSDMA comment			
22.02.17	Review of DDMP with BSDMA			
5.8.17	Final approval from District administration			
7.10.17	Final review at BSDMA			

Cont....

Hazard, Risk , Vulnerability and Capacity

- 5 percent of gram panchayat taken in the district
- Total 10 panchayats was selected in the districts for community consultation
- In each community consultation male and female were consulted separately
- Community prioritized the risks as per its effectiveness
- 21 departments/ agencies are consulted





Cont...

Community and Departmental Consultations

		•	
Blocks	GP	Departments	Departments
Triveniganj	Barkhurwa	Agriculture	Food supply department
Basantpur	Banelipatti	Fire	Panchayati raj
Saraigarh	Dholi	PHED	Police
Bhaptiyahi Supaul	Telwa	Eastern kosi embankment (Birpur and Nrmali	NDRF and SDRF
Raghopur	Ramvishunpur	Transport	Rural development department
Marauna	Kadmaha	Health and ICDS	Road Construction Department
		Education	District disaster management Authority
Pratapur	Sirpur	Building construction	Water resources department
Chhatapur	Dehria	department	
Pipra	Vishunpur	Planning	Nagar Parisad
Kishanpur	Sonbarasa	Animal and fisheries department	Communication and public relation
		Power	

Cont...

Types of Hazards & Risks

(Based on stakeholder's consultation)

Natural



Flood



Fire

Man made

- Road accident
- Drowning
- Boat capsizing
- Animal intrusion
- Health epidemic
- Electric shocks



Drought



Wind storm



Earthquake

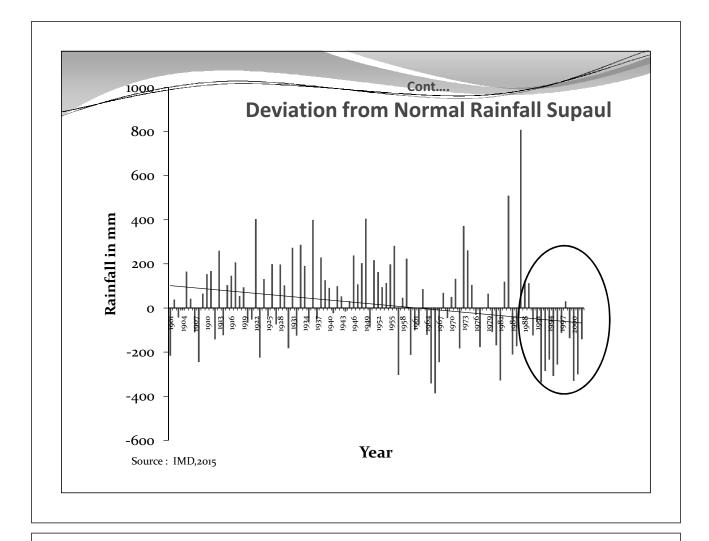


Hailstorm



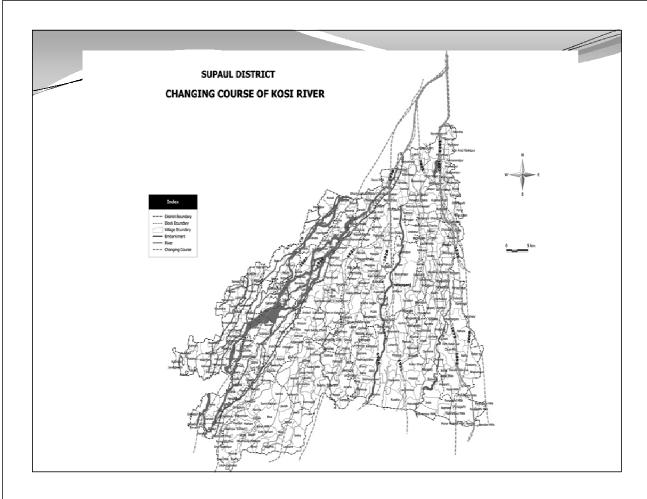
Lightening Heat and cold waves

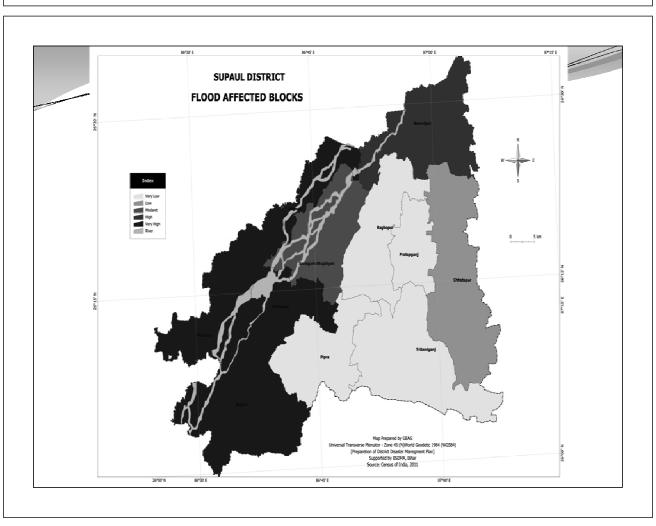
Cont.... Seasonality of hazards and risks Flood Drought **Earthquake** Fire Hailstorm **Wind Storm** Heat wave **Cold wave** Lightening **Electric shock** Road Accident **Boat Capsizing Drowning Epidemics Animal Attack**

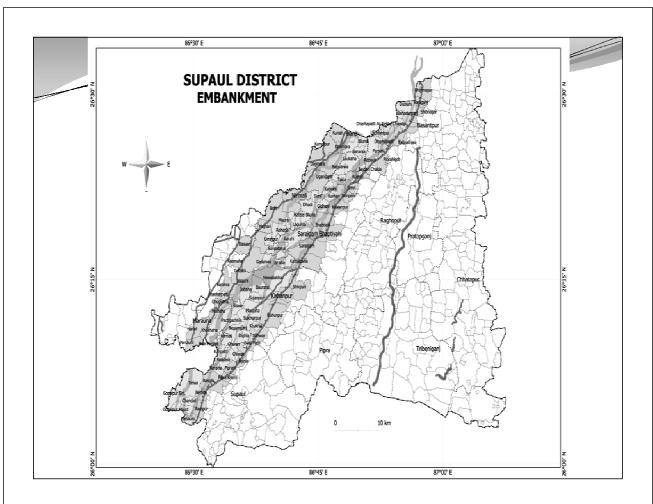


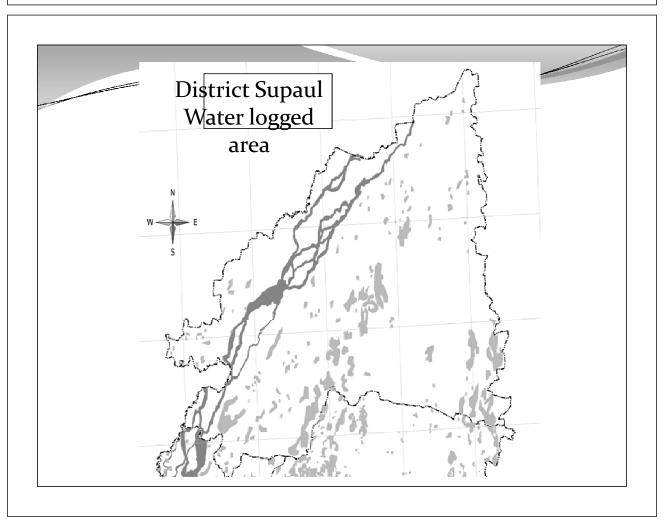
S.N	Block	Flood events (Year)	
			Frequen
			cy
1	Supaul	87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,05,06,07,0	26
		9,10,12, 13, 14	
2	Kishanpur	87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,05,07,09,1	25
		0 12,13,14	
3	Marauna	87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99,2000,01,02,03,04,07,09,10,13,14	21
4	Nirmali	87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99,2000,01,02,03,04,07,09,10,13	20
5	Basanpur	87,88,89,90,91,93,96,98,99,02,03,04,06,07,08,10,	16
6	Saraigarh	96,97,98,99,2000,01,02,03,04,06,07,09,10,12,13,14	16
	Bhaptiahi		
7	Chattarpur	96,97,98,99,2000,01,02,03,04,06,07,09,10,13	9
8	Triveniganj	87,96,98,04,08	5
9	Pipra	87,04	2
10	Raghopur	87,08	2
11	Pratapganj	96,08	2

Year - 1992, 2001,2010 and 2013 were declared as drought

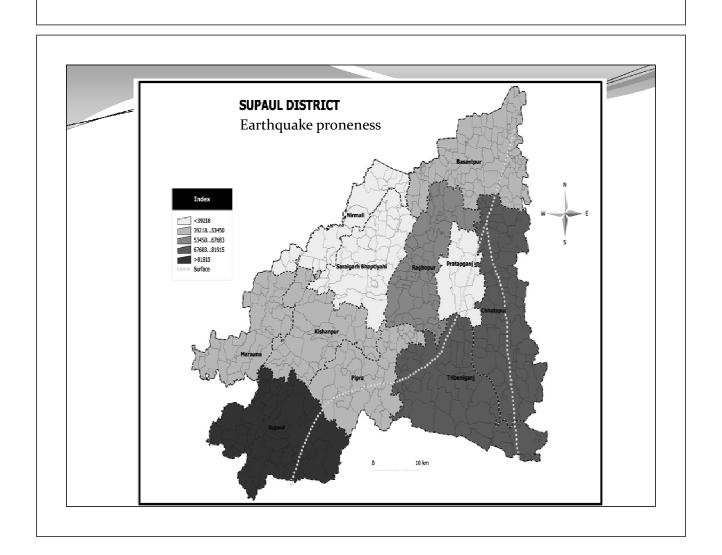








o' kI	i#kkfor {ks= (yk[k gøen)			Qlydk updlku		edku dk urdl ku		ekuo {kfr (la[; k ea)	a[;kea) lEifRrdk updlku	QIy]edku, a I kenpkf;d I EifRrdk day
			क्षेत्र ;लाख हे0मेंद्ध	मूल्य ;लाख मेंद्ध	संख्या	मूल्य ;लाख मेंद्ध	ei)		(yk[k e i)	uqdlku (yk[k es)
1991	0.24	2.49	0.13	53.35	4593	58.10	_	-	30.00	141.45
1992	0.16	0.98	0.11	2.66	978	7.13	_	4	0.75	10.54
1993	0.45	2.33	0.08	185.20	3991	47.25	50	5	4.00	236.45
1994	0.44	1.63	0.07	37.85	1604	17.04	_	1	1.25	56.14
1995	0.42	1.92	0.19	21.80	3444	46.90	_	1	0.80	69.50
1996	1.0	3.25	0.37	259.24	7050	79.78	23	5	18.61	357.63
1997	0.53	1.42	0.13	27.37	3018	63.87	_	-	_	91.24
1998	0.93	2.35	0.18	197.00	-	_	_	-	_	197.00
1999	0.02	0.33	0.02	120.00	657	43.95	_	5	_	163.95
2000	0.25	1.0	0.07	84.18	2226	30.33	_	_	9.60	124.11
2001	0.32	1.39	0.09	458.20	3584	76.01	_	-	25.00	559.21
2002	1.93	3.02	0.44	276.31	4406	272.31	2	5	224.78	773.40
2003	0.39	2.25	_	13.50	1530	28.70		2	6.00	48.20
2004	1.78	4.21	0.47	709.36	15131	1669.15	3	7	527.01	2905.52
2005	0.004	0.61	_	2.50	445	23.50	_	_	_	26.00
2006	_	0.03	-	2.00	819	18.93	_	3	_	20.93
2007	0.12	2.37	0.12	761.23	11671	2313.86	_	1	_	3075.09
2008	0.84	7.5	0.43	2691.19	73300	16644.36	5445	217	11222.31	30557.86
2009	0.04	0.77	_	_	1914	188.07	_	1	_	188.07
2010	0.04	1.34	0.03	173.42	8808	410.35	_	4	9.20	592.97
2011	0.07	1.15	0.08	244.44	2962	210.46	_	4	10.00	464.90
2012	0.68	0.63	0.002	3.86	719	68.40	_	1	_	72.26
2013	2	1.2	1.3	0.51	2417	229.20	21	4	_	229.71
2014	0.06	1.10	-	_	924	24.25	2	0	375.88	413.13
015	_	0.86	_	_	220	44.1	0	6	3.0	44.1



Human losses in different disasters

Year	Drowni ng	Boat capsizi ng	Epide mic	Fire	Earthqu ake	Lighte ning	Win d stor m	Heat wave	Cold wave	Road accid ent	Tot al
2008- 09	159	15	23	3	0	0	0	О	О	О	200
2009- 10	10	28	0	2	О	О	3	О	О	О	43
2010-11	2	О	О	3	О	2	2	0	О	1	10
2011-12	3	О	О	7	О	4	О	0	О	9	23
2012-13	О	О	О	О	О	4	О	0	О	0	4
2014-15	О	0	o Sp.	a V ial d	i 8 tributio	pof thes	e ^c hun	an loss	<u>e</u>	О	5
2015-16	27	1	0	4	О	10	0	0	0	4	46

Cont.... Response Plan

- Emergency Support Functions
- Emergency operation center
- Resources
- Deployment of NDRF and SDRF

Cont.... Preparedness, Mitigation, Prevention, Recovery & Reconstruction plan (link attached)

Thanks !!







बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण

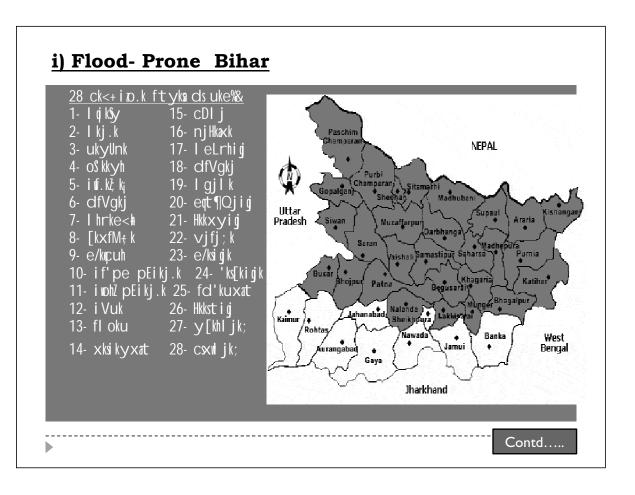
बाढ़ आपदा से निपटने हेतु मानक सञ्चालन प्रक्रिया

प्रस्तुतिकरण, विपिन कुमार राय

CONTENT

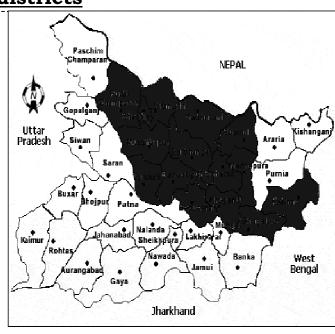
- 1. AN INTRODUCTION OF FLOOD IN CONTEXT OF BIHAR
- i. Explanation through Map/Graph /Table and Bar diagram presentation
- ii. Flood hazard zoning (Hazard map of Bihar)
- iii. Flood Hazard Area under Various Categories
- iv. Percentage of various flood hazard categories w r t total geographical area in the state
- v. Common Characteristics of Rivers in Bihar
- vi. River zones of Bihar
- 2. Pre-flood preparation (as per SoP) & govt. circular I
- 3.Search/Rescue &Relief (as per SoP) & govt. circular 2
- 4.Post-Flood Tasks(as per SoP)

1.AN INTRODUCTION OF FLOOD DISASTER IN CONTEXT OF BIHAR



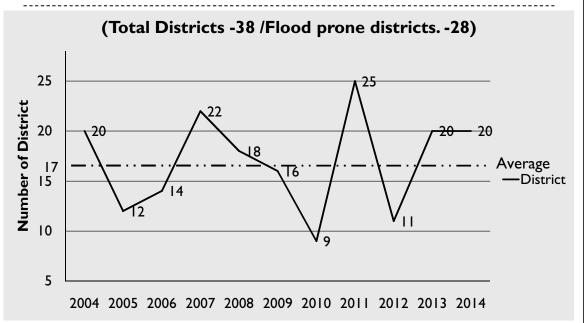


- 1. l q kSy 9- e/kqcuh
- 2- e/ksi gi k 10- l eLrhi gi
- 3- f'kogj 11- o\$kkyh
- 4- I gj I k 12- dfVgkj
- 5- [kxfM+ k13- i nohl pEi kj.k
- 6- I hrke<#14- csx// jk;
- 7- njHkaxk 15- Hkkxyi g
- 8- eqt¶Qjij



Contd....

A GRAPIC LOOK AT AVERAGE FLOOD AFFECTED DISTRICTS IN BIHAR



In II years, affected districts are 6 time above the average mark.(source final form IX)

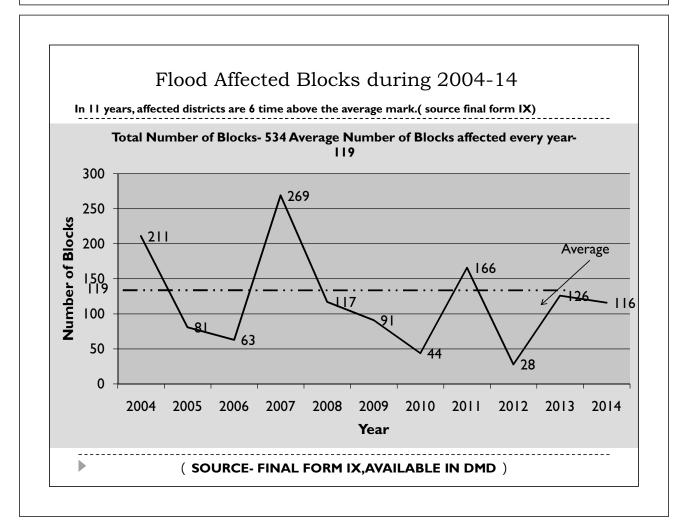
Contd.....

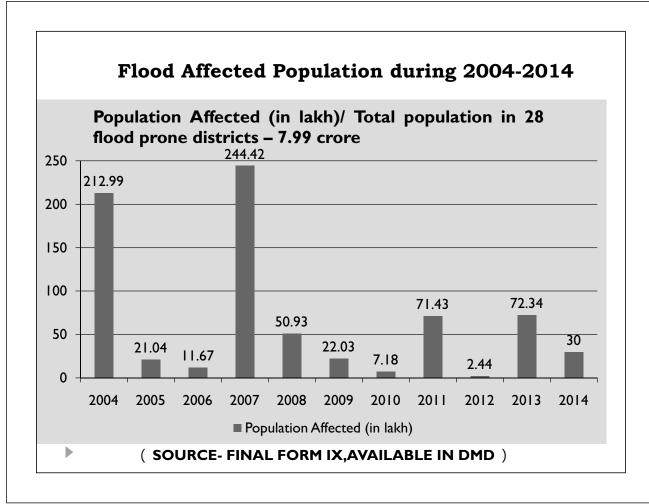
Frequency of Flood during 2004-2014

SI. No.	District	Frequency of Flood	Remarks
1	Muzaffarpur	11	Most flood prone
2	Saharsa	11	Most flood prone
3	Supaul	11	Most flood prone
4	Khagaria	10	Most flood prone
5	West Champaran	9	Flood Prone
6	Madhubani	9	Most flood prone
7	Purnia	9	Flood Prone
8	Katihar	9	Most flood prone
9	Sitamarhi	8	Most flood prone
10	Samastipur	8	Most flood prone
11	Bhagalpur	8	Most flood prone
12	Gopalganj	8	Flood Prone
13	Darbhanga	7	Most flood prone
14	Madhepura	7	Most flood prone
15	Araria	7	Flood Prone

Continued.....

SI. No.	District	Frequency of Flood	Remarks		
16	Patna	7	Flood Prone		
17	Kishanganj	6	Flood Prone		
L8	Nalanda	6	Flood Prone		
.9	East Champaran	5	Most flood prone		
20	Vaishali	5	Most flood prone		
21	Begusarai	5	Most flood prone		
22	Seohar	3	Most flood prone		
23	Bhojpur	3	Flood Prone		
4	Saran	3	Flood Prone		
25	Buxar	2	Flood Prone		
26	Lakhisarai	2	Flood Prone		
27	Sheikhpura	2	Flood Prone		
28	Siwan	1	Flood Prone		
29	Munger	1	Flood Prone		

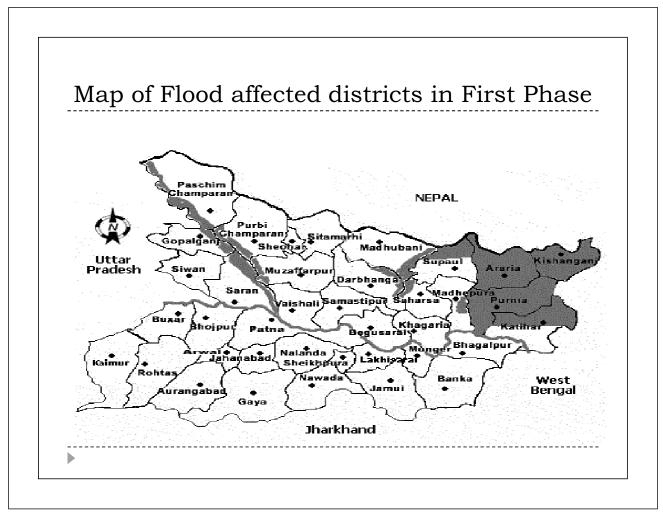


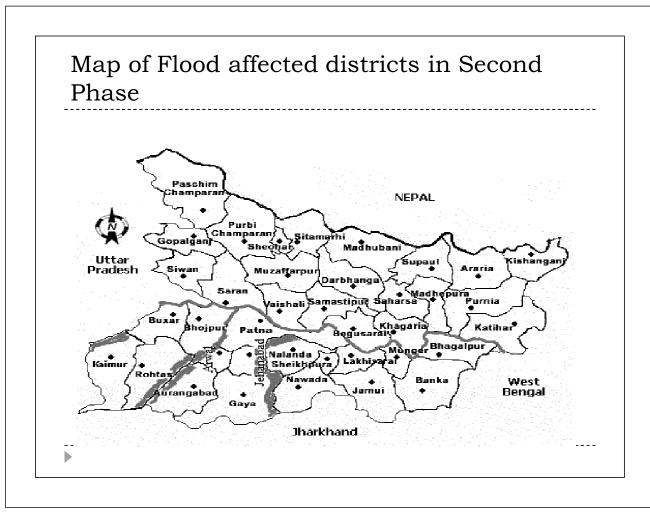


Salient features of flood 2016

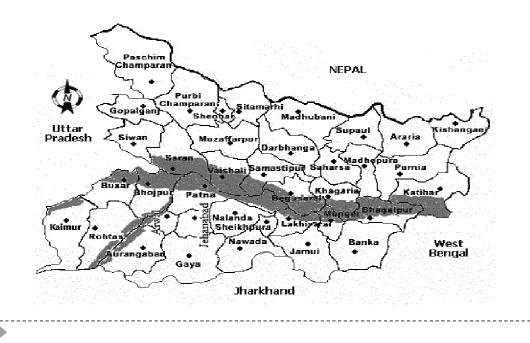
- ▶ Out of 38 districts 31 districts were affected by flood in four phases.
- ▶ 182 Blocks, 1421 Panchyats, 5024 Villages and 88.23 lakhs of people has been affected.
- ▶ Total 243 human lives and 5383 live stocks has been lost.
- ▶ A total of 3.72 lakh of hectare of Agriculture land has been affected which damages crop estimated to 56060 lacs rupees.
- ▶ A total of 129922 houses were damaged resulted estimated loss of Rs. 271 crore.
- ▶ Memorandum for Central Assistance amounting to Rs. 411198.42512 lacs has been sent to the Central Government.

("SOURCE- FINAL FORM IX, AVAILABLE IN DMD")





Map of Flood affected districts in Third Phase



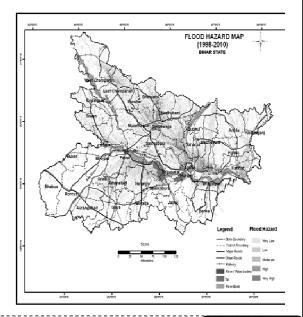
Salient features of flood 2017

- ▶ Out of 38 districts 22 districts were affected by flood in four phases.
- ▶ 8419 Villages and 171.72 lakhs of people has been affected.
- ▶ Total 514 human lives and 373 live stocks has been lost.
- ▶ A total of 810454 hectare of Agriculture land has been affected.
- ▶ A total of 274958 huts, 1526 pucca houses & 12014 kutcha houses were damaged.

(SOURCE- DMD, Report available till 10/10/17)

Flood hazard zoning

- Satellite data sets (128 in number) acquired during flood season between 1998 and 2010 covering Bihar state have been used for preparation of flood hazard zone map.
- It is observed that about 26.09% (24.56 lakh hectares) of land in Bihar state is affected by flood during 1998-2010 out of the total state geographical area 94.16 lakh hectares.
- Out of total 24.56 lakh hectares of flood affected area, about 0.83 lakh hectares of land falls under very high (inundated 11-13 times), 1.22 lakh hectares under high (inundated 8-10 times) flood hazard categories.



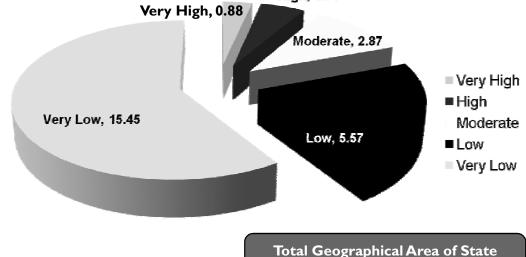
Contd....

Flood Hazard Area under Various Categories

S.No.	Hazard Severity	Flood Hazard Area (ha)	% Flood Hazard (wrt State Geographic Area)	% Flood Hazard (wrt Total Flood Hazard Area)
I	Very High	83280	0.88	3.39
2	High	122905	1.31	5.00
3	Moderate	270579	2.87	11.01
4	Low	524862	5.57	21.36
5	Very Low	1455278	15.45	59.23
	Total	2456904	26.09	100.00

Contd





94.16 lakh hectare

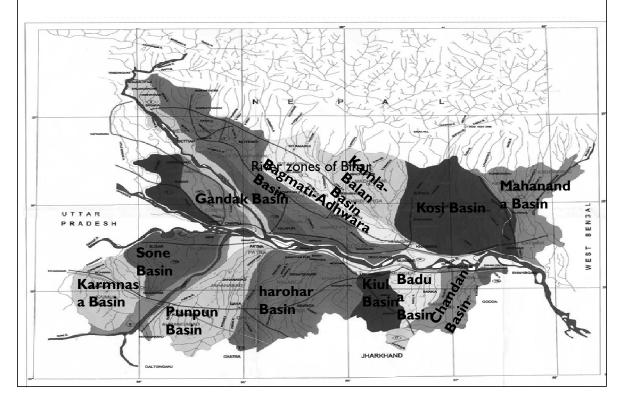
Common Characteristics of Rivers in Bihar

- Bihar, in North, is a courtyard of Himalayan rivers, south Bihar is a backyard of rivers flowing from the hills of Chotanagpur and Rajmahal.
 - > 17.2% of total flood prone area of the country falls in Bihar
- North- planes of Bihar, adjoining Nepal, drained by number of rivers having their catchment areas in steep and geologically nascent Himalayas
- 65% of this catchment area of these rivers lies in glacial region falling in Nepal/Tibet, receive very heavy rainfall during monsoon increasing the discharge level 50 to 90 times larger than normal time.
 - > 76% of the population in north Bihar live under the recurring threat of flood
- -->--56%-of total-geographical area covering 28 districts in north-Bihar is flood prone. --

Contd....

- ☐ Unstable water flow and tendency to shift their course,
- ☐ Unsteadiness in the incidence of flash flood due to sudden heavy discharge,
- □ Destruction of banks & embankments due to problem of erosion,
- □ Problem caused by uncontrolled silting,
- ☐ Flooding of crops land due to rising level of river.

River zones of Bihar



River zones in North Bihar

Ghaghara-gandak zone

- Total area 15.91 lakh hect,
 5.88 lakh hect is flood prone.
- Floods in the region mainly due to
- ✓ Overtopping of banks
- ✓ Breach in embankment
- √ Bank erosion

Gandak-bagmati zone

- ➤ Total area 12.32 lakh

 hect, 10.65 hect is flood prone
- Extremely meandering in nature all along their courses
- Inside Bihar flow of river slows down dropping its bed load of sand & silt; stream meander through serpentine course
- Devastating flood aggravated by tributaries Lalbakia, Lakhandei.

Contd...

Bagmati-kosi zone

- ➤ Total area 11.60 lakh hect;8.14 lakh flood prone
- Includes Adhwara group of rivers
- ▶ 12 rivers flow in this zone
- ▶ All the rivers come down from the steep slopes of the Himalayas
- Accumulates silts along the courses of rivers results in changing of their course

Kosi- mahananda zone

- ▶ Total area 16.48 lakh■ hect; 15.30 lakh hect is flood prone
- ▶ Kosi is the river of seven streams, each one originates in the high region of the Himalayas, the region with plenty of snow and precipitation.

2. Pre-flood preparation (as per SoP)

2. बाढ़ पूर्व तैयारिया (SoP के अनुसार)

- o"kkZekid; ≔kadhejEefr
- o"kkīkr ∨k\dMkadk išk.k
- ck<+lsiHkkfor gksus okys l Hkkfor {ks=ksa, oa ladVxiLr
 fDr lengksadh igpku, oa utjh uD'kk r\$kj djuk

लगातार.....

- <u>l al k/ku_ekufp=.k_%&</u>
 - > ftyka ea mi yC/k futh ukoa
 - > igkuh Ijdkjh ukokadh ejEefr
 - > ubl I jdkjh ukoka dk fuekl k
 - tujýj I sv@is/keDI /VsJV@egktky vkfn dh miyC/krk
 - > jkT; [kk| fuxe ds xknkeka es [kk|kUu dh mi yC/krk

लगातार.....

- TRrve uede pwlke xweekeckrhe fn; klykble fdjklu rsy vkfn dh miyC/krk dk vkdyu] nj fu/kklj.k , oa vl; 0; oLFkk, w
- > i kWyhFkhu 'khVka dk Ø;
- > ekuo nok dh mi yC/krk
- i 'kq nok dh miyC/krk
- > i'kqpkjsdh miyC/krk
- [kk | kUu ds | a/kkj . k gsrq xkmkeks dk fpfUgdj . k

yxkrkj-----

- ukfodka@ukoka ds yafcr etnijh@ HkkMs dk Hkorku
- [kkst] cpko , oa j kgr nyka dk xBu
- 'kj.k LFkyka dh i gpku
- {k\$=h; i; b\${kdk} dh i frfu; fDr
- rVca/kka dh I j {kk
- I Medka dh ej Eer
- ukMy inkf/kdkjh dk ukWeusku

लगातार.....

- vki krdkyhu l ipkyu dilni@fu; ≥ .k d{k dki dk; ji r dj uk
- I pkj ; kst uk (Communication Plan)
- ukoka ykbQ t&ds@eksVj cksV ds ifjfu; kstu
 (Deployment) dh vkdfLed; kstuk
- ftyk, oajkT; Lrjh; VkLd Qkd Idk xBu
- vkdfLed QI y ; kstuk dk I ⊯.k
- I acf/kr foHkk×ks }kjk ∨kdfLed; kstuk dk I ⊯.k
- I empk; , oa ∨U; I k>nkj ka (Stakeholders) dk
 i f' k{k. k

.

परिपत्र-1(ज्ञापांक 1137 दिनांक 24/4/17); (28 बाढ़प्रवण जिलो के अतरिक्त अन्य जिले भी शामिल हैं)

पत्रांक 1910आ0-06/2016 ... बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग

प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिय।

सेवा मं,
जिला पदाधिकारी,
सुपील, संपपुरा, शिवहर, सहरसा, खगडिया, शीलामदी, दरमगः,
पुजनि, सम्पूरा, शिवहर, सहरसा, खगडिया, शीलामदी, दरमगः,
पुजनि, समस्तिपुर, गेगाली, कहितर, पूर्वी समारण,
अनुसराव, सागलपुर (अति बाह प्रचणा 15 जिले)।
वकार, सारण (छण्या), जालन्दा (विहास्तरोफ), पूर्णिया, अरदिया, पश्चिम
समारण, शैक्षपुरा, किथानगंज, घटना, गीजपुर, सिवान, लखीस्तराव,
गीपालगंज (बाद प्रचण जिले) एवं नवादा, मुगेर, जहानावाद, रोहतास,
कैंगूर, औरंगावाद, अरवल।

□टला−15, दिनांक−

विषयः संमावित बाढ़ 2017 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

बाद पूर्व तैयावियों हेतु उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार होंगे :

3.बाढ़ के दौरान की जाने वाली करवाई (SoP के अनुसार)

3.Search/Rescue & Relief during flood (as per SoP)

- · ck<+i nol psrkouh
- · ck<+dh l wpuk dk i &k.k
- i Hkkfor {ks=ka ea ukoka dk i fjfu; kstu (**Deployment**)
- {kfr dk Rofjr vkdyu
- vkcknh dk fu"Øe.k

>

लगातार.....

- jk"Vh; vkink fjLik¶ Qkd 1¼, u0Mh0vkj0, Q0½@ jkT; vkink fjLik¶ Qkd 1¼, I0Mh0vkj0, Q0½ dhetx
- I suk dh ekx
- , ; j Qksl 1 ds gsyhdkWVj dh ekx
 - > vf/k; kpuk dh i fØ; k
 - gsyhdkWVjk@gokb1 tgkt ds }kjk dh tkus okyh dkjbkb1
 - > ok; q ku ds i idkj
 - gsyhdkW/j ds vkus ij fuEu 0; oLFkk, Wdh tk, xh
- gsyhdkWVj Is Qw i sdsV fxjkus dh dkj/bkb/l

लगातार.....

- ck<*xilr {k≤ka eajkgr 0; oLFkk
- ekuo LokLF; dh ns[kHkky
- i 'kq pkjs dh 0; oLFkk
- i'kq LokLF; dh ns[k&Hkky
- xHkbrh ekrkvks@/kkr`ekrkvks dh ns[k&Hkky
- is ty dh 0; oLFkk

लगातार.....

- vko'; d I sokvka dk Rofjr i uLFkkli u
- vkokxeu dh 0; oLFkk@l Ei dZ i Fkka dk i quLFkkZi u
- ck<-xilr {ks=kareafctyh , oanujlapkj 0; olFkk dk iqulFkkiju
- rVca/kka ds ViWus dh n'kk ea vko'; d dkj bkbł; ki
- ftyk@jkT; Lrjh; VkLd Qkd ldh fu; fer c\(\mathbb{B} \)d
- ck<+ls[kjkc gq pkikdykadh ejEefr

लगातार.....

- eirdka ds 'koka dk fui Vku
- i'kq'koka dk fuiVku
- erdka ds vkfJrka dks vuqzg vuqnku dk Hkqzrku
- jkgr, oa cpko dk; ka ea LFkkuh; lenk; ka, oa ukxfjd læBuka dh Hkkxhnkjh

.....

लगातार.....

- x§ Ijdkjh I & Ekkuks@varjk\(\bar{L}\)Vh; , tfUI; ks@vU; jkT;
 Ijdkjks@dk\(\bar{L}\)iksj\(\s\) I \(\bar{L}\)Vj@0; fDr; ksa\(\bar{L}\)kjk jkgr dk; k\(\bar{L}\) es
 Ig; k\(\s\)
- I wouk , oa fefM; k dk i zaku
- tu f'kdk; rka dk fui Vku
- ehfM; k eaindkf'kr@inlkfjr fjiksVlij dkjbkbl

>

परिपत्र-2(बाढ़ के समय राहत शिविर की नई संकल्पना)

		विहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग
	प्रेषक,	
		व्यास जी,
	संबा में	प्रधान राजिय ।
	साथा म,	
		सभी जिला पदाधिकारी. बिहार।
	विषय—	पटना—15, दिनाक— बाढ़ पीड़ितों के द्वारा आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे सड़कों,
		बांधों एवं अन्य ऐसे स्थलों को राहत शिविर की मान्यता देते हुए आवश्यक
		सुविधार्ये उपलब्ध कराने के संबंध में।
	गहाशय,	•
		उपर्युवत. विषय को संबंध में कहना है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल प्लावित
	गागा / डोलों /	(भित्रता से सरक्षित बाहर किकानका जाने जान कार्यक के
	गागक खबाल	। पाक्रिया म उल्लेखित नाम्से के अनुसार राज्य किकिन के आक्रम
	≛. इस पण भा यह भी स्वत्रक	ज्य के विभिन्न जिलों में आयी बाढ़ के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों के संबंध में
	राहत शिवियों	। प्राप्त हो रही है कि बाद से प्रभावित कर लोग प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे में न जाकर किसी सड़क, बांध अथवा अन्य सूखे स्थलों पर शरण लिये हुए हैं।
	3. दिनांक-21	.08.2016 को गंगा नदी के बढ़ते जलरतर के कारण गंगा नदी किनारे अवस्थित
	विभिन्न जिलो	में आमे बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार हारा संबंधित जिला
	पदाधिकारियों	के साथ विडियो कांक्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक में यह
	ા અનુવા વિશ્વસા ક	ाया कि बाद प्रभावितो देश आक्षक काक के क्या के क्या कि क्या क
	राष्ट्रभाग, व्याचना स	९९ अ.च स्थला का भा पहल 19वंक के कहा है स्टब्स के स्टब्स के
	संघालन प्रक्रिय करायी जाय।	पा में उत्त्वेखित नाम्स् के अनुरूप नियमानुसार उन्हें आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध
	आय।	अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में यथीचित कार्रवाई करने की कृपा की
		विश्वासभाजन
-		80/-
		(ख्यास जी)
•	ज्ञापांक	ਸ਼ਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਹ
	प्रतिलिपि	
		ह0 / -
		TISTED TO FIRM
	D:\flood\Flood 2016\i	Letter to flood dist katihan-docx

4.बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कारवाई (SoP के अनुसार)

4.Post-Flood Tasks(as per SoP)

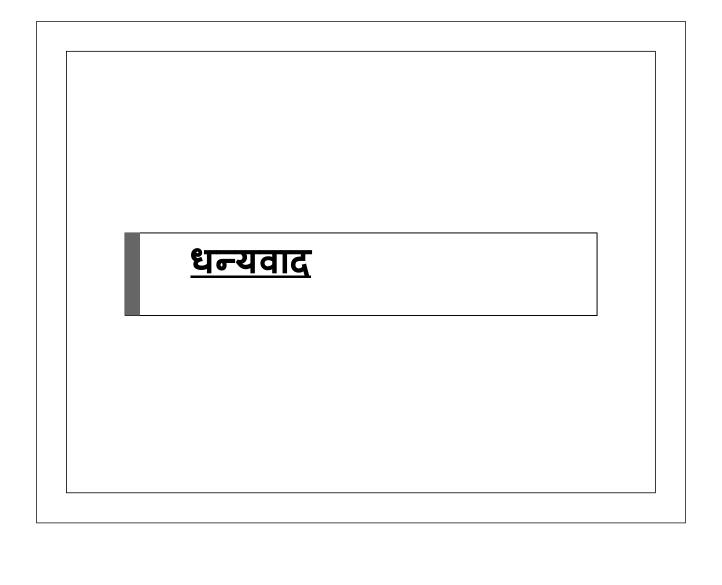
- jkgr forj.k
 - >eqr [kk | kUu 1/Gratutious Relief) dk forj.k
 - ≽iwkZ {kfr dk ∨kdyu
 - >{kfr ∨unku forj.k
 - >fdl ku ØfMV dkMZ/kkjdkadks __.k dk forj.k
 - > QI y chek Is ∨kPNkfnr QI yks ds fy, chek ykHk Hkoxrku
 - >ck<+jkgr d£i@exk d£ikaeajkgr dh 0; oLFkk

.....

लगातार.....

- vk/kkjHkwr I j puk∨ka dh {kfr dk vkdyu
 - > {kfrx1Lr vk/kkjHkvr l jpukvkadk iquLFkkiu@iqufu1ek1k
- ▶ egkekjh dh jkødFkke
- ty teko okys {ks=kals ty fudklh dh 0; oLFkk
- ck<+ds vare i aronu dk i atk.k
- jkgr dk; kalea0; ; jkf'k dk mi; kfxrk iæk.k&i =
- -r dkjbkb; ka dk vllrfujh{k.k ¼Introspection½, oa Hkfo"; ds fy, lh[k ¼Lessons learnt½

>









बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण

isty ladV izaku gsrqviukbZt kusokyh ekud lapkyu iadz k

> प्रस्तुतिकरण विपिन कुमार राय

i Łrardj.k; kt uk

- 1. परिचय
- 2. संस्थात्मक ढाँचा
- 3. पेयजल संकट प्रबंधन की पूर्व तैयारियाँ
- 4. पेयजल संकट के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ

>

परिचय

- पेयजल संकट आपदा के रूप में अलग से अधिसूचित नहीं है.
- भीषण गर्मी/ अल्प वर्षा-पात /सुखाइ की स्थिति में पेयजल संकट उत्पन्न होने पर मानक सञ्चालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्य किया जायेगा.
- विशेषकर गंगा के दक्षिण के 17 जिले, जिन्हें सुखाड़ ग्रस्त जिले
 माना जाता है, उन जिलों में, किन्तु सूखाग्रस्त घोषित अन्य जिलों
 में भी इस मानक सञ्चालन प्रक्रिया के अनुरूप करवाई होगी.

- vkink izáku vf/kfu; e 2005 dh/kkjk 20 dhmi/kkjk ¼1½, oa ½½ ds várx ír eq; l fpo dh v/; {krk ea j kT; dk, Zlkfj. kh l fefr dk xBuA
- यह समिति राज्य स्तर पर पेयजल संकट प्रबंधन कार्यों का समन्वय करेगी.राज्य सरकार के किसी भी विभाग/प्राधिकार/निकाय को निदेश देगी.
- vkink izaku foHkox } kjk ukovny foHkox ds: Ik ena jkT; dk; Zdkj. kh l fefr ds funškom dk
 dk; kZb; uA
- is ty ladV izaku eaykd LokLF; vfHk, æ.k foHkx] Ik kq, oa ekL; lakku foHkx] y?kq ty lakku foHkx] uxj fodkl , oa vkokl foHkx] ÅtkZ foHkx , oa fcgkj LVV ikoj gkYMax dEiuh fy0 एवं सम्बंधित नगर निकाय dh HxfedkA

- ▶ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपातकालीन प्रबंधन समूह गठित, जिसमें विकास आयुक्त, सचिव / प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष—सह—निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 सदस्य के रूप में एवं सचिव / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग सदस्य सचिव के रूप में नामित।
- समय-समय पर बैठक कर सभी विभागों के आकस्मिक योजनाओं और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा
- आपातकालीन प्रबंधन समूह में मुख्य सचिव द्वारा किसी अन्य विभाग अथवा संगठन को आमंत्रित किया जा सकेगा।
- आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा लिए गए निर्णय सभी संबंधित विभागो पर बाध्यकारी होगा।

- ▶ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित।
- ▶ जिला पदाधिकारी घटना कामांडर Incident Commander के रूप में कार्य करेंगे तथा पेयजल संकट से जुडे विभागों के जिला स्तरीय तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न एजेंसियाँ घटना कमांडर के निदेशानुसार कार्य करेंगे।
- पेयजल संकट प्रबंधन का निदेश एवं नियंत्रण जिलापदाधिकारी के हाथों में होगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति की निति और दिशानिर्देश में कार्य करेगा
- पेयजल संकट प्रबंधन में भूमिका निबाह रहे संबंधित विभाग अपने विभाग के लिए
 वरीय पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारियों को नामित करेंगे।

2- is ty ladV izáku dhiwZr\$kj; k

- \blacktriangleright lks ty ladV dh igpku (लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभग और लघु जल संसाधन वि \bullet)
 - > दक्षिण-पश्चिम एंव उत्तर पूर्वी विगत मॉनसून में अल्प वृष्टि
 - > जलाशयो में जलो का कम भंडारण
 - > भूजल स्तर में लगातार गिरावट
 - > चापाकल से पानी आहरित करने में कठिनाई
 - ≽ कुऑ–आहर–तालाब सूख रहे हों
- is ty ladV dh lapuk izir gkrsgh vkink izzáku foHkx }kjk vki krdkyhu izzáku legy dsvfHkKku esaykuk

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा आकिस्मक योजना का सूत्रण
- > जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण
- लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि० का समन्वय
- पेय जल संकट से प्रभावित होने वाले संभावित ग्रामों / टोलो का चिन्हिकरण एवं इनकी जनसंख्या तथा उपलब्ध जलश्रोतों का मानचित्रण
- पारम्परिक जलश्रोतों के पहचान एवं आवश्यकतानुसार उनकी सफाई / गहरीकरण
- > आवश्यतानुसार जलधारा में अस्थाई डैम बनाकर जलापूर्ति की व्यवस्था
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों / निकायों द्वारा गाड़े गए चापाकलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा चापकलों की विशेष / साधारण मरम्मति की योजना

लगातार.

- - > लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन
 - यांत्रिक दोष / विद्युत दोष के कारण बंद पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 के द्वारा किया जाना
 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा यांत्रिक / विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना का सूत्रण
 - पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति करने हेतु जलश्रोतों की पहचान एवं रूट चाट तैयार करना तथा इसकी नियमित अनुश्रवण करना
 - आवश्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जल आपूर्ति की योजना तैयार करना।

- > आवश्यकतानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था करना तथा इस हेतु दर का निर्धारण करना
- > टैंकरों की कमी होने पर सिंटैक्स जैसे टंकियों के माध्यम से जलापूर्ति करना।
- ▶ बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में नलकूपों से जल की लिपिटंग हेतु डीजल सेट की व्यवस्था करना
- स्थायी मिस्त्रियों के कमी की स्थिति में संविदा / आउटसोर्सिंग के आधार पर मिस्त्रियों की व्यवस्था करना
- > पशु शिविरों के लिए यथा संभव जलश्रोतों के पास स्थलों की पहचान करना
- नगरीय क्षेत्र के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदेशों के अनुसार पेय जल जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण

लगातार.

▶ vU; læf/kr foHkkxka}kjk iwZr\$kfj;k,

----->-Yk2kqt.y-1-å-k/ku-foHkx------

- राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को सक्रिय करना
- भूजल रिचार्ज की योजनाओं के कार्यन्वयन एवं नियमित समीक्षा
- नलकूपों की स्थिति एवं कार्यरत बनाए रखने की सघन एवं नियमित समीक्षा

> 1k'kq, oaeRL; lak'ku foHkx

- पेयजल एवं चारा संकट की सतत निगरानी
- राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को सक्रिय करना
- पशु शिविर हेतु आकस्मिक योजना का सूत्रण
- पशु शिविर हेतु स्थल चयन
- पशुओं को पशुशिविरो में पहुचाने की व्यवस्था
- पशुशिविर के अन्तर्गत अस्थायी सेड का निर्माण
- पीने की पानी एवं नाद की व्यवस्था
- पशु चारा की व्यवस्था
- बिमार पशु के इलाज के लिए दवा की व्यवस्था
- पषुपालको एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था
- मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था

लगातार.

> Åt kZfoHkkx @ fcgkj LVsV i koj gkKYMax dEiuh fyfeVsM

जलापूर्ति संयत्रों एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु
 आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन

> Uxj fodkl , oavkokl folkkx

• पेय जल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन

> ft yk VkLd Qkd Zdk xBu

- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार स्टेट पावार होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा यथानुसार संबंधित नगर निकायों के आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य के रूप में जिला टास्क फोर्स का गठन
- आकिस्मिक योजना के कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा

लगातार.

> ft yk Lrjh, ukMy inkf/kdkjh

- जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाना
- नोडल पदाधिकारी द्वारा पेयजल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य
- टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग द्वारा जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करना
- विभागीय नोडल पदाधिकारी द्वारा अपने—अपने विभागीय आकिस्मक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करना

> ft yk fu; æ. k d{k dh LFkki uk

- दूरभाष / फैक्स सं0 की जानकारी संचार माध्यमों से आमजनों को देना
- जन साधारण द्वारा जल संकट की सूचना प्रशासन को देना

> jkT; fu; a=.k d{k dh LFkki uk

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना
- दुरभाष / फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों के माध्यम से आमजनों को देना
- आमजनों तथा अन्य श्रोतों से पेयजल संकट के संबंध में शिकायतों / सूचनाओं पर जानकारी प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना
- पेयजल संकट से निपटने हेतु की गई कार्रवाईयों से आम जन एवं मीडिया को भी समय—समय पर अवगत कराना
- आपदा प्रबंधन विभाग में गठित आपातकालीन संचालन केन्द्र को सिक्रय करना

> is ty ladV i záku gsrqfuf/k dh Q oLFkk

- संबंधित विभाग द्वारा पेयजल संकट प्रबंधन हेतु विभागीय बजट द्वारा निधि की व्यवस्था करना
- स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से यथानुसार राज्य कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निधि उपलब्ध कराना
- आकिस्मिक योजना के त्विरत क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 के अन्तर्गत शिथिलिकरण हेतु संबंधित विभाग द्वारा पूर्व औचित्य दर्षाते हुए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करना

3- is ty lad V dsnkýku dh t kus okyh dkj Zko Z k

fu; æ.k d{k dks l fdz, djuk

- > राज्य, जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सिक्रय करना
- प्राप्त होने वाले सूचनाएं तथा उनपर कृत कार्रवाईयों से संबंधित कागजातों का दस्तावेजीकरण (Documentation)
- > प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाईयों को रजिस्टर में संधारित करना

▶ ft yk VkLd Qkd Zdh c\$d

🕨 जिला टास्क फोर्स की आवश्यकतानुसार प्रति दिन तथा स्थिति सुधरने पर साप्ताहिक बैठक

▶ VSdjkal sikuh igopkus dh Q oLFkk

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा आकस्मिक योजना के अनुरूप पहचाने गए गावों में टैंकरों के माध्यम से जल पहुंचाने एवं वितरण का कार्य करना
- विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधिक्षकों द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात करना
- > जल वितरण के कार्य में पूर्ण पादर्शिता बरतना
- > भेजे जाने वाले टैंकरों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति का आकलन कर तद्नुरूप कार्रवाई
- > प्राप्त किए जा रहे पेयजल के जल श्रोतों की पीने योग्य की जांच करना
- विभागीय कनीय/ सहायक अभियंता द्वारा टेंकरो द्वारा जल पहुंचाने एवं वितरण कार्य का संघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

▶ lk, ty Jkrkadhigpku

- > केन्द्रिय भू-जल बोर्ड के मदद से जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू-जल श्रोतों की पहचान
- लोंक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / लघु जल संसाधन विभाग द्वारा चिन्हित जल श्रोतों से जल के दोहन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना

u, pki kdyka, oauydivka dk vf/k'Bki u

- भू—जल उपलब्ध क्षेत्रों में भू—जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नए चापाकलों के अधिष्ठापन में तेजी लाना
- लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवष्यकतानुसार नए नलकूपों का अधिष्ठापन कर जल के नए श्रोतों को उपलब्ध कराना

i ji kus pki kdyka dh ej Fefr

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित मिस्त्रियों की टीम को सिक्कय करना तथा पर्याप्त साजो—समान से लैस करना
- अपर्याप्त संख्या में मिस्त्री उपलब्ध होने पर संविदा / आउटसोर्सिंग से गैंगमैन की सेवा लेना
- प्रखण्ड स्तर पर मिस्त्रियों के टीमों के बीच क्षेत्रों का बटवारा करना तथा उनका लगातार क्षेत्र का भ्रमण करना
- प्रखण्ड नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर गैंगमैनों को मरम्मति हेतु भेजना एवं उसी दिन शाम तक गैंगमैनों को व्यक्तिगत उपस्थिति कराकर किए गए कार्य का ब्योरा प्राप्त करना
- > कनीय / सहायक अभियंता द्वारा आकार्यरत चापाकलों के मरम्मति का सघन पर्यवेक्षण एवं ---अनुश्रवण-----लगातार.

▶ 'kgjh {ks=kaeaty ladV dk eqdkcyk

- > नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निकायों के माध्यम से जल संकट वाले क्षेत्र में ---- आवस्थकतानुसार -दैंकसें-के-माध्यम-से-जल-पहुंचाना-एवं-वितरण-करने-का-ब्यवस्था-करना-
- विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जल वितरण के समय नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराना

· uydwikadksdk, #r cuk, j[kuk

- » लघु जल संसाधन विभाग चिन्हित जल श्रोतों को चालू रखने के लिए ऑपरेटरो सहित मोबाईल टीमों का
- मोबाईल टीमों में सामान्य यांत्रिक दोश एवं विद्युत दोश का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारी के साथ आवश्यक साजो समानों एवं वाहनों से लैस रहेंगे
- 🕨 मोबाईल टीमों के बीच नलकूपों का बटवारा जिससे सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके

+ tyki frz; kt ukvka, oa uydŵka ds fo | qr nkilka dk fuokj. k

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुप्रभाषित दायित्व सौपकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकायों के साथ सतत् सम्पर्क कर जलापूर्ति योजनाएं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का युद्ध स्तर पर निवारण करेंगे।

tyki frz; kt ukvka, oa uydwka dks fo | qr vki frz

- बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा जलापूर्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्ति हेत् पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी
- 🕨 प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू करना
- > रोस्टर व्यवस्था आम जनों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना

लगातार.

▶ eoskh fikojkadksdk, ¼r djuk

- > पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आवष्यकतानुसार पषु षिविर लगवाना
- --->- पशु शिविरों- में -पेयजल- एवं -चारे- की -व्यवस्था- करना------
 - पशु शिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरीये आम जनों तक पहुंचाना

▶ ftyk v kink i zaku i Łaf/kodkj dho SBd

- > उत्पन्न जल संकट तथा उससे निपटने के लिए की जा रही कार्रवाईयों की नियमित समीक्षा
- आवश्यकतानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राधिकार द्वारा अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए संबंधित एजेंसियों को निदेश देना तथा अन्य प्रबंधन करना

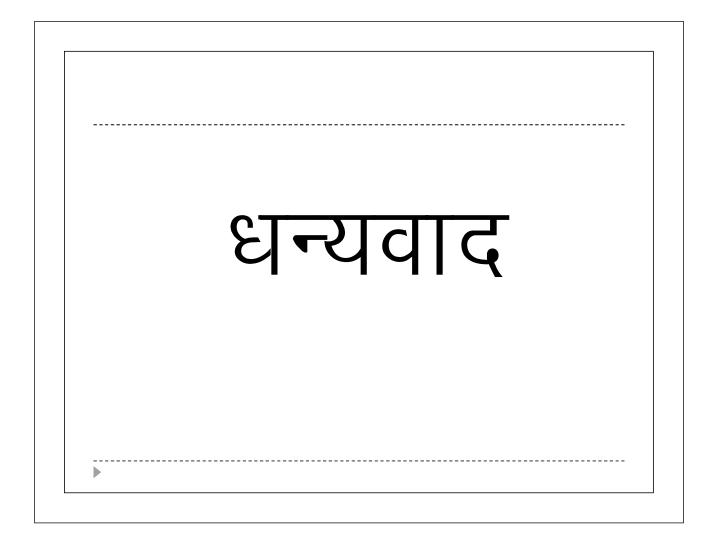
vki krdkyhu i záku l egy dh cSbd

- आवश्यकतानुसार जिलों में व्याप्त जल संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा हेतु नियमित बैठक
- वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता होने पर आवश्यक निर्णय लेना एवं उक्त निर्णय का सभी संबंधित विभागों पर वाध्यकारी होना

▶ jsyos l s i kuh dh < gykbZ</p>

- पेयजल संकट की स्थिति गहराने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रेलवे तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावित जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन तक जल पहुंचवाने की व्यवस्था करेगा।
- रेलवे स्टेशन से संबंधित जिलो तक जल ले जाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को होगा

은 중 PHED, DIVISION.... EXECUTIVE ENGINEER 탏 PH. Division P.H.sub Division D of 100 Weekly Report for Water Supply through Trasportation in scarce habitations Day Dayard ⊒ (दष्टवा कहिका- 2.2) Nos of feeding points of tractors/tanke previous Day DISTRICT MAGISTATE DISTRUCT.... Satisfactor Normalio after treatypen Water testing report of source Mode of transportation 동종 Quantity of water supplied in KL/Day Remarks









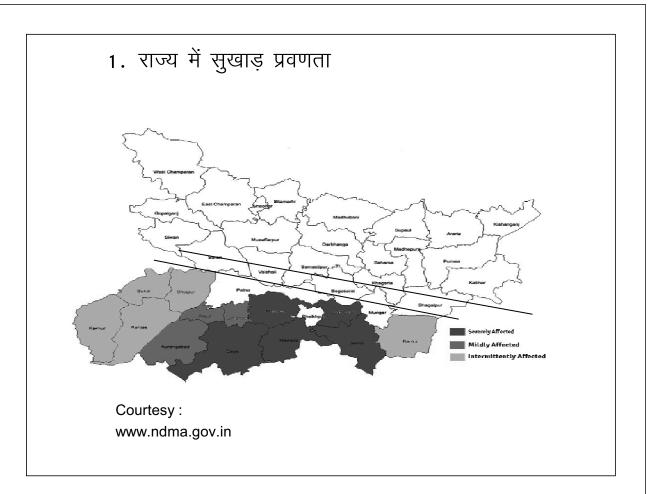
l (kkM+vki nk i záku dsfy, ekud l pokyu i zØ; k

Mo xxu

vu**ę** Myh, ykd f'kdk; r fuokj.k i nkf/kdkjh egukj ½8 kkyh½

प्रस्तुतिकरण योजना

- 1. राज्य में सुखाड़ प्रवणता
- 2 संस्थात्मक ढाँचा
- 3. सुखाड़ की अनुमानित परिस्थितियाँ
- 4. सुखाड़ के निर्धारित संकेतांक
- 5. संचार योजना
- 6. सुखाड़ आपदा की विभिन्न स्थितियाँ
- 7. सुखाड़ आपदा की विभिन्न स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयाँ
- 8. सुखाड़ की घोषणा



1. राज्य में सुखाड़ प्रवणताcontd

- ❖बिहार राज्य सुखाड़ की समस्या से कम या अधिक स्तर पर प्रायः प्रत्येक वर्ष प्रभावित होता है।
- ❖सामान्यतः राज्य के गंगा के दक्षिण स्थित जिले यथा—गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, रोहतास, सासाराम, नवादा, अरवल, बांका आदि सुखाड़ की समस्या से ज्यादा प्रभावित होते हैं।
- ❖एक या दो वर्ष के अंतराल में अल्प वृष्टि या अनियमित वर्षापात के कारण राज्य को भयानक सुखाड़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

2. संस्थात्मक ढाँचा

- > राज्य कार्यकारिणी समिति
- नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग
- ➤ आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG)
- > जिला पदाधिकारी-घटना कमांडर
- > जिला टास्क फोर्स

3. सुखाड़ की अनुमानित परिस्थितियाँ

d øl 0	vu ę kfur ifjfLFkfr; k	o"kkikr dh fLFkfr
1	सामान्य वर्षापात (Normal Rainfall)	सामान्य वर्षापात से ± 19% तक वर्षापात
2	अल्प वर्षापात (Deficient Rainfall)	सामान्य वर्षापात से -20% से -59% तक वर्षापात
3	अपर्याप्त वर्षापात (Scanty Rainfall)	सामान्य वर्षापात से -59% से -99% तक वर्षापात
4	वर्षापात में अन्तराल (Dry Spell)	दो अथवा अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होना
5	मॉनसून की समय पूर्व वापसी (Early withdrawal of Monsoon)	सितम्बर माह से पहले मॉनसून की वापसी एवं वर्षापात न होना
6	वर्षा का नहीं होना (No Rainfall)	सामान्य वर्षापात से -100%

4. सुखाड़ आपदा की विभिन्न स्थिति

- ❖अल्प वर्षा तथा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति
- वर्षापात में अंतराल
- मॉनसून की समय पूर्व वापसी
- ❖दक्षिण—पूर्व मॉनसून की अवधि में बिल्कुल वर्षा न होना

5. l (kkM+vki nk dh fofHkUk fLFkfr; kaeadh t kus okyh dkj ZkbZ kkW

5.1 vYi o"kkZrFkk vi; kZr o"kkZdh fLFkfr eadh t kusokyh dkjZkbZ, kkk&

3.1	VII O NETTRE VI; KET O NE CHI LINIT ESICHI LINUSKYII CHI DIOZENNA				
Øe	તીકું ઢોઇ , દૂ	ukMy foHkx@, t & h	YkkbZu foHkkx@,t&Uh	le; lhek	
1-	o"Wakr dh fuxjkuh ✓ जिला स्तर पर नियमित तौर पर वर्षापात के आंकड़ो का संग्रहण (प्रखण्ड स्तर पर) एवं विश्लेषण	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	जिला पदाधिकारी/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	1 जून से 31 अक्टूबर तक	
2-	i hus ds i kuh dh mi y Ukrk, oabl ds fy; s v kdfled; kt uk ✓ पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अनुरूप पूर्व तैयारी की समीक्षा तथा आकस्मिक योजना को अद्यतन करना। ¼s tylalVizaku grqekudlapkyu i fdz k v kink izaku folkkx ds osclkb% http://www.disastermgmt.bih.nic.in ij n kh t k l drh g 5/2 ✓ निर्माणाधीन पाइप जलापूर्ति योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना। ✓ बन्द पड़े चापाकलों की मरम्मित		जिला पदाधिकारी / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 मई तक	

5.1 vYi o"kkZrFkk vi; kZr o"kkZdh fLFkfr eadh t
 kusokyh dkjZkkV-contd.

Øe	d lġ ZlbZ k	ukMy foHkx@,t\$1 h	YNNbZu foHNx@,t&Ih	le; lhek
3-	vkdfLed Ql y ; kt uk ✓ सुखाड़ की स्थिति हेतु खरीफ फसल के लिये आकस्मिक योजना का सूत्रण/ आकस्मिक योजना को अद्यतन करना। पशु चारा को भी आकस्मिक योजना में शामिल किया जायेगा। ¼vkdfLed Ql y ; kt uk df'k foH&x ds oscl kb // http://krishi.bih.nic.in/ ij n﴿kh tk l drh g%		जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 जून तक
4-	Ql y chek सुखाड़ के संकेताकों और तात्कालिक रूझानों को देखते हुए मौसम आधारित फसलों का बुआई से पूर्व ही विशेष अभियान चला कर एवं किसानों को जागरूक कर फसल बीमा कराना।	सहकारिता विभाग	जिला पदाधिकारी / सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप 15 अगस्त से पूर्व।

5.1 vYi o"kkZrFkk vi; kZr o"kkZdh fLFkfr e ${\bf a}$ dh t
 kusokyh dkj ${\bf Z}$ kW......contd.

Øe	clkj ØkbZ kj	ukMy foHkx@,t\$1 h	YkkbZı foHkx@, t.XL h	le; lhek
5-	ा क्रफेZgrqvko'; d irák ✓ जिन जिलों में अत्य वर्षापात / सुखाड़ के कारण सिंचाई के पानी की कमी होने की संभावना है, स्थानीय स्थितियों के अनुरूप आकरिसक योजना तैयार करना। आकरिसक योजना में खरीफ की फसल के लिए बिचड़ा लगाने के लिए पानी की व्यवस्था एवं धान की रोपनी तथा इसके पश्चात supplementary irrigation के लिए विभिन्न स्तरों पर की जानेवाली कार्रवाइयों की सूक्ष्म रूप से व्याख्या होगी। ✓ सिंचाई हेतु अधिष्ठापित सभी ट्यूबवेलों को ससमय यांत्रिक दोषों के निवारण हेतु आवश्यक मरम्मित कराना। ट्यूबवेलों के विद्युत दोषों को दूर करने के लिए उर्जा विभाग से समन्वय करना। ✓ राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी ट्यूबवेलों में आवश्यक विद्युत आपूर्त्ति हेतु एक आकरिसक योजना तैयार करना। ✓ विद्युत दोषों के कारण बंद पड़े ट्रांसफार्मरों / ट्यूबवेलों को चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। ✓ ऊर्जा विभाग द्वारा आकरिसक योजना का सूत्रण करना । ¼/kdfLed; kt uk Åt ½/foHkx ds ocl kb¼/http://energy.bih.nic.in/ ij nq/kh t k l drh g5/2 ✓ आकरिसक योजना प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना आवश्यक होगा। ✓ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा भूजल सिंचाई से संबंधित विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं सुखाड़ के लिए युद्धस्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। ✓ नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुँचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।	लघु जल संसाधन/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग	जिला पदाधिकारी / लघु जल संसाधन/ जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 जून तक

5.1 vYi o"kkZrFkk vi; kZr o"kkZdh fLFkfr ea dh t kusokyh dkjZkkV-contd.

Øe	dkj ZkbZ k _j	ukMy foHkx@, t {] h	YMbZi foHkx@, t & h	l e; l lek
6-	tylaj{kkgrqvho'; dirák प्रारंभिक संकेतकों के विश्लेषण से यदि सूखे का आभास हो तो ✓ कम अवधि की जल संरक्षण (Short Term Water Conservation) संबंधी उपाय किया जाना। ✓ मनरेगा के अन्तर्गत Water Harvesting की योजनायें जैसे आहर, पाईन एवं तालाबों की मरम्मित इत्यादि का कार्य कराना। ✓ पारंपरिक सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों जैसे — तालाब, पोखर, आहर, पाईन आदि को रिचार्ज करने हेतु आवष्यक कदम उठाना।	लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी / लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 अप्रैल से 30 जून तक
7-	 Ikk kth dh mi yChrk ✓ राज्य खाद्य निगम के कार्यालयों / गोदामों में खाद्यान्न उपलब्धता का आकलन तथा आवश्यकतानुसार भंडारण सुनिश्चित करना। 	खाद्य आपूर्ति एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग	जिला पदाधिकारी / खाद्य आपूर्ति एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 जून तक।

$\begin{tabular}{ll} $$ $$ vYi $ o''kkZrFkk vi; kZr $ o''kkZdh fLFkfr e $adh t kuskyh dkj ZkbZ, kkW.....contd. \end{tabular}$

Øe	dkj ZkbZ k _i	ukMy	YMbZu foHkx@,t &U h	le;
		folkkx@, t & h		l hek
8-	How let have be the later of	आपदा प्रबंधन विभाग	जिला पदाधिकारी / जिला के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन) / जिला टास्क फोर्स	सतत् निगरानी।
9-	ekuo Lok.F; dh ng kkky ✓ सुखाड़ की स्थिति में संभावित बिमारियाँ की रोकथाम हेतु की जानेवाली कार्रवाईयों के संबंध में संधारित अनुदेष सभी सिविल सर्जन / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को निर्गत करेगा। उक्त अनुदेष में वर्णित निर्देषों के अनुरूप तैयारियाँ की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 603 (11) दिनांक−14.07.2015 द्वारा निर्गत अनुदेष दृष्टव्य	स्वास्थ्य विभाग	जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स	15 मई तक

5.1 vYi o"kkZrFkk vi; kZr o"kkZdh fLFkfr ea dh t kusokyh dkjZkbZ, kkW.....contd.

Øe	clkj 3kb Z k _j	ukMy foHkx@ , t & h	YkkbZı foHkx@, t &l h	le; lhek
10-	i'lql à l/lu dh ns lilley पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आकस्मिक योजना तैयार करना, जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ भी शामिल होंगी :─ ✓ पशुओं के लिए पानी एवं चारे की व्यवस्था करना। ✓ जलस्रोतों की पहचान एवं जल के संग्रहण के लिए लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित करना ✓ पशु राहत शिविर का स्थल चिन्हित करना। पशु शिविर यथा संभव राजकीय ट्यूबवेलों अथवा अन्य जल स्रोतों के आस—पास स्थापित किए जाएं ✓ पशुचारा का संग्रहण एवं आपूर्ति। ✓ सुखाड़ के समय पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था पूर्व से ही करना। कम नमी में जमने वाली घास बरिसम, शू बबूल एवं अन्य दूसरे पशु आहार की व्यवस्था या उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी लाईजन रखना होगा। ✓ सुखाड़ के दौरान पशुओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बिमारियों के लिए पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयों/टीका इत्यादि का प्रबंध करना। ✓ इस योजना को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना। ✓ मृत पषु/ पक्षियों के मृत शरीर को जलाने अथवा दफनाने का स्थान चिन्हित करना।	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग	जिला पदाधिकारी / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	15 जून तक

$_{5.1}\ vYi\ o"kkZrFkk\ vi; kZr\ o"kkZdh\ fLFkfr\ ea dh$ t kusokyh dkjZkbZkkW.....contd.

Øe	dkj žk b Z kj	ukMy	YNADZi foHkx@,t&lh	le;
		foHkx@,tLlh		l hek
11-	jkt xkj dh mi yl'krk ✓ रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार किये जानेवाले विभिन्न कार्यों की पहचान की जाएगी। ✓ मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर Shelf of Project or Bank of Sanctions पूर्व से ही तैयार रखना।	ग्रामीण विकास विभाग	जिला पदाधिकारी / ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	30 मई तक।
12-	Lekt d isk यृद्धावस्था पेशन का वितरण सुनिश्चित करना अत्रवृति का वितरण ससमय कराना तािक गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटे अच्चों एवं गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना * स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याहन भोजन का कार्यान्वयन कराना	समाज कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग	जिला पदाधिकारी / समाज कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स	30 मई तक।
13	I puk, oafefM; k dk i raku भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग से प्राप्त वर्षापात एवं फसल आच्छादन के आंकड़े का विश्लेषण कर सुखाड़ से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को प्रसाारित करने हेतु मिडिया को जानकारी देना।	आपदा प्रबंधन विभाग / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	जिला पदाधिकारी / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	

5- l q kkW+vki nk dh fofHkUk fLFkfr; ka ea dh t kus okyh dkj ZkbZ kkW 5.2 o"kkZ kr ea varjky gkus ij dh t kus okyh dkj ZkbZ kkW&

Øe	dkj Zkb Zk	ukMy foHkx@,till h	YkkbZi foHkkx@,t&lh
1	राज्य में फसल आच्छादन/ वर्षापात/	राज्य आपातकालीन प्रबंधन	जिला पदाधिकारी/जिला
	सिंचित क्षेत्र / भूगर्भ जल की स्थिति आदि के	समूह/आपदा प्रबंधन	टास्क फोर्स
	आंकड़ों की गहन समीक्षा करना तथा लिए	विभाग	
	गए निर्णय के आलोक में सभी संबंधित को		
	तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई के लिये आदेश		
	निर्गत करना		
2	डीजल अनुदान के माध्यम से लगाये गए	कृषि विभाग	जिला पदाधिकारी/कृषि
	बिचड़ों / फसलों को बचाने हेतु समुचित उपाय		विभाग के जिला स्तरीय
	करना।		पदाधिकारी / जिला टास्क
			फोर्स
3	नहरों के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी	जल संसाधन विभाग	जिला पदाधिकारी/ जल
	पहुँचाने की कार्रवाई में तेजी लाना एवं		संसाधन विभाग के जिला
	लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर कठिनाईयों को दूर		स्तरीय पदाधिकारी/
	करना		जिला टास्क फोर्स

5.2 o"kkZkr esavarjky gksus i j dh t kus okyh dkjokbZkkW.....contd.

Øe	dkj ökb ‡ k	ukMy foHkx@,t il h	YkkbZu foHkkx@,t&Ih
4	ट्यूबवेलों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र सिंचित	लघु जल संसाधन विभाग/	जिला पदाधिकारी/ लघु जल
	करने हेतु बंद पड़े ट्यूबवेलो की यांत्रिक	ऊर्जा विभाग	संसाधन विभाग / ऊर्जा
	एवंविद्युत दोष तुरन्त ठीक करना।		विभाग के जिला स्तरीय
			पदाधिकारी / जिला टास्क
			फोर्स
5	ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु विद्युत की आपूर्ति	ऊर्जा विभाग / बिहार स्टेट	जिला पदाधिकारी / ऊर्जा
	सुनिश्चित करना	पावर होल्डिंग कम्पनी	विभाग / बिहार स्टेट पावर
		लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के
			जिला स्तरीय पदाधिकारी/
			जिला टास्क फोर्स
6	पेयजल संकट से निपटने हेतु मानक संचालन	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	जिला पदाधिकारी / लोक
	प्रकिया के अनुरूप कार्रवाई करना	विभाग	स्वारथ्य अभियंत्रण विभाग के
			जिला स्तरीय पदाधिकारी/
			जिला टास्क फोर्स

5. 1 (kkM+vki nk dh fofHkUk fLFkfr; kaeadh t kus okyh dkj ZkbZ kkW

5.3 मॉनसून की समय पूर्व वापसी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाईयाँ

Øe	ડીકું ઝીઇ ટ્રે દ્વ	ukMy foHkx@,t&Ih	YkkbZu foHkkx@,t&Uh
1.	iş t y (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा पशु संसाधनों के लिए) आपूर्ति ✓ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों ∕ नलकूपों की मरम्मित करना। ✓ आवश्यकता का आकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने की व्यवस्था करना। ✓ जरूरत के अनुसार नये नलकूप / चापाकल लगाना। ✓ पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए उर्जा विमाग से समन्वय कर विद्युत आपूर्ति कराना। ✓ जरूरत के अनुसार पानी भरकर टैंकर / ट्रैकटर पर पी०वी०सी० टैंक बैठाकर पहुँचाने की व्यवस्था करना। ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण की व्यवस्था करना। ✓ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त सबमिसंबल पंप रखना तािक कहीं खराबी आने पर उसे तुरंत बदलकर जलापूर्ति चालू रखा जा सके। ✓ टैंकर एवं ट्रैक्टर पर पी०वी०सी० टैंकों को भरने के लिए हाइड्रेट का निर्माण करना। ✓ इस संबंध में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया को कियान्वित किया जायेगा। ¼iştylalVizaku grqviuk, tkusokyhekudl pkyu ifctzk vkink izaku folkox dsocl kb% http://www.disastermgmt.bih.nic.in ij nelk tkl drk g%2 ✓ शहरी अथवा नगर पंचायत क्षेत्रों में जलापूर्ति की शिकायत दर्ज करने एवं समस्या के त्वरित निष्पादन हेतु हेल्पलाइन की व्यवस्था करना।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (ग्रामीण क्षेत्र)/ नगर विकास विभाग (शहरी क्षेत्र)	जिला पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare & \blacksquare & A & $$

Øe	dkj ö kb Z kj	ukMy	Ykkb Z i
		foHkx@,t&lh	foHkx@,t & h
2-	o&dfYid@vkdfLedQly;ktuk		जिला
	🗸 पूर्व से तैयार आकस्मिक फसल योजना का क्रियान्वयन करना।		पदाधिकारी /
	✔ किसानों को आकस्मिक फसल योजना में निहित उपायों को इस्तेमाल करने		कृषि विभाग के
	हेतु प्रोत्साहित करना तथा इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना।	कृषि विभाग	जिला स्तरीय
			पदाधिकारी /
			जिला टास्क फोर्स
3-	Qlychek@df"k .k		
	✓ फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि सभी कृषक आच्छादित न हो तो		जिला
	अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित करना। इस		पदाधिकारी /
	कार्य में छोटे किसानों पर विषेष ध्यान रखा जाएगा।	सहकारिता	सहकारिता
	प्राप में अंट विस्ताना पर विषय व्यान रखा आर्नान	विभाग /	विभाग / सांस्थिक
	🗸 कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना।	ापमाग् सांस्थिक वित	वित के जिला
		सारथक वित	स्तरीय
			पदाधिकारी /
			जिला टास्क फोर्स

$\begin{tabular}{ll} \hline \square & E-$kW1 w dh l e; i-$wZ okilh dh $fLFkfr$ e a-$dh t $kus okyh $dkjZ kbZ kWcontd. \\ \end{tabular}$

Øe	dkj ö kb Z k	ukMy	Ykkb Z i
		foHkx@,t Ll h	foHkx@,t41 h
4-	Mt y vunku forj.k आवश्यकतानुसार बिचड़ों एवं फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए डीजल अनुदान उपलब्ध कराना। फसल बचाने के लिए कितनी बार डीजल अनुदान दिया जाय इसका निर्णय आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप किया जायेगा। ✓ डीजल अनुदान का वितरण पंचायत राहत एवं अनुश्रवण समिति की देखरेख में कराना। ✓ अनुदानित बीज का वितरण कराने की व्यवस्था करना। ✓ कृषि सुझावों/बुलेटिन का समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों से प्रभावित कृषकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कराना।	कृषि विभाग	जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स
5-	osalfyi d fl splkbzQ olfkk		
	√ सिंचाई हेतु अधिष्ठापित सभी ट्यूबवेलों को कार्यरत रखना। ससमय आवश्यक मरम्मित		जिला पदाधिकारी/
	कराना। ट्यूबवेलों के विद्युत एवं यांत्रिक दोषों को भी दूर करने के लिए आवश्यक कदम		लघु जल संसाधन
	उठाना।	लघु जल संसाधन	विभाग
	🗸 ग्रामीण क्षेत्रों (अति प्रभावित) के लिए पर्याप्त (कम से कम ८ घंटे) विद्युत आपूर्त्ति	विभाग	/बिहार पावर
	सुनिश्चित करना।	/बिहार पावर	होल्डिंग कॉरपोरेषन
	सिंचाई आदि के लिए आवश्यक है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल का समुचित	होल्डिंग कॉरपोरेषन	लि0 / जल संसाधन
	प्रबंधन किया जाए :	लि0 / जल संसाधन	विभाग /
	🗸 विभिन्न प्रक्षेत्रों यथा– उद्योग, कृषि आदि में जल की मांग का आकलन करना।	विभाग /	लघु जल संसाधन
	🗸 किसानों को सिंचाई के लिये नहर से आच्छादित क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने	लघु जल संसाधन	विभाग
	हेतु आवश्यक प्रबंध करना।	विभाग	के जिला स्तरीय
	राज्य के प्रमुख जलाशयों एवं अन्य सतही जल स्रोतों पर निगरानी रखना ताकि इसके		पदाधिकारी / जिला
	दुरूपयोग से बचाया जा सके।		टास्क फोर्स

5.3 ENNAMI w dh l e; i waZoki l h dh fLFM r e a dh t kus okyh dhj \mathbf{Z} NaWcontd.

Øe	cl∮ ઝીઇ ℤ կ	ukMy	YMbZi
_	EN LIVE 1 - O	foHkx@,tLlh	foHkx@,t41h
6-	[kk kii 1 j {kk ✓ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न की उपलब्धता एवं इसके उठाव का अनुश्रवण करना। ✓ मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था करना। ✓ केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करना। ✓ खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि पर सतत् निगरानी करना। मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि से राज्य सरकार को अवगत कराना। ✓ मूल्य वृद्धि रोकने हेतु जमाखोरी, काला बाजारी आदि पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	जिला पदाधिकारी / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स
7-	Ik kql à k/ku dh ns[kHky		
	 ✓ पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ✓ विन्हित पशु शिविरों में जल की व्यवस्था करना। ✓ पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण करना। एंटी—बायोटिक्स, एनालजेसिक, पारासिटामोल, एंटी—हिस्टास्टामिनिक, एंटी— डायिरयल, लीवर टॉनिक, नॉरमल सलाईन, एलेक्ट्रोलाइट इन्यूजन लिक्विड, आदि का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। 	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	जिला पदाधिकारी/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी/ जिला टास्क फोर्स
	🗸 मृत पशुओं के शवों के सुरक्षित निपटान (विसर्जन) की त्वरित व्यवस्था करना।		

5.3 ENNANT we do le; i we Zokilh dh fLFM r eardh t kus okyh dkj Zokocontd.

Øe	dlý Zlb Z k	u kM y	YkłbZi
		foHkx@,t41h	foHkx@,tLlh
8-	fo q ∨ ki fr Z ✓ कृषि एवं अन्य कार्यों जैसे पम्प, नहर योजनाएँ, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएँ एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत आपूर्त्ति सुनिश्चित करना। ✓ सुखाड़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अलग—अलग क्षेत्रों के लिए अलग—अलग समय निर्धारित करते हुए इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना।	ऊर्जा विभाग / बिहार पावर होत्खिंग कम्पनी लि0	जिला पदाधिकारी / ऊर्जा विभाग / बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि० के जिला स्तरीय पदाधिकारी / जिला टास्क फोर्स
9-	े फ़ुप्प i रक्षिप , oaelfM: k ds l lefk l elb: सुखाड़ आपदा के पूर्व सूखा के संकेतकों एवं आपदा के समय कृषि विभाग के द्वारा फसलों के बचाव आदि से संबंधित बुलेटिन जारी किया जाना। समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया माध्यमों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना।	कृषि विभाग / सूचना एवं जन संपर्क विभाग	जिला पदाधिकारी / कृषि विभाग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी

5.4 दक्षिण—पूर्व मॉनसून की अवधि में बिल्कुल वर्षा न होना

दक्षिण-पूर्व मॉनसून की अवधि में बिल्कुल वर्षा न होने की स्थिति में पूर्व वर्णित कार्रवाईयों के अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्णय अनुसार लगान वसूली, त्रृण वसूली आदि पर रोक लगाई जा सकती है।

6. सुखाड़ की घोषणा

- आपात कालीन प्रबंधन समूह की बैठक में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा एवं संकेताओं का विश्लेषण
- ❖ जिला पदाधिकिरयों से जिला / प्रखंडों में खरीफ फसल के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेताओं के आलोक जिला पदाधिकारी का स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करना
- आवश्यकतानुसार प्रमंडलीय आयुक्त / जिला के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेजकर जमीनी हकीकत का पता लगाना तथा सुखाड़ घोषणा के संबंध में स्पष्ट अनुषंसा प्राप्त करना
- ❖ प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सुखाड़ घोषित करने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह के द्वारा राज्य स्तर पर अनुषंसा भेजा जाना
- ❖ कृषि विभाग के द्वारा विधिवत् प्रस्ताव का आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाना
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संलेख तैयार करना एवं इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रिपरिषद) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा संबंधी अधिसूचना निर्गत किया जाना। तत् पश्चात् यथा स्थिति कार्रवाइयों को प्रारंभ करना

. सुखाड़ की घोषणाContd.

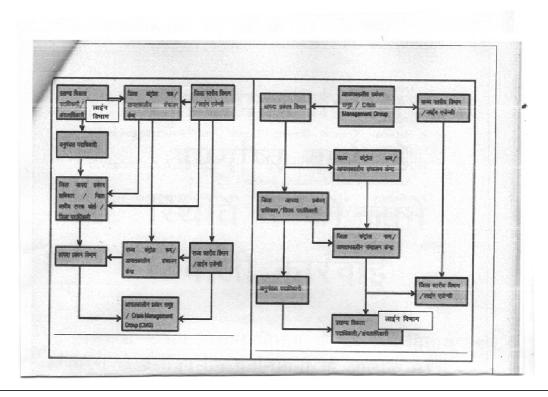
- आपात कालीन प्रबंधन समूह की बैठक में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा एवं संकेताओं का विश्लेषण
- जिला पदाधिकिरयों से जिला / प्रखंडों में खरीफ फसल के आच्छादन, वर्षापात की स्थिति एवं अन्य संकेताओं के आलोक जिला पदाधिकारी का स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करना
- आवश्यकतानुसार प्रमंडलीय आयुक्त / जिला के प्रभारी सचिव अथवा राज्य स्तर के पदाधिकारियों की टीम भेजकर जमीनी हकीकत का पता लगाना तथा सुखाड़ घोषणा के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करना
- ❖ प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सुखाड़ घोषित करने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह के द्वारा राज्य स्तर पर अनुशंसा भेजा जाना
- 💠 कृषि विभाग के द्वारा विधिवत् प्रस्ताव का आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाना
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में संलेख तैयार करना एवं इसका अनुमोदन राज्य सरकार (मंत्रिपरिषद) से प्राप्त कर सुखाड़ की घोषणा संबंधी अधिसूचना निर्गत किया जाना

7. सुखाड के निर्धारित सकताक

आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक—3759 दिनांक—18.10.16 के माध्यम से राज्य में सुखाड़ की घोषणा हेतु निम्न संकेतांक/आधार निर्धारित किये गये है:-

- √ वर्षापात— माह जून से 31 अगस्त के बीच वर्षापात में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक
 की कमी
- ✓ खरीफ फसलों का आच्छादन— 31 अगस्त तक 50 प्रतिशत से कम होना
- √ अन्य आधार –
- मॉनसून के आगमन में देरी अथवा मॉनसून के कमजोर रहने संबंधी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान
- वर्षा की कमी के कारण भूजल एवं सतही जलस्रातों के स्तर में कमी
- वर्षापात में कमी के कारण फसलों का सूखना / / मुरझाना (wilting)
- वर्षापात की कमी के कारण धान के खेतों में नमी का कम होना
- मॉनसून की समय पूर्व वापसी

8. संचार योजना



धन्यवाद







vLirkyknen v f Xulslýn (kkizákudsfy, ekud l pokyuizídzk

MkO xxu

vu**ęM**yk, ykd f'kdk, r fuokj.k i nkf/kdkjh egukj ½8 kkyh½

i Łrardj.k; kt uk

- 1. l LFkRed < kWk
- 2- vfXu lslj{kk gsrqivvZr\$, kfj; ktN
- 3- vkx yxus ds le; dh t kus okyh कार्यवाईयो
- 4- vkx yxus ds i'pkr~ dh tkus okyh dkjokbZkW

1. l **1. FkkR**ed < k**y** k

- ❖ LokLF; foHkx dh dk; Zdkjj.kh l fefr
- ukMy foHkx &LokLF; foHkx
- ❖ jkT; ds vU; foHkx
- vki nk i zaku foHkx
- x\u00e0 foHkx
- mt lZfoHkx
- uxj fodkl, oavkokl foHkx
- ykxd LokLF; vfHx, a=. k foHkx
- Hou fuelZk foHkx
- lyvuk tu lådZfoHkx
- funsky;] ukxfjd l jj{kk
- funšky;] gkexkMZ
- funskky;] vfXu'keu l sok, W

1. l LFkRed <kW/kcontd.

- ft ykaea xfBr dk, Zdkj.kh l fefr ½ft yk vkink i záku i ½f/kdj.k ds varx½f
- ft yk i nkf/kdkj h&?kVuk dekMj
- i ½ kM Lrjh, ?kVuk fu; æ. k ny

2. vfXu lslj{kk gsrqivvZr\$kfj;kW

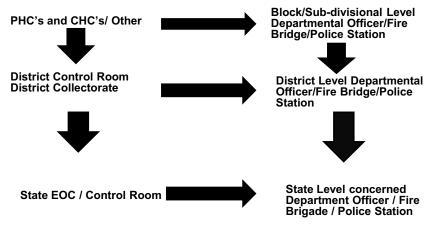
- 2-1 fo/kgr l #LFkki uka dh ns[k&Hkky
- 2-1-1 fujh(k k
- 2-1-2 j [k&j [kko
- 2-1-3 det kj, oankski wkZi t kadks cnyuk
- 2-1-4 fo | or | 'kfDr iznku djusokysmidj. kkadsfo | or | a ktu, oaeW; kadr; kW; rk, oadl usdh t kW
- 2-1-5 $j[kkj[klo] l \dot{g}\{kk i j h(k k, oal \dot{g}\{kk l \dot{g}kkj clk, Z; kt uk$
- 2-2 fo | or 1 s1 ac a/kr; a=ks dkj [k&j [kko
- 2-3-1 $\sqrt{1}$ \sqrt
- ikWscy vfXu'kled; a=
- gknt jhy
- vkWkesVd Librdy1.
- eSucyy dkW, ykeZ
- /kbp/klalyou;a=
- rki lalpou;æ
- vfXujk/kh njokt k

vfXu 1 s 1 j {kk gsrqi wZr\$ kfj; kt....contd.

- 2-3-2 vfXu lj{kkgrqty HaMg.kdhQoLFkk
- 2-4 vkx yxus dh?kVuk dh i wZi Hkfor t xgkal svfrfjDr fudkl dh Q oLFkk
- 2-5 vfXu l sl #Hvfor gkusokyh l #Hvfor txgka, oa HvfM&HvM+okyh txgkadh igpku, oautjh&uD'kkr\$kj djuk
- 2-6 lakku ekufp= % vfrfjDr 'k\$;kļ vfrfjDr LV\$pj V\$\$\hat{y}h c\$M\$ tju\$\/j l\$\/] V\$\/] nok v\/fn
- 2-7 jlgr, oacplo nyksdk xBUk@QMRT
- 2.8 नोडल पदाधिकारी / पर्यवेक्षकों की पहचान
- 2.9 अस्पतालों से जुड़ी मुख्य सड़कों की पहचान
- 2-10 vki kr dkyhu l apkyu dsinzdk l fdz. k
- 2-11 l apkj; kat uk

vfXu 1 s 1 j {kk gsrqi wZr\$ kfj; kt....contd.

l pouk i zokg



3. vkx yxus ds le; dh t kus okyh dkj oko Z kW

- ❖ iwZpsrkouh
- ❖ vkx yxus dh l youk dk i xk k
- i Heldfor txgkaij i fi kf{kr dfe Z kadk i fj fu; kt u
- i #Hofor 0, fDr; ka dk fu"dæ. k
- v'kOr ejht ka; Fkk xHzörh ekrkvkæ/kkr` ekrkvkæf'k'kykadh nslk&Hky
- ❖ isty dh 0, oLFkk
- ❖ vko'; d l sokvkadk Rofjr i quLFkklu
- ❖ ft yk@jkT; Lrjh, dk, Zhkfj.kh l fefr dh c\$Bd
- erdkads 'kokadk fui Vku
- erdkads vkf Jrkadks vuckg vucku dk Hogerku

- 3. vkx yxus ds le; dh t kus okyh dkj okb / kt/ contd.
- ❖ jkgr, oacpko dk, katea LFkkuh, leqnk, ka, oaukxfjd
 lax Buka dh Hkxhnkjh
- x5 ljdkjhlaLFkkuks@varjk"Vhr, ,ts1; ks@vU; jkT;
 ljdkjks@dkj%lkjsVlsDVj@0; fDr; ksa}kjk jkgr एवं बचाव
 dk; kaZesalg; ksx
- ❖ Lhouk, oafefM; kdkizáku
- ❖ Thu f'kdk, rhadk fui Vhu
- ❖ vkx yxus ds nkỹ ku i źrosnu dk i żk k
- ft yk / i ½ kW/uxj / i pok, r / Lrjh, vfXu l j {kk vuoJo. k&l g&fuxjkuh l fefr; kadh c\$Bd

4. vkx yxus dsi'pkr~dh t kus okyh dkj okb Z kW

- ❖ vkx yxus ds nkỹ ku i źrosnu dk i ¾k k
- ft yk / i½ k¾/uxj / ipk, r / Lrjh, vf¾u lýj{kk vuýo. k&l g&fuxjkuh l fefr; kadh c\$Bd
- jkgr forj.k
- {kfr dk vkadyu&Hkkxkfyd {ks=] i Hkkfor l eqnk,]
 er@[kks, s 0, fDr
- vk/kkj/knv/ljipukvknadh/kfr/dk/vkdyu

- 4. vkx yxus ds i 'pkr~dh t kus okyh dkj okb.\(k\) ... contd.
- vfXu jkgr d\$i dh 0, oLFkk ½vkink izzáku foHkx ds}kjk i wZesfux²r ekxZfun§'kdk dsvul kj½
- > {kfr&xLr vk/kkj How ljpukvkadk <u>iquLFkkiu@iqufuZekZk</u>
- vkx yxus ds ckn vare i zrosnu dk i zk k
- folkh, 1 gk, rk dh 0, oLFkk&nok@LokLF; 1 qo/kk, kkgsrq , oavfXudkM fi fMr 0, fDr; kads vLi rkyhdj. k dh fLFkfr vuqxg jkf'k gsrq

- 4. vkx yxus ds i 'pkr~dh t kus okyh dkj okb Z kW...contd
- ljdkjh vLirkyka e a vko'; dlsokvka dhi quc Zekyh, oa i qufu Ze k
- jkgrdk, kalea0, ; dh xbZjkf'k dk mi; kfxrk i zek k i = dk i zk k
- dr dkji 15kb; knadk varfu 15kkk, oa Hofo"; ds fy, lh[k 4ekuo cy] n q 15y i {k] volj, oa df Bukb 15, knads e W; knadu ds v k/kkj i j

अनुलग्नक - 1 अग्नि से सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारियों की चेकलिस्ट

<u>s</u> p.	की जाने वाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1.	अग्नि से सुरक्षा संबंधी यंत्रों की मरम्मत / देखभाल (यदि पूर्व से अवस्थित हो)		
2.	अग्नि से सुरक्षा संबंधी यंत्रों को यथोचित स्थलों तक नियमानुकूल लगाने की व्यवस्था (यदि पूर्व से नहीं उपलब्ध हो तो)	ferred o	
3.	संभावित क्षेत्रों (संवेदनशील) / जगहों की पहचान एवं नक्शा तैयार करना।		
4.	संसाधन मानचित्र।		
5.	विद्युतचलित उपकरणों, विद्युत संचरण लाइन इत्यादि की मरम्मत एवं देखमाल।		1.0
6.	विद्युत संचरण हेतु ट्रांसफॉर्मर की स्थिति।		
7.	जेनरेटर, पेट्रोमेक्स, बैट्रीचलित प्रकाश उपकरण आदि की उपलब्धता (आकस्मिकता हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत)।	That	96 j. es
8.	संबंधित दवाओं की समुचित मात्रा में उपलब्धता।		
9.	मरीजों / परिजनों के निष्क्रमण हेतु कार्य योजना की तैयारी ।		
10.	परिजनों के उपचार एवं मरीजों के अनवरत उपचार सहित निष्क्रमण कार्य योजना।		
11.	मरीजों / परिजनों के निष्क्रमण के पश्चात सुरक्षित स्थल की पहचान।		
12.	जलस्रोत एवं जल भंडारण की उपलब्धता।		
13.	आपात्कालीन निकास की व्यवस्था।		
14.	नोडल अफसर की पहचान / पर्यवेक्षक की नियुक्ति।		
15.	अस्पतालों तक पहुँच सड़कों की स्थिति (व्यवस्थित आवागमन हेतु)।		
16.	आपात्कालीन संचालन / नियंत्रण कक्ष को कार्यान्वित करना।		
17.	संचार योजना।		
18.	प्रशिक्षित कर्मियों के परिनियोजन हेतु आकस्मिक योजना।		
19.	प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक कार्यकारिणी समिति।		
20.	संबंधित विभागों द्वारा आकस्मिक योजना का सुत्रण।	Term 1	

अनुलग्नक - 2 आग लगने के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की चेकलिस्ट

sh.	की जाने वाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1.	आग लगने के पूर्व चेतावनी (चेतावनी उपकरणों द्वारा प्राप्त संकट सूचना) का आकलन एवं त्वरित कार्रवाई।		
2.	आग लगने की सूचना का प्रेषण।	PFF	BE TO
3.	प्रशिक्षित कर्मियों का परिनियोजन।		
4.	प्रभावित मरीज एवं परिजनों का निष्क्रमण।		
5.	क्षति का त्वरित आकलन।		
6.	अग्निशमन विभाग /एस०डी०आर०एफ० से सहायता की माँग।		
7.	सेना /एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मांग (आवश्यकतानुसार आग की विभीषिका के अनुरूप)।		
8.	निष्क्रमित प्रभावित मरीज एवं परिजनों के इलाज की व्यवस्था।		
9.	अशक्त वर्ग यथा गर्भवती महिला, धातृ महिला / बच्चों के इलाज को सर्वोच्च प्राथमिक्ता।		
10.	फायर फाइटिंग के लिए जल संग्रहण की व्यवस्था।		
11.	पेयजल की व्यवस्था।		
12.	बिजली एवं दूरसंचार व्यवस्था की पूनर्स्थापना।		
13.	आवागमन की व्यवस्था (दमकल/रोगी वाहन इत्यादि)।		
14.	सूचना एवं मीडिया का प्रबंधन।		
15.	मृतकों के शवों का निपटान।		
16.	बचाव कार्यों में स्थानीय समुदाय एवं नागरिकों की भागीदारी।		
17.	गैर सरकारी संस्थानों / अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों / अन्य राज्य सरकारों / कॉरपोरेट सेक्टर / ब्यक्तियों द्वारा बचाव / राहत कार्यों में सहयोग।		
18.	जन शिकायतों का निपटान।	THE P.	
19.	आग लगने के दौरान/आग लगने के पश्चात प्रतिवेदन का प्रेषण।		
20.	राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स कोष से राशि प्राप्त करने हेतु मेमोरेंडम का सूत्रण।	261 159	HOS DE

अनुलग्नक - 3 आग लगने के पश्चात की जानेवाली कार्रवाइयों की चेकलिस्ट

क्र.	की जाने वाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1.	राहत वितरण (अग्नि की विभीषिका एवं क्षति के अनुरूप)।		
2.	पूर्ण क्षति का आकलन।		
3.	अग्नि राहत कैंप की व्यवस्था (यदि अग्नि विभीषिका ज्यादा हो)।		
4.	आधारभूत संरचनाओं की क्षति का आकलन।		17 SH
5.	क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण।		
6.	आग लगने के बाद अंतिम प्रतिवेदन का प्रेषण।		
7.	वित्तीय सहायता।		
8.	राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यदि आवंटन प्राप्त हुआ हो)।		
9.	कृत कार्रवाइयों का अंतर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)A		

21. जिला, प्रखंड / नगर एवं पंचायतस्तरीय अग्नि सुरक्षा अनुश्रवण—सह— निगरानी समितियों की बैठकें।

धन्यवाद



vkink izaku foHkkx

आपदा प्रबंधन संबंधी प्रपत्र एवं प्रतिवेदनों का प्रेषण

lgk; d vunnku Islacaf/kr mi; ksfxrk iæk.k&i= (BTC-42A) Hkjusgsnaekxan'kad fooj.kh%&

- 1. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला को दिये गये प्रत्येक आवंटन पत्र / स्वीकृत्यादेश के लिए अलग—अलग उपयोगिता प्रमाण—पत्र (BTC-42A) तैयार किया जाना है।
- 2. बीटी0सी0 42ए0 प्रपत्र के उपरी भाग में बायें तरफ बने हुए बॉक्स में सहायक अनुदान मद के आवंटन के शीर्ष, उप आवंटन शीर्ष आदि तथा दाहिने तरफ बने हुए बॉक्स में ट्रेजरी कोड, डी0डी0ओ0 कोड एवं बिल कोड भरा जाना है।
- 3. प्रपत्र की कंडिका—1 में संबंधित आवंटन पत्र के माध्यम से आवंटित कुल राशि, उसमें से व्यय की गई राशि एवं शेष बची राशि को अंकित किया जाना है। यदि इस आवंटन की पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पाया हो और उसे प्रत्यर्पित किया गया हो, तो प्रत्यर्पित राशि एवं संबंधित प्रत्यर्पण पत्र की संख्या एवं तिथि अंकित की जानी है। ध्यान रहे कि प्रत्यर्पण की स्थित में प्रत्यर्पण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति इस उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

yxkrkj-----

- 4. उपयोगिता प्रमाण—पत्र (BTC-42A) पत्र के भाग—ए में संबंधित आवंटन के विरुद्ध अआहरित (Undrawn) राशि, प्रत्यर्पण की स्थिति में प्रत्यर्पित राशि एवं प्रत्यर्पण पत्र संख्या एवं तिथि अंकित किया जाना है। यदि निकासी की गई राशि में से पूरी राशि का उपयोग/खर्च नहीं हो सका हो तो शेष बची हुई राशि चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा किये जाने वाली राशि को भी इस भाग में अंकित किया जाना है। ध्यान रहे कि बची हुई राशि चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा करने की स्थिति में संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान सं० सहित उस चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति इस उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 5. उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) की कंडिका—2 में व्ययों के नियंत्रण हेतु अंचल कार्यालय में जो अभिलेख संधारित किये गए हो एवं जिनकी जॉच के आधार उपयोगिता प्रमाण—पत्र (BTC-42A) तैयार किया गया है उसका वर्णन किया जाना है यथा रोकड़ बही, बिल रजिस्टर, भाउचर आदि।

yxkrkj-----

- 6. उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) की कंडिका—3 के टेबुल के कॉलम—2 में सहायक अनुदान के आपदा प्रबंधन विभाग के आवंटन पत्र संख्या एवं तिथि lfcl limble lfcl lfcl es bl dkbye es mi vkolvu i = la[;k;k vl]; dkbl i = la[;k vfdr ughl fd;k tkuk gsl/] अनुदान प्राप्त करने वाले पदाधिकारी अर्थात् जिला के डी०एम०, कॉलम—4 में कार्यालय, सहायक अनुदान के उदेश्य, कॉलम—5 में की गयी निकासी से संबंधित विपत्र संख्या एवं तिथि, कॉलम—6 में निकासी की गई राशि, कॉलम—7 में संबंधित टी०भी० संख्या एवं तिथि, कॉलम—8 में व्यय की गई राशि, कॉलम—9 में शेष बची हुई राशि, कॉलम—10 में प्रत्यर्पित राशि (प्रत्यर्पण पत्र सं० एवं तिथि सहित) तथा कॉलम—11 में यदि नकद बची राशि चालान से कोषागार में जमा की गई हो तो संबंधित चालान की सं० एवं तिथि का विवरण अंकित किया जाना है।
- 7. इसके उपरांत कंडिका—3 के टेबुल के नीचे जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर यथा स्थान होना आवश्यक होगा। यदि जिला पदाधिकारी के बदले उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर रहे हो, तो एतद् संबंधी प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
- 8. इसके नीचे जो विहित प्रमाण—पत्र अंकित है उसे भरकर दाहिने तरफ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मृहर रहना आवश्यक होगा।

yxkrkj-----

- 9. इस विहित प्रमाण-पत्र के बाये तरफ हस्ताक्षर का जो स्थान बना हुआ है वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। वहाँ पर किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना है।
- 10. ध्यान रहे कि उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) की कंडिका—3 में सहायक अनुदान के आवंटन पत्र कॉलम में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गए आवंटन/स्वीकृत्यादेश की संख्या एवं तिथि अंकित की जानी है। fdl h Hkh fLFkfr en bl dkWye en mi vkon/u i = la[; k; k vVI; dkb/l i = la[; k vfdr ugha fd; k tkuk gA ijrq ftyk inkf/kdkjh }kjk fuxir mi vkon/u i = dh vfHkiækf.kr Nk; kifr mi; kfxrk iæk.k i = ds l kFk layXu fd; k tkuk vko'; d gkxkA
- 11. ध्यान रहे आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये प्रत्येक आवंटन पत्र के लिए अलग—अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) तैयार किया जाना है। एक ही शीर्ष में दो आवंटन पत्रों के द्वारा दिये गये आवंटन के लिये भी अलग—अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना पड़ेगा।

yxkrkj-----

- 12. प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A) के साथ तीन प्रतियों में चेक लिस्ट जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा मुहर सिहत हस्ताक्षरित हो, को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। चेकलिस्ट के विवरण कॉलम में खाली जगह पर उस चेक लिस्ट से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की संक्षिप्त विवरण यथा आवंटन पत्र संख्या एवं तिथि, आवंटित राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि विपत्र कोड, ट्रेजरी कोड आदि भरना आवश्यक है।
- 13. प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण-पत्र (**BTC-42A**) के साथ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत संबंधित आवंटन पत्र / स्वीकृत्यादेश की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 14. प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण-पत्र (**BTC-42A**) के साथ उसमें अंकित निकासी के विपत्र संo एवं टीoभीo संo से संबंधित **CTMIS** की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
- 15. उपयोगिता प्रमाण—पत्र के अन्तिम कंडिका में जो प्रमाण—पत्र संबंधी दो विन्दु दिये गये है उनमे से '1'(एक) या '2' (दो) जो भी लागू हो, उसपर टिक करना आवश्यक है। यदि सहायक अनुदान से हुए व्यय का अंकेक्षण हो चुका हो तो बिन्दु—1 टिक करना है और यदि अंकेक्षण नहीं हुआ हो तो बिन्दु—2 टिक करना होगा।

yxkrkj -----

- 16. उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने हेतु उपर्युक्त कागजातों को निम्नांकित क्रम में संलग्न कर प्रस्तुत किया जाय:-
 - (क) चेकलिस्ट-तीन प्रतियों में
 - (ख) उपयोगिता प्रमाण-पत्र
 - (ग) सी०टी०एम0आई०एस0
 - (घ) शेष राशि प्रत्यर्पण की स्थिति में प्रत्यर्पण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति
 - (ड़) यदि निकासी के उपरांत अव्ययित राशि कोषागार में जमा की गई है तो कोषागार चालान (कोषागार के मुहर एवं हस्ताक्षर एवं चालान संख्या सहित) संबंधित कोषाागार पदाधिकारी द्वारा चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - (च) विभागीय आवंटन पत्र (अभिप्रमाणित).
 - (छ) जिला पदाधिकारी का उप-आवंटन पत्र (अभिप्रमाणित)
 - (ज) यदि उपयोगिता प्रमाण—पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होकर उनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है, तो जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(उपर्युक्त सभी क्रमांक—'ग' से 'ज' पर अंकित कागजात सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक होगा।)

yxkrkj-----

- 16. विभागीय आवंटन पत्रवार उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संक्षिप्त विवरणी, जिसमे निकासी की गई राशि, व्यय की गई राशि, प्रत्यर्पित राशि एवं चालान से जमा की गई राशि अलग—अलग कॉलम में दर्शायी गई हो तथा प्रत्येक कॉलम का कुल योग अंकित किया गया हो, संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 17. उपयोगिता प्रमाण-पत्र (BTC-42A) के सभी कॉलमों को भरना आवश्यक है। इसका कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहना चाहिए। जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

UTILIZATION CERTIFICATE

BTC FORM-42A

FORM FOR UTILIZATION CERTIFICATE

(See Rule 271)

Not Payable at treasury

Major Head	Treasury Code								
Sub Major Head	DDO Code								
Minor Head	Bill Code								
Sub Head									
UTILIZATION CERTIFICATE NO/ Bill No									
	Certified that out of Rsof Grants-in aid sanctioned during the year								
table below and Rson accoun	under this Department letter no. given in the t of unspent balance of the previous year, a purpose for which it was sanctioned and that nutilized at the end of the ered to the Govt. vide letter No								

yxknkj
For the grant to Government Offices for various schemes. Certified that the remaining undrawn grant amount Rs
• •
•
•Others



3. Particulars of Grants-in aid:

SI.	Sanction/	Name of	Purpose of	Bill	Amount	T.V	Amount	Balance	Amount	Challan
No.	Allotment	the	the grant/	No.	of grants	No.	UC	amount	Surrendered	No. &
	letter No.	grantee	name of	Date	drawn	&			(with letter	Date
	and date	Institution	scheme			date			no.& date)	
		/ Office								
	2	3	4	!	6		8	9	10	1
										1

(District Magistrate or officer authorised by him)

Signature & Stamp of Grantee Agency/ Institution/ Office

This is certified that-

- 1. Audited Accounts Reports has obtained from the Grantee Agency/ Institution& the same has been kept in this office.

Counter Signature
By Sanctioning Authority/ Officer
Authorized by him

Signature & Stamp of Drawing & Disbursing Officer for the Grant-in-Aid

, uDI pj&A thOvkbD, O Is I ref/kr mi; kfxrk i rek. k&i = MBTC-42A½ ds I kFk I ayXu fd; k tkus okyk **Check List** fudkl h jkT; knsk@LohdR; kns Ø fooj.k egkys[kkdkj ∨fHk; **(**fD , oa 0; ; u 'k fuxir djus okys $dk; k y; \} k j k$ i nkf/kdkj h inkf/kdkjh ∨Fkok i kj fEHkd t kjp ukfer inkf/kdkjh ea i nkf/kdkfj; ka dk iæk.k&i =}kjk tkip djusij dk i = k.k = i¼gki djuk Mh0Mh0∨k**0** dk I ghik; k x; kiek.k&i = 1 gh ik; k ; k ugha I gh g% ik; s tkus i j x; k; k ugha I gh ik; s tkus i j gkj gki djuk gs djuk g\$ vI; Fkk ugha ∨U; Fkk ugha djuk g\$A djuk gA उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग के माध्यम से प्राप्त है। Utilisation फार्म 42A में है एवं दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामले में वित्त विभाग के पत्रांक 1310 दिनांक 07.02.2014 के द्वारा संशोधित फार्म में है।

yxkrkj-....

3	Utilisation Certificate Sanctioning		
	Authority द्वारा अथवा विभाग द्वारा नामित		
	पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। (नामित होने के		
	मामले में संबंधित आदेश की प्रति संलग्न होनी		
	चाहिए)।		
4	इस कार्यालय में उपलब्ध डाटा बेस के अनुसार		
	T.V.No.&Date से राशि का मिलान किया		
	गया है। मिलान नहीं होने के स्थिति में		
	कोषागार का प्रमाण-पत्र अथवा CTMIS की		
	सत्यापित प्रति संलग्न है।		
5	प्रत्येक Sanction के विरूद्ध अलग–अलग		
	Utilisation दिया गया है।		
6	D.D.O. एवं Grantee		
	Agency/Institution का Utilisation		
	Certificate का पर हस्ताक्षर स्वीकृत्यादेश के		
	अनुरूप है।		

yxkrkj-....

Utilisation Certificate Form 42A				
पर सभी सूचनाएँ पूर्णरूप में है।				
स्वीकृत्यादेश के अधीन सभी आवंटन				
आदेश संलग्न है।				
स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से				
संबंधित है, संलग्न है।				
स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता				
प्रमाण–पत्र का समेकित राशि T.V. No.&				
date के साथ है				
Kinds of check exercise में सूचना				
पूर्ण है।				
दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों				
में Audited Column की बिन्दु (1) एवं				
(2) में से किसी एक का चयन किया गया				
है।				
	पर सभी सूचनाएँ पूर्णरूप में है। स्वीकृत्यादेश के अधीन सभी आवंटन आदेश संलग्न है। स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है। स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समेकित राशि T.V. No.& date के साथ है Kinds of check exercise में सूचना पूर्ण है। दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में Audited Column की बिन्दु (1) एवं (2) में से किसी एक का चयन किया गया	पर सभी सूचनाएँ पूर्णरूप में है। स्वीकृत्यादेश के अधीन सभी आवंटन आदेश संलग्न है। स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है। स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समेकित राशि T.V. No.& date के साथ है Kinds of check exercise में सूचना पूर्ण है। दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में Audited Column की बिन्दु (1) एवं (2) में से किसी एक का चयन किया गया	पर सभी सूचनाएँ पूर्णरूप में है। स्वीकृत्यादेश के अधीन सभी आवंटन आदेश संलग्न है। स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है। स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण—पत्र का समेकित राशि T.V. No.& date के साथ है Kinds of check exercise में सूचना पूर्ण है। दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में Audited Column की बिन्दु (1) एवं (2) में से किसी एक का चयन किया गया	पर सभी सूचनाएँ पूर्णरूप में है। स्वीकृत्यादेश के अधीन सभी आवंटन आदेश संलग्न है। स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है। स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समेकित राशि T.V. No.& date के साथ है Kinds of check exercise में सूचना पूर्ण है। दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में Audited Column की बिन्दु (1) एवं (2) में से किसी एक का चयन किया गया

yxkrkj-....

13	समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्र				
	की राशि का Abstract से				
	मिलान किया गया है।				
		डी०डी०ओ०	राज्यादेश / स्वीकृत्य	महालेखाकार	
		का नाम,	ादेश निर्गत करने	कार्यालय का	
		हस्ताक्षर, तिथि	वाले पदाधिकारी	पदाधिकारी का नाम,	
		तथा मुहर	अथवा नामित	हस्ताक्षर, तिथि तथा	
			पदाधिकारी का	मुहर	
			नाम, हस्ताक्षर,		
			तिथि तथा मुहर		
	उपर्युक्त बिन्दुओं को जाँचनेवाले				
	विभाग के आन्तरिक वित्तीय				
	सलाहकार का प्रमाण-पत्र				

टिप्पणी:— इस प्रतिवेदन को दो प्रतियों में संलग्न कर महालेखाकार ¼ले0 एवं हक0½ में समर्पित किया जाना है तथा महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि प्राप्ति के साथ ही इस मामले का आई०डी० नं0/इन्डेक्स नं0 अनिवार्य रूप से दोनों प्रति पर अंकित कर इसे संबंधित अनुभाग में अग्रसारित करेंगे।

khnygi dk asud istnoau

fcgkj ljdkj vkink izáku foHkkx jkT; en'khrygj dsindkni lscpko lnzákh n¶ud infronu

fnukad&

Ø0 I 0	ftyk dk uke	i frofnr frfFk ds i noZ frfFk dks vyko tyk; s x; s LFkkuka dh I a[; k	ifrofn r frffk ds i voz frffk dks tyk; s x; s ydMh dh ek=k Vfd0xk0 ev/c	vc rd tyk; s x; s ydM# dh ek=k %fd0xk0 e#£	'khrygj dsizdki Is i#kkfor tula[;k ½yk[k e#z	eindka dh Ta[; k	foHkkx }kjk ∨kođV rjkf'k ½yk[k enk	v ru 0;; dh x;h jkf'k jkfk en/	jSu clojk ch la[;k	jsu clejk esa vkJ; ysus okyksa dh la[;k	forfjr dEcyka dh la[; k	vH; (Dr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

vfXudkM lis lacf/kn infranu

fcgkj ljdkj vkink izaku folkkx vfXudkM lslacf/kr ifronu

fnukad 1%&

Ø0	ftyk		Da	ily		Comulativ			ve				
	dk uke	eirdk a d	l db	a[; k	tys	e`rc	eirdka dh		tys	tys	I koltfud	ftyks dks	∨fXu
					edkuk s	Ia[;k		edkuk	edkuk a	l Ei fÙk dh	∨ko f Vr	fi fMr	
		o; Ld	сРр	i 'ka	dh		cPpk	i'kq	dh	dk	glp2 {kfr	j kf' k	k a dks
		0 / 20.	k		I a[; k				I a[; k	∨uækfu			mi yl/
					ι υ <u>,</u> κ				I UL / K	re⊮;			k
													djkbl
													xbl
													jkgr
													l kexh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

nfud ck<+ i fromu

ii = & I

vkink icaku foHkkx ½nfud ck<+ifronu½

ftyk dk uke %&

fnukad

1	i#kkfor iz[k#Mkg dk uke	13	निष्क्रमित आबादी की संख्या	
2	प्रभावित पंचायतों की संख्या	14	साहाय्य कैम्प की संख्या	
	पूर्ण		कैम्प में विस्थापितों की संख्या	
	आंशिक	15	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	
3	प्रभावित गाँवों की संख्या		इलाज कराये गये व्यक्तियों की संख्या	
4	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)		वितरित हैलोजेन टेबलेट की संख्या	
	मनुष्य		छिड़के गये ब्लिचिंग पाउडर की मात्रा	
	पशु	16	साहाय्य केन्द्रों में गाड़े गये चापाकल की संख्या	

yxknkj.....

5	iHkkfor {ks=Qy ¼yk[k gĐVs;j en½			उँचे किये गये चापाकल की संख्या		
	कृषि योग्य			मरम्मति किये गये चापाकल की संख्या		
	गैर—कृषि योग्य		17	निर्मित अस्थाई शौचालयों की संख्या		
	कुल योग		18	पशु केन्द्र की संख्या		
6	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रफल (लाख हेक्ट0 में)			उपचार किये गये पशु की संख्या		
7	क्षतिग्रस्त पफसलों का अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)		19	forfjr [kk kUu	परिवार	मात्रा

yxknkj.....

8	क्षतिग्रस्त	ा मकानों की संख्या			गेहूँ	
		पूर्ण			चावल	
	कच्या	आंशिक		20	वितरित नगद अनुदान (रू० लाख में)	
	पक्का	पूर्ण		21	वितरित तैयार भोजन का व्यौरा	
		आंशिक			चना	
	झोपड़ी				चूड़ा	
9	क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)				गुड़	
	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)				सत्तु	
10	eindkadh la[; k			22	दिया सलाई की संख्या मोमबत्ती की संख्या	
	मनुष्य	मनुष्य		23	किरासन तेल (लीटर में)	
	पशु	पशु		24	वितरित पोलीथीन शीट्स की संख्या	

yxkr	yxknkj										
11	कितने गाँव पानी से घिरे हैं		25	तटबंध (Breach Location)							
12	चलाये गये नाव की संख्या		26	अन्य सूचनाएँ							
	मोटरवोट				•						
	सरकारी नाव										
	निजी नाव			ftyk inkf/kdkjh							

FLOOD REPORT

Disaster Management Department, Government of Bihar

Cumulative Form IX

No. of affected Districts -

FLOOD REPORT

				No. of affected									
No	Name of	No. of	Pa	nchaya	ats	Village	Persons	Animais	Affected area (In lac hac)		ac hac)	Estd crop dam	
-	District	Blocks	Fully	Partly	Total		In lac	ac in lac Agri Non- Ag Total	Total	Cropped	age (Rs lac)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Houses damaged										
Pucca		Kucha								
Fully	Partly	Fully Partly		Huts	Total	Value Rs Iac				
15	16	17	18	19	20	21				



Public property damaged (Rs lac)	Lives	slost	Population evacuated		on kept in liter liative)	No. of villages surrounded	Population on roads/rail tracks/	
	Human	Animai		Relief camps	Population	with water	roof tops etc.	
22	23	24	27	25	26	28	29	

	Boa	ts		Centr	'e	Stoc	x position upto (in Mt)	
Motor	Govt	Pvt	Total	Health	Vet	Wheat	Rice	
30	31	32	33	34	35	36	37	



	GI	R Distrib	ution (in Qis)	Ready food (in qis)						
Wheat	Rice	Total	GR Distribution Cash (in Lakh)	Cash component (in Lakh)	Chana	Salt	Chura	ıra Sattu (· Khichri
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Fodder	Matches	Candles	K Oil			
in qtl	no	no.	litres	Polythene	Food Packet	Packets Dropped by Air
49	50	51	52	53	54	55

whinh do elatj vuong vuonku dh vf/k; kpuk gog i i = A

 $i \, k d fr d@x \ \ i \, k d fr d@LFkkuh; \ \ i \, k d fr \ \ d h \ \ \lor k i \, n k \ \ d s \, e \, i \, k utj \ \ \lor u \rho k u \ \ d h \ \ \lor f/k; \, k \rho u k \ \ g r q \, i \, i = A$

Ī	Ø0	eird dk	eird dh	erd	erd ds	eR; q dk	eïR; q	eR; q dh	×§	vf/k; kfpr	vII; (Dr
		uke, oa	∨k; q	dk	vkfJr dk	dkj.k	dk	frfFk	i kdfrd@LFkkuh	j kf' k	
		irk		fyax	uke , oa	, oa i <i>i</i> dkj	LFkku		; i⊅dfr ∨kink		
					l aca/k				dh fLFkfr e s		
									, dy@l eng ds		
									i Hkkfor gksus dh		
									fLFkfr		
ŀ											

ftyk inkf/kdkjh

/kU; okn



